रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D(D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 1981/भाद्र 28, 1903

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1981/BHADRA 28 190

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कंम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1981

का०आ० 2427.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री देवी सरन चोपड़ा, एडवोकेट, टू रोजीज, पाली रोड, बान्द्रा, मुम्बई-400050 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे महाराष्ट्र राज्य के बान्द्रा, बम्बई में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति का नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[संख्या 5(40)/81-न्या०]

के०सी०डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTICE

New Delhi, the 7th August, 1981

S.O. 2427.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Devi Saran Chopra, Advocate Two Roses, Pali Road, Bandra, Bombay-400050 for appointment as a Notary to practise in State of Maharashtra at Bandra, Bombay.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(40)/81-Judl.]

K. C. D. GANGWANI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1981

का०आ० 2428.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रण-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में

(1) उपनियम (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(13क) ऐसा कोई सैनिक पेंशन भोगी, जो सैनिक सेवा से निवृत्ति पर, निवृत्ति पेंशन, सेवा पेंशन या आशक्त पेंशन पर सामान्य कुटुम्ब पेंशन मंजूर किए जाने के लिए सेना अनुदेश

2/एस/64 द्वारा या तत्संबंधी नौसेना या वायुसेना अनुदेशों द्वारा शासित होता है और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के पूर्व किसी सिविल सेवा या सिविल पद में पुनर्नियोजित हो जाता है, वह इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन या पूर्वोक्त सेना/नौसेना/वायुसेना अनुदेश के अधीन पहले से प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन की पात्रता के प्रयोजन के लिए निम्नानुसार शासित होगा :--

(i) यदि वह पुनर्नियोजन के अनुक्रम में किसी अस्थायी हैसियत में सिविल पद धारण करते हुए मर जाता है तो उसके कुटुम्ब को इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन या इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन या सैनिक सेवा से उनकी निवृत्ति या उन्मुक्ति के समय सेना अनुदेश 2/एस/64 या तत्संबंधी नौसेना या वायुसेना अनुदेश के अधीन प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन के लिए विकल्प बताने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा,

(ii) यदि वह किसी सिविल सेवा या सिविल पद से किसी अधिष्ठायी हैसियत में स्थायी पद धारण किए बिना निवृत्त हो जाता है तो उसका कुटुम्ब, सेवा निवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु की दशा में, सेना अनुदेश 2/एस/64, या तत्संबंधी नौसेना या वायुसेना अनुदेश के अधीन प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होगा,

(iii) यदि अपने पुनः नियोजन के अनुक्रम में किसी सिविल सेवा में या सिविल पद पर पुष्टि पर उसने इन नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार पूर्व सैनिक सेवा के लिए सेना पेंशन प्रतिधारित करने का विकल्प प्रकट किया है तो वह इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन या सेना अनुदेश 2/एस/64 अथवा तत्संबंधी नौसेना या वायुसेना अनुदेश के अधीन पहले से प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए एक अन्य विकल्प का प्रयोग करेगा। विकल्प का प्रयोग सिविल सेवा या सिविल पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति का आदेश जारी होने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर अथवा यदि वह उस दिन छुट्टी पर है तो उसके छुट्टी से वापस आने की तारीख के तीन मास के भीतर इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जाएगा। यदि पूर्वोक्त अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि पेंशन भोगी ने सेना अनुदेश 2/एस/64 या तत्संबंधी नौसेना या वायुसेना अनुदेश के अधीन प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन के लिए विकल्प का प्रयोग किया है।

(iv) यदि पुनः नियोजन के उपक्रम में सिविल सेवा में या सिविल पद पर पुष्टि हो जाने पर उसने इन नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसार सेना पेंशन के अभ्यर्पित करने और उसके बदले में सिविल पेंशन के लिए सैनिक सेवा की गणना किए जाने का विकल्प प्रकट किया है तो वह इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन द्वारा शासित होगा;

(2) उप नियम (15) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(ख) ऐसा सैनिक पेंशनभोगी जो पहली जनवरी, 1964 को या उसके पश्चात् सैनिक सेवा से निवृत्त हो गया है और जिसने सिविल सेवा में या सिविल पद पर पुनर्नियोजन की तारीख को वह अधिवर्षिता की आयु जो इस पद को लागू है। जिसमें उसे पुनर्नियोजित किया गया है, प्राप्त कर ली थी;

(3) उप नियम (16) का लोप किया जाएगा।

[सं० 1(13) पेंशन(ए)/80]
एस० पी० मदान, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 18th February, 1981

S.O. 2428.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:—

(2) They shall come into force on the date of their pubvices (Pension) (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 :—

(1) after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(13A) A military pensioner, who on retirement from military service, on retiring pension, service pension or invalid pension is governed for the grant of ordinary family pension by Army Instruction 2|S|64 or corresponding Navy or Air Force Instructions and is re-employed in a civil service or civil post before attaining the age of superannuation, shall for the purpose of eligibility for the family pension admissible under this rule or the family pension already authorised under the aforesaid Army|Navy||Air Force Instruction, be governed as follows :—

(i) if he dies while holding a civil post in a temporary capacity in the course of re-employment, his family may be allowed to opt for the family pension admissible under this rule or the family pension authorised at the time of his retirement or discharge from the military service under Army Instruction 2|S|64 or the corresponding Navy or Air Force Instruction.

(ii) if he retires from civil service of civil post without holding a permanent post in a substantive capacity, his family in the event of his death after retirement shall be eligible for family pension authorised under Army Instruction 2|S|64 or corresponding Navy or Air Force Instruction.

(iii) if on confirmation in a civil service or a civil post in the course of his reemployment, he has opted to retain military pension for the past military service in terms of clause (a) of sub-rule (1) or rule 19 of these rules, he shall exercise another option to receive family pension admissible under this rule or the family pension already authorised under Army Instruction No. 2|S|64 or the corresponding Navy or Air Force Instruction. The option shall be exercised within a period of three months of the date of the issue of orders of substantive appointment to a civil service or civil post or if he is on leave on that day, within three months of his return from leave, whichever is later. If no option is exercised within the period aforesaid, the pensioner shall be deemed to have opted for family pension authorised under Army Instruction No. 2|S|64 or the corresponding Navy or Air Force Instruction, and

(iv) if on confirmation in a civil service or civil post in the course of re-employment he, in terms of clause (b) of sub-rule (1) of rule 19 of these rules, has opted to surrender military pension and count in lieu thereof military service for civil pension, he shall be governed by family pension admissible under this rule.";

(2) for clause (b) of sub-rule (15), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) a military pensioner who retired from military service on or after tht 1st January, 1964 and who on the date of re-employment in a civil service or civil post had attained the age of superannuation applicable to the post in which he is re-employed";

(3) sub-rule (16) shall be omitted.

[No. 1(13)Pen(A)|80]

S. P. MADAN, Director

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1980

अधिसूचना

आय-कर

का०आ० 2429.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना सं० 604 (फा०सं० 203/26/74-आई टी ए II), तारीख 30 अप्रैल, 1974 द्वारा भारतीय पोषण सोसाइटी, हैदराबाद को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i)(ii) के अधीन दिया गया अनुमोदन, विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर तारीख 1-4-80 से वापस ले लिया गया है।

[सं० 3770/फा०सं० 203/230/80-आई टी ए II]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th December, 1980

INCOME-TAX

S.O. 2429.—It is hereby notified for general information that the approval given under Section 35 (1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to Nutrition Society of India, Hyderabad, vide Notification No. 604 (F.No. 203|26|74-ITA.II) dated the 30th April, 1974, is withdrawn with effect from 1-4-1980 on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[No. 3770|F. No. 203|280|80-ITA.II)]

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1981

का०आ० 2430.—अधिसूचना सं० 3471 (फा०सं० 203/99/75-आई०टी०ए० II), तारीख 15 जून, 1980 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी भारतीय कृषि अर्थशास्त्र परिषद्, द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

इण्डियन सोसायटी आफ एग्रिकल्चरल एकोनोमिक्स, बाम्बे। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1982 की तीन वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 3944/फा०सं० 203/204/80-आई टी ए (II)]

New Delhi, the 30th April, 1981

S.O. 2430.—In continuation of Notification No. 3471 (F. No. 203|99|75-ITA(II) dated 15th June, 1980, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (i) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Indian Society of Agricultural Economics, Bombay

The notification is effective for a further period of 3 years from 1st April, 1979 to 31st March, 1982.

[No. 3944|F. No. 203|204|80-ITA(II)]

नई दिल्ली, 12 मई, 1981

आय-कर

का०आ० 2431.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :

(i) भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान, हैदराबाद द्वारा इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का उपयोग अनन्यतः समाज विज्ञान के अनुसंधान की उन्नति के लिए ही किया जाएगा।

(ii) भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान, इस छूट के अधीन संग्रह की गई निधियों का पृथक लेखा रखेगा, और

(3) यह कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान छूट के अधीन संगृहीत की गई निधियों का और वह रीति जिसमें उनका उपयोग किया गया है दर्शित करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का विवरण भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् और साथ ही साथ सम्बद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान, हैदराबाद।

यह अधिसूचना 1-12-1980 से 30-11-1983 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 3930/फा०सं० 203/252/80-आई टी ए II]

New Delhi, the 12th May, 1981

INCOME TAX

S.O. 2431.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :

(i) The funds collected by the Indian Institute of Economics, Hyderabad under this exemption shall be utilised, exclusively for promotion of research of Social Science.

(ii) That the Indian Institute of Economics, shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption, and accounts of the funds collected by them under the exemption, and

(iii) That the Indian Institute of Economics shall send an annual report and Statement of accounts regularly to the Indian Council of Social Science Research as well as to the concerned Commissioner of Income-tax showing the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilised.

INSTITUTION

The Indian Institute of Economics, Hyderabad.

This notfication is effective for a period of three years from 1-12-1980 to 30-11-1983.

[No. 3930|F. No. 203|252|80-ITA.II]

नई दिल्ली, 3 जून, 1981

का० आ० 2432.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात:—

(i) यह कि प्रतिष्ठान चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाए और उसे सूचित किए जाए।

(iii) यह कि उक्त प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

लोकमान्य चिकित्सा प्रतिष्ठान (अनुसंधान केन्द्र) पुणे

यह अधिसूचना 21-2-81 से 20-2-83 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4005/फा०सं० 203/51/81-आई टी ए II]

New Delhi, the 3rd June, 1981

S.O. 2432.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 (ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific research association" in the field of Medical Research subject to the following conditions —

(i) That the Foundation will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Foundation will furnish an annual audited statement of accounts to the Council by 31st May each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Lokmanya Medical Foundation Researrh Centre, Pune.

The notification is effective for a period of 2 years from 21-2-1981 to 20-2-1983.

[No. 4005|F. No. 203|51|81-ITA.II]

का०आ० 2433.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "विश्वविद्यालय" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(i) यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

(iii) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरण और लेखाओं का वार्षिक विवरण आय-कर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

यह अधिसूचना 6-1-1981 से 5-1-1984 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4006/फा०सं० 203/4/81-आई टी ए II]

S.O. 2433.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rules 6(vi) of the Income-tax Rules, 1962 under the category "University" in the areas of other natural and applied science, subject to the following conditions :—

(i) That the University of Gorakhpur, Gorakhpur, will maintain a separate account of sum received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than agriculture/animal husbandry/fisheries and medicines ;

(ii) That the said University will furnish Annual Return of its scientific research activities to the Presscribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.

(iii) That the said University will submit the Annual Return and Statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax, for every year.

INSTITUTION

University of Gorakhpur, Gorakhpur

This notification is effective for a period of 3 years from 6-1-1981 to 5-1-1984.

[No. 4006|F. No. 203|4|81-ITA.II]

का०आ० 2434—सर्वसाधारणकी जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(vi) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्रों में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(i) यह कि संगीत महाभारती, मुम्बई (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में) वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेष रूप से इस अनुमोदन की बाबत प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगी।

(ii) अनुमोदन के तीन वर्षों के दौरान लगभग 6 लाख रुपए (छह लाख रुपए) की राशियां संगृहीत करेगी और उसे विभाग को प्रस्तुत की गई पांच परियोजनाओं के अर्थात् :—

(1) जवारी-प्रसंस्करण तकनीक, (2) तबला : स्याही लगाने की तकनीक और उल्टी तरफ लगाने की तकनीक (3) वाद्य-यंत्रों के लिए संशोधन प्रक्रिया (4) वाद्य यंत्रों को सुखाने के लिए पद्धति तैयार करना और (5) इलैक्ट्रानिक्स मात्रामापी, के क्रियान्वयन के लिए उपस्कर और सहयुक्त कर्मचारीवृन्द के वेतन पर खर्च करेगी। संगृहीत की रकम भवन निर्माण पर खर्च नहीं की जाएगी।

(iii) यह कि उक्त महाभारतीय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iv) यह कि उक्त महाभारतीय प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी और लेखाओं का विवरण आय-कर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

संगीत, महाभारती, मुम्बई

यह अधिसूचना 8-3-1981 से 7-3-1984 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4007(फा०सं० 203/69/79-आई टी ए II]

S.O. 2434.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 (vi) of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the areas of other natural and applied science, subject to the following conditions:—

(i) That the Sangit Mahabharati, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than agriculture|animal husbandry/fisheries and medicines and specially in regard to this approval:

(ii) Collect sums approximately Rs. 6 lakhs (Rupees six lakhs) during the three years of approval and will spend the same on equipment and associated staff salaries for carrying out five projects submitted to the Department viz. : (1) Jawari-Processing Technique, (2) Tabla : Syahi application technique & reverse application technique (3) Seasoning process for Instruments (4) Evdoing method for Dehydrating of music instruments and (5) Electronics Metronome. The sums collected will not be spent on construction of building :

(iii) That the said Mahabharati will furnish Annual Return of its scientific research activities to the rescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.

(iv) That the said Mahabharati will submit the annual return and Statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax for every year.

INSTITUTION

Sangit Mahabharati, Bombay.

The notification is effective for a period of 3 years from 8-3-1981 to 7-3-1984.

[No. 4007|F. No. 203|69|79-ITA.II]

नई दिल्ली, 9 जून, 1981

का०आ० 2435.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(vi) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "महाविद्यालय" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि श्रीमती पार्वती बाई चौगुले सांस्कृतिक प्रतिष्ठान का कला और विज्ञान महाविद्यालय, मार्गाओ (गोवा) प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त महाविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

(iii) यह कि उक्त महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी और लेखाओं का विवरण आय-कर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

श्रीमती पार्वती बाई चौगुले सांस्कृतिक प्रतिष्ठान का कला और विज्ञान महाविद्यालय, मार्गाओ (गोवा)

यह अधिसूचना 10-5-81 से 9-5-1984 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4019/फा०सं० 203/263/80-आई टी ए-II]

New Delhi, the 9th June, 1981

S.O. 2435.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, he prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961; read with Rule 6(vi) of the Income-tax Rules, 1962 under the categoryy 'Collegc' in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions :—

1. That the Smt. Parvatibai Chowgule Cultural Foundations's College of Arts & Science Margao (Goa), will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agricultural animal husbandary/fisherics and medicines.

2. That the said College will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.

3. That the said College will submit the annual return and statement of accounts to the Commissioner of Income-tax, every year.

INSTITUTION

Smt. Parvatibai Chowgule Cultural Foundationsn's College of Arts & Scienee Margao (Goa)

This notification is effective for a period of three years from 10-5-81 to 9-5-1984.

[No. 4019|F. No. 203|263|80-ITA.II]

नई दिल्ली, 10 जून, 1981

का० आ० 2436.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम,

1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में 'संगम' प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि फाई अनुसन्धान संस्थान, इचलकरंजी प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषध से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

2. उक्त संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

3. उक्त संस्थान प्रत्येक वर्ष वार्षिक विवरणी और लेखाओं का विवरण आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

फाई अनुसन्धान संस्थान, इचलकरंजी

यह अधिसूचना 28-5-1981 से 27-5-1982 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 4021/फा० सं० 203/29/80—आ ई टी ए-II]

New Delhi, the 10th June, 1981

S.O. 2436.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 (vi) of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'Association' in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions :—

1. That the Fie Research Institute, Ichalkaranji will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agricultural/animal husbandry/fisheries and medicines).

2. That the said Institute will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescirbed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them or this purpose, by 30th April. each year.

3. That the said Institute will submit the annual return and statement of accounts to the Commissioner of Income-tax every year.

INSTITUTION

Fie Research Institute, Ichalkaranji

This notification is effective for a period of one year from 28-5-81 to 27-5-82.

[No. 4021/F. No. 203/29/80-ITA.II]

नई दिल्ली, 12 जून, 1981

का० आ० 2437 :—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2226 (फा० सं० 203/49/77-आई टी ए-II) तारीख 23-3-1978 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने नीचे उल्लिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

(i) कि ज्ञान प्रबोधिनी द्वारा इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का उपयोग अनन्यतः समाज विज्ञान में अनुसंधान के प्रवर्धन के लिए किया जाएगा ।

(ii) कि ज्ञान प्रबोधिनी इस छूट के अधीन उनके द्वारा संगृहीत निधियों का पृथक लेखा रखेगी ।

(iii) कि ज्ञान प्रबोधिनी इस छूट के अधीन उनके द्वारा संगृहीत निधियों और वह रीति जिससे निधियों का उपयोग किया गया था, दर्शाते हुए परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाविवरण नियमित रूप से भेजेगी ।

संस्था

ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे

यह अधिसूचना 1-1-1981 से 31-12-1983 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4024/फा० सं० 203/261/80—आई टी ए-II]

New Delhi, the 12th June, 1981

S.O. 2437.—In continuation of this Office Notification No. 2226 (F. No. 203/49/77-II) dated 23-3-1978 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions:—

(i) The funds collected by the Jnana Probodhini under this exemption will be utilized, exclusively for promotion of research in Social Science.

(ii) That the Jnana Prabodhini shall maintain separate accounts of the funds collected by them under this exemption.

(iii) That the Jnana Jrabodhini shall send to the Council annual report and audited statements of accounts regularly showing the Funds collected by them under this exemption and the manner in which the funds were utilized.

INSTITUTION

Jnana Prabodhini, Pune

This notification is effective for a period of three years from 1-1-1981 to 31-12-1983.

[No. 402/F. No. 203/261/80-ITA.II]

नई दिल्ली, 15 जून, 1981

का० आ० 2438 :—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 2955 (फा० सं० 203/41/79—आई टी ए II), तारीख 2-8-79 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक और अनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि बकुल फाइन केम रिसर्च सेंटर, मुम्बई प्राकृतिक या अनुप्रयोगिक (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों की पृथक लेखा रखेगा ।

(2) यह कि उक्त सेंटर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(3) यह कि उक्त सेंटर प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरण और लेखाओं का विवरण आय-कर आयुक्त, मुम्बई को भेजेगा ।

संस्था

बकुल फाइन-केम रिसर्च सेंटर, मुम्बई

यह अधिसूचना 1-4-1981 से 31-3-1984 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4025/फा० सं० 203/43/81-आई टी ए II]

New Delhi, the 15th June, 1981

S.O. 2438.—In continuation of this Office Notification No. 2955 (F. No. 203/41/79-ITA.II) dated 2-8-79, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the I.T. Act, 1961, read with Rule 6 (iv) of Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the areas of other natural and applied science, subject to the following conditions :—

1. That the Bakul Finechem Research Centre, Bombay will maintain a separate account of sums received by it for scientific research in the field of natural and appliled sciences other than agriculture|animal husbandry|fisheries and medicines.

2. That the said Centre will furnish annual return of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimate to them for this purpose by 30th April each year.

3. That the said Centre will submit the annual return and statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax, Bombay for every year.

INSTITUTION

Bakul Finechem Research Centre, Bombay

The notification is effective for a period of three years from 1-4-1981 to 31-3-1984.

[No. 4025|F. No. 203|43|81-ITA.II]

नई दिल्ली, 25 जून, 1981

का० आ० 2439:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने नीचे उल्लिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए आयुर्विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

(1) यह कि संगम आयुर्विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(2) यह कि संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(3) यह कि संगम लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

(4) यह कि संगम डा० स्पेंसर्स हार्ट फाउन्डेशन, न्यूयार्क से दान दिए जाने वाले उपस्कर को आयात करने के पूर्व भारत सरकार से निकासी प्राप्त करेगा ।

संस्था

एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली ।

यह अधिसूचना 19-6-1981 से 18-6-1983 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4047/फा० सं० 203/103/81-आई टी ए-II]

एम० के० पाण्डेय, उप सचिव

New Delhi, the 25th June, 1981

S.O. 2439.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-Section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 (ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of Medical Research.

(ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish an annual audited statement of accounts to the council by 31st May each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

(iv) That the Association will seek Govt. of India's clearance before importing equipment to be gifted from Dr. Spancer's Heart Foundation, New York.

INSTITUTION

Escorts Heart Institute and Research Centre, New Delhi.

This notification is effective for a period of two years from 19-6-1981 to 18-6-1983.

[No. 4047|F. No. 203|103|81-ITA.II]
M. K. PANDEY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 1981

का० आ० 2440:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "अरुलमिगु स्थल शयन पेरुमल मन्दिर, माम्लापुरम्" को, तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 4010/फा० सं० 176/36/81 आ. क (ए० 1)]
के. के. पाण्डे, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 1981

S.O. 2440.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Sthala Sayana Perumal Temple, Mamallapuram" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 4010/F. No. 176/36/81-IT(AI)]
K. K. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1981

का० आ० 2441:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री द्वारकाधीश जी मन्दिर, बेट (गुजरात)" को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण गुजरात राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० 4071/फा० सं० 176/45/80-आई टी (ए-I)]

New Delhi, the 3rd July, 1981

S.O. 2441.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Dwarkadishji Mandir, Bet (Gujarat)" to be a place of public worship of renown throughout the State of Gujarat for the purposes of the said section.

[No. 4071|F. No. 176|45|80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1981

का० आ० 2442:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री महासती सावित्री मंदिर प्रबंध समिति" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4155/फा० सं० 197/125/78 आ० क. (ए I)]

New Delhi, the 11th August, 1981

S.O. 2442.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Centrl Government hereby notifies "Shri Mahasati Savitri Mandir Managing Committee" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1981-82.

[No. 4155|F. No. 197|125|78-IT(AI)]

का० आ० 2443:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "गुरु नानक प्रतिष्ठान" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4156/फा० सं० 197/200/79 आ० क (ए I)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

S.O. 2443.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Guru Nanak Foundation" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1979-80 to 1983-84.

[No. 4156|F. No. 197|200|79-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1981

का० आ० 2444:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री राम वैकुंठ मंदिर न्यास, पुष्कर" को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4131/फा० सं० 197/244/80 आ० क (ए I)]

New Delhi, the 24th July, 1981

S.O. 2444.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Rama Vaikunoh Temple Trust, Pushkar" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4131|F. No. 197|244|80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1981

का० आ० 2445:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, "श्री पार्वती शंकर महागणपति परिषद" को निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है

[सं० 4142/फा० सं० 197/230/80 आ० क (ए I)]

New Delhi, the 29th July, 1981

S.O. 2445.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Parvathy Sankara Mahaganapathi Parishad" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year(s) 1980-81 and 1981-82.

[No. 4142|F. No. 197|230|80-IT(AI)]

शुद्धि-पत्र

का० आ० 2446:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 4011, तारीख 6 जून, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है :—"श्री पद्मनाभास्वामी मंदिर, त्रिवेन्द्रम" शब्दों के स्थान पर "श्री पद्मनाभास्वामी मंदिर न्यास, त्रिवेन्द्रम" शब्द पढ़े ।

[सं० 4143/फा० सं० 197/38/78-आ० क (ए I)]

CORRIGENDUM

S.O. 2446.—In exercise of the powers conferred by Section 10(23C)(v) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby amend its notification No. 4011 dated the 6th June, 1981 as below:—

For the words "Sree Padmanabaswamy Temple, Trivandrum"

Read "Sri Padmanabhaswamy Temple Trust, Trivandrum".

[No. 4143|F. No. 197|38|78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1981

का० आ० 2447:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री परम आनंद, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ, अहमदाबाद" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4150/फा० सं० 197/134/79 आ क (ए I)]

वी० बी० श्रीनिवासन, उप-सचिव

New Delhi, the 4th August, 1981

S.O. 2447.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Param Anand Swetamber Murtipujak Jain Sangh, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1981-82.

[No. 4150|F. No. 197|134|79-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली 19 सितम्बर, 1981

का०आ० 2448:—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 75-सीमा-शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने, स्तम्भ 3 में, मद (ख) में, उपमद (xx) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(xxi) समुद्री, डेरी और पोलट्री उत्पाद ।"

स्पष्टीकरण टिप्पण:—यह अधिसूचना अहमदाबाद विमानपत्तन से जो सीमा-शुल्क विमान पत्तन घोषित कर दिया गया है, समुद्री, डेरी और पोलट्री उत्पाद के निर्यात की अनुज्ञा प्रदान करती है ।

[सं० 204/81-सीमा शुल्क फा०सं० 481/6/81/सी०शु०VII]

एन के. कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 1981

S.O. 2448.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75-Customs, dated the 3rd July, 1975, namely:—

In the Table annexed to the said notification, against Serial No. 1, in column 3 in item (b), after sub-item (xx) the following sub-item shall be inserted, namely:—

"(xxi) marine, dairy and poultry products."

Explanatory Note:—This notification permits exports of marine, dairy and poultry products from Ahmedabad Airport which has been declared as Customs airport.

[No. 204/81-CUSTOMS/F. No. 481/6/81-CUSVII]
N. K. KAPUR, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1981

का० आ० 2449:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 18-6-1979 की अधिसूचना सं० 2876 का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० एस० सक्सेना को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एस० एस० सक्सेना के कर वसूली अधिकारी का पद भार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं 4157/फा० सं० 398/2/81-आ० क० स० क०]

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 13th August, 1981

S.O. 2449.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2876 [F. No. 404/127 (TRO-Agra)-ITCC] dated 18th June, 1979, the Central Government hereby authorises Shri S. S. Saxena being a gazetted officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. S. Saxena takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4157 (F. No. 398/2/81-ITCC)]

का० आ० 2450:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम० एल० केराल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री एम० एल० केराल के कर वसूली अधिकारी का पद-भार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4159/फा० सं० 398/2/81-आ० क०म० क०]
एच० वेंकटरामन्, निदेशक

S.O. 2450.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri M. L. Keral, being a gazetted officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri M. L. Keral takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4159/F. No. 398/2/81-ITCC]
H. VENKATARAMAN, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1981

बीमा प्रभाग

का० आ० 2451:—जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष श्री अशोक गोयनका को उस अवधि तक के लिए जब तक वे भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष रहते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के निदेशक मण्डल का सदस्य नियुक्त करती है।

[एफ० सं० 124(4) बीमा-4/80]
मदन गोपाल गुप्त, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 5th August, 1981

INSURANCE DIVISION

S.O. 2451.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) the Central Government hereby appoints Shri Ashok Goenka, Chairman, General Insurance Corporation of India, as Member of the Board of Life Insurance Corporation of India so long as he holds the post of Chairman of G.I.C.

[F. No. 124(4)Ins. IV/80]
M. G. GUPTA, Director

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1981

का० आ० 2452:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबन्ध 31 अगस्त, 1981 तक विजया बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इन के अधीन निर्धारित रूप में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखे तथा तुलन पत्र का प्रकाशन और 30 जून, 1981 तक की बढ़ाई गई अवधि के भीतर रिटर्नों के रूप में इनकी तीन प्रतियां रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना, आवश्यक है।

[संख्या 2/25/81-एकाउंट्स]
अहमद फरीद, अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 29th August, 1981

S.O. 2452.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the said Act shall not apply to the Vijaya Bank upto 31st August, 1981, insofar as it is required to publish the accounts and balance sheet together with the Auditor's report in the prescribed manner and submit three copies thereof as returns to the Reserve Bank within the extended period upto 30th June, 1981.

[No. 2/25/81-ACCTTS.]
AHMED FAREED, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1981

का० आ० 2453:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्द्वारा घोषणा करती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 30 जून, 1982 तक बड़ी दोआब बैंक लिमिटेड, होशियारपुर (पंजाब) पर उस समय तक लागू नहीं होंगे जहां तक इनका सम्बन्ध पंजाब के होशियारपुर जिले के प्रेमगढ़ तथा फिरोजपुर जिले के कोटवाल गांव में इसके द्वारा भू-सम्पत्ति की धारिता से है।

[संख्या 15(5)/81-बी० ओ०-III]
एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd September, 1981

S.O. 2453.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply upto 30th June, 1982 to the Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur (Punjab) in respect of the landed properties held by it at Premgarh, Hoshiarpur District and at Village Kotwal, Ferozepur District, Punjab.

[No. 15(5)/81-B.O.III]
N. D. BATRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)
New Delhi, The 27th August, 1981

का०आ० 2454.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जून 1981 के दिनांक 26 जून को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा
S.O. 2454—**An Accoont pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 26th day of June 1981**

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	22,30,45,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Buillion		
संचलन में नोट Notes in circulation	14435.94.75.000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	225,58,28,000	
जारी किए गए कुल नोट Total Notes issued		14458,25,20 000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India		
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	2364,05,75,000	
			जोड़ Total		2589,64,03,000
			रुपए का सिक्का Rupees Coin		48,69,85,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		11819,91,32,000
			देशी विनियम बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		
कुल देयताएं Total Liabilities		14458,25,20,000	कुल आस्तियां Total Assets		14458,25,20,000

दिनांक 19

गवर्नर
Governor
I.G. PATEL,

New Delhi the 1st day of July, 1981

26 जून, 1981 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India Banking Department as on 26th June 1981

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	22,30,45,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपए का सिक्का Rupee Coin	3,76,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long term Operations) Fund	920,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	6,69,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	290,00,00,000	खरीदे और भुनाए गये बिल Bills Purchased and Discounted :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	1355,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	2,83,80,000
जमाराशियां :— Deposits :—		(ख) विदेशी (b) External	..
(क) सरकारी (a) Government		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	2823,00,88,000
		विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad*	1567,76,15,000
		निवेश Investment**	2030,18,94,000

(i) केन्द्रीय सरकार	
(i) Central Government	65,07,54,000
(ii) राज्य सरकारें	
(ii) State Governments	5,53,08,000
(ख) बैंक	
(b) Banks	
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
(i) Scheduled Commercial Banks	4516,81,98,000
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	52,19,62,000
(3) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	3,40,85, 000
(4) अन्य बैंक	
(iv) Other Banks	5,87,17,000
(ग) अन्य	
(c) Others	1395,14,33,000
देय बिल	
Bills Payable	81,25,87,000
अन्य देयताएं	
Other Liabilities	2685,56,20,000
रुपये	
Rupees	11530,86,64,000

ऋण और अग्रिम:—	
Loans and Advances to :—	
(1) केन्द्रीय सरकार को	
(i) Central Government	
(2) राज्य सरकारों को	
(ii) State Governments@	915,90,22,000
ऋण और अग्रिम :—	
Loans and Advances to :—	
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	
(i) Scheduled Commercial Banks†	564,26,09,000
(2) राज्य सहकारी बैंकों को	
(ii) State Co-operative Banks††	296,66,62,000
(3) दूसरों को	
(iii) Others	15,83,14,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(क) ऋण और अग्रिम :—	
(a) Loans and Advances to :—	
(1) राज्य सरकारों को	
(i) State Governments	125,74,77,000
(2) राज्य सहकारी बैंकों को	
(ii) State Co-operative Banks	30,65,08,000
(3) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	
(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(4) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	303,44,50,000
(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	5,50,64,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
Loans and Advances to State Co-operative Banks	94,03,45,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
(a) Loans and Advances to the Development Bank	1310,35,28,000
(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश	
(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
अन्य आस्तियां	
Other Assets	1422,26,18,000
रुपये	
Rupees	11530,86,64,000

नकदी, सावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिए गए शून्य रुपए शामिल है।

†Includes Rs. –Nil– advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

[U.O. No. F. 10/1/81-BOI]

C.W. MIRCHANDANI *Dy. Secy.*

आयकर आयुक्त कार्यालय

(विदर्भ, नागपुर)

नागपुर, 31 जुलाई, 1981

का० आ० 2455.—चूंकि केन्द्रीय सरकार की राय में यह आवश्यक और उचित है कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान कर के व्यतिक्रमी (डिफाल्टर) निर्धारितियों जिनके मामलों में एक लाख से अधिक रुपयों को बट्टे खाते में डाला गया है, के नाम और पतों को लोकहित में प्रकाशित किया जाए।

2. और चूंकि आयकर अधिनियम की धारा 287 (1961 का 43) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसी सभी अन्य शक्तियों द्वारा जिनसे इसके लिए समर्थ किया गया है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपने तारीख 26 दिसम्बर, 1970 के आदेश फा० सं० 83/108/69-आयटी (बी) के द्वारा आयकर आयुक्त को प्राधिकृत करती है और निदेश देती है कि ऐसे चूक-कर्ताओं के नाम और पते प्रकाशित किए जाए।

3. अतः मैं, आयकर आयुक्त, विदर्भ, नागपुर एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान कर चूक-कर्ताओं के नाम और पते, जिनके मामले में रुपये एक लाख से अधिक की रकम बट्टे खाते में डाली गई है, प्रकाशित करता हूं।

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम और पता	हैसियत	निर्धारण वर्ष	बट्टे खाते डाली गई रकम	बट्टे खाते में लेने का संक्षिप्त कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मै० खेतान ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज, बनोसा, जि० अमरावती	फार्म	1968-69	76779	राशि वसूली करने के योग्य नहीं है, अतः बट्टे खाते में डाली गई है।
			1969-70	42352	
			1970-71	5065	
			1971-72	3339	
			कुल रुपये	127535	

[फा० सं० वसूली (64)(2)/79-80]

डी० सी० अग्रवाल, आयकर आयुक्त

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, VIDARBHA, NAGPUR)

Nagpur, the 31st July, 1981

S.O. 2455.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and addresses hereinafter specified relating to tax defaulters in whose cases amounts over Rs. 1 lakh were written off during the financial year 1980-81.

2. And whereas in exercise of the powers conferred by Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government by its order F. No. 83/108/69-IT(B) dated the 26th December, 1970 authorised and directed Commissioner of Income-Tax to publish the names and addresses of such tax defaulters.

3. Now therefore, I, Commissioner of Income-tax, Vidarbha, Nagpur hereby publish the names and addresses of the tax defaulters in whose cases amounts over Rs. 1 lakh has been written off during the Financial Year 1980-81.

Sl. No.	Name and Addresses of the assessee.	Status.	Asstt. Year	Amount Written off	Brief reasons for write Off
1	2	3	4	5	6
				Rs.	
1.	M/s. Khetan Trade and Industries Banosa, Distt. Amravati	Firm	1968-69	76779	Amount considered irrecoverable hence written off.
			1969-70	42352	
			1970-71	5065	
			1971-72	3339	
				Total Rs. 127535	

[F. No. Recy (64)/(2)/79-80]

D. C. AGGARWAL, Commissioner of Income tax

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1981

का० आ० 2456.—हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) के खंड 6 के उप खंड (1), (4) और (5) के अनुपालन में 29 अगस्त, 1981 को आयोजित बैठक में श्री मुस्तफा फकीह को हज समिति के अध्यक्ष के रूप में और सर्वश्री सैयद शहाबुद्दीन मोहम्मद और अमीर खंडवानी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, इसके द्वारा अधिसूचित की जाती है।

[सं० एम० (हज) 118-1/15/80]

एम० एच० अन्सारी, प्रधाचार प्रमुख और संयुक्त सचिव (हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st September, 1981

S.O. 2456.—In pursuance of Sub-section (1), (4) and (5) of section 6 of the Haj Committee Act, 1959 (No. 51 of 1959), the selection of Shri Mustafa Fakih as Chairman and S/Shri Syed Shahabuddin and Mohammed Amin Khandwani as Vice-Chairman of the Haj Committee, Bombay, at the meeting of the committee held on 29th August, 1981, is hereby notified.

[No. M(Haj)118-1/15/80]

M. H. ANSARI, Chief of Protocol and Jt. Secy. (Haj)

ई० पी० (एम० पी०) डेस्क

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1981

का० आ० 2457.—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री डी० बाबू पाल, विशेष सचिव (परिवहन, मछली पालन तथा पत्तन, केरल सरकार) को श्री एस० कृष्ण कुमार (सचिव, मछली पालन, केरल सरकार) के स्थान पर प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 11एम०/12/80-ई० पी० (एग्री०-1)]

आई० ए० खां, निदेशक

EP(MP) Desk

New Delhi, the 18th August, 1981

S.O. 2457.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of the Section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972) read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby appoints Shri D. Babu Paul, Special Secretary (Transport, Fisheries & Ports, Government of Kerala) vice Shri S. Krishna Kumar (Secretary Fisheries, Government of Kerala), as member of the Authority.

[No. IM/12/80-EP(Agri.I)]

I. A. KHAN, Director

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1981

का० आ० 2458.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ए० बटकार, आई० ए० एस० (तमिलनाडु संवर्ग-1966) को 17 अगस्त, 1981 से, जिस तारीख से उन्होंने पद का कार्यभार संभाला है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय में रेशम बोर्ड के सचिव के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा० सं० 25012/19/79-रेशम]

एस० थॉ० सत्यऋषि, उप सचिव

(Department of Textiles)

New Delhi, the 27th August, 1981

S.O. 2458.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri A. P. Bhatikar, (IAS: 1966-Tamilnadu) as Secretary to Central Silk Board, with effect from 17th August, 1981, (A.N.) the date on which he assumed charge of the post and until further orders.

[F. No. 25012/19/79-Silk]

L. V. SAPTHARISHI, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(संयुक्त मुख्य नियन्त्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय)

आदेश

मद्रास, 9 जुलाई, 1981

का०आ०.—2459मर्सर्स पलनी आण्डवर मिल्स लिमिटेड, 236-1, डाली रोड, उडमलपेट को, एक संख्या टायडा स्लिवर लाप फार्मर माडल एस० के० 4ए०, फालतू पुर्जे के साथ दो संख्या टायडा हाई प्रोडक्शन कोम्बर माडल सी० एम० 8, यू० टी० 600-यू० टी० 620 के बाक्स में निपिंग प्रेशर की निरीक्षण के लिए डिवाइस की एक संख्या और 9.629-800-3378-1 के काटन स्पीड फ्रेम्स के लिए यू० टी० एम० 620 का आयात करने के लिए लाइसेंस संख्या पी०-सी०जी०-2078347-सी०-एक्स० एस०-77-एम०-80 दिनांक 4-12-80 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो जाने के कारण, उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। उनसे यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की उपयोग उनसे न की गयी है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी०-सी० जी०-2078347-सी०-एक्स० एस०-77-एम०-80 दिनांक 4-12-80 की सीमा-शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और आदेश देता है कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी किया जाए। लाइसेंस की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या 2464762 दिनांक 27-6-81 अलग जारी किया जाता है।

[संख्या: ए० टी० सी०-सी० जी०-लाल-डी० जी० टी० डी०-158-ए० एम० 81-ए० यू० 2]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Madras, the 9th July, 1981

S.O. 2459.—M/s. The Palani Andavar Mills Ltd. 236/1, Dhally Road, Udamalpet, were granted licence No. P/CG/2078347/C/XX/77/M/80 dated 4th December, 1980 for import of 1 No. Toyoda Sliver Lap Former Model SK 4A 2 Nos. Toyoda High Production Comber Model CM-8 with spares and 1 No. Device for checking the Nipping pressure in a box for UT. 600/UT 620 and UTM 620 for cotton speed frames 9.629-800-3378-1.

They have requested to issue a duplicate copy of the above licence (Customs Copy) which has been lost by them. Further it has been stated by them that the above licence has not been utilised by them.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original copy of the licence No. P/CG/2078347/C/XX/77|M|80 dated 4th December, 1980 (Customs copy) has been lost and directs that a duplicate copy of the said licence (Customs copy) should be issued to them. The original copy of the licence is hereby cancelled.

A duplicate licence (Customs copy) No. 2464762 dated 27th June, 1981 has been issued separately.

[No. ITC/CG/Non-DGTD/158/A.M. 81/AU-III]

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय)

आदेश

मद्रास, 17 जुलाई, 1981

का० आ० 2460.—सर्वश्री दी पांडीचेरी पेपर्स लिमिटेड, पिल्लैयारकुप्पम, कुममबाक्कम, बहूर कम्यून, पांडीचेरी-607402 को रुपये 2,53,250 (केवल रुपये दो लाख तिरपन हजार दो सौ पचास) तक, लाइसेंसधारी से लगाये गये या उपयोग में लिये गये पूंजीगत माल की प्रचलन और रख-रखाव के लिए सहायक उपस्कर की फालतू पुर्जे, कंट्रोल और प्रयोगशाला उपस्कर, और सेफ्टि उपकरण के साथ गैर अनुषंग फालतू पुर्जे का आयात करने के लिए लाइसेंस संख्या पी०-ए०-1214107-सी०-एक्स० एक्स०-73-पी०-79 दिनांक 17-11-1979 जारी किया गया था । उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति, मद्रास सीमा-शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कर लेने के बाद, खो जाने के कारण, उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए उन्होंने आवेदन किया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी०-ए०-1214107-सी०-एक्स० एक्स०-73-पी०-79 दिनांक 17-11-79 की सीमा-शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और आदेश देता है कि आवेदक को रुपये 2,53,250 (केवल रुपये दो लाख तिरपन हजार दो सौ पचास) का सीमा-शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी किया जाए। लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या डि० 2465826 दिनांक 17-7-81 अलग जारी किया जाता है।

[संख्या डी० आर० - 357-ए० एम० 82-एयु० 3]

एम० नरसिंहन, उप मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Madras, the 17th July, 1981

S.O. 2460.—M/s. The Pondicherry Papers Limited, Pilliarkuppam, Kirumambakkam, Bahour Commune, Pondicherry-607402 were granted Licence No. P/A/1214107/O/XX/73/P/79 dated 17th November, 1979 for import of "Non permissible spares required for operation and maintenance of the Capital Goods installed or used by the Licence Holder, including spares of Ancillary Equipment, Control and Laboratory Equipment and Safety Appliances" to the value of Rs. 2,53,250 (Rupees Two Lakhs fifty three thousand two hundred and fifty only). They have requested for the issue of duplicate Customs Copy of the above licence which has been lost by them after having been registered with the Customs at Madras.

2. In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs copy of the licence No. P/A/1214107/C/XX/73/P/79 dated 17th November, 1979 has been lost and directs that a duplicate Customs Copy of the said licence be issued to them for the value of Rs. 2,53,250 (Rupees Two lakhs fifty three thousand two hundred and fifty only). The Original Customs Copy of the licence is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Copy of the Licence No. D. 2465826 dated 17th July, 1981 is being issued separately.

[No. DR/357/A.M. 82/AU-III]

S. SARASIMHAN, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1981-08-19

का० आ० 2461.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और ये फीस उनके सामने दिखाई गई तिथियों से लागू होंगी :—

अनुसूची

क्रम सं०	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डाइमेथोएट, तकनीकी	IS : 3902-1975 डाइमेथोएट तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	100 कि० ग्रा०	(i) रु० 10.00 प्रति इकाई पहली 500 इकाइयों के लिए (ii) रु० 5.00 प्रति इकाई 501वी से 1000 इकाइयों के लिए,; और (iii) रु० 1.00 प्रति इकाई 1001वीं इकाई और अगली इकाइयों के लिए	1981-04-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	अविद्युत कार्यों के लिए पिटवां एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्र छड़े, सरियां, नलियां और सेक्शन	IS : 5082-1969 विद्युत कार्यों के लिए पिटवां एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्र छड़े, सरियां, नलियां और सेक्शन की विशिष्ट	एक टन	(i) रु० 10.00 प्रति इकाई पहली 200 इकाइयों के लिए, (ii) रु० 5.00 प्रति इकाई 201वीं से 500 इकाइयों के लिए, और (iii) रु० 1.00 प्रति इकाई 501वीं और अगली इकाइयों के लिए	1981-04-01
3.	अमिथाइल पैराथियान धूलन चूर्ण	IS : 8960-1978 मिथाइल पैराथियान धूलन चूर्ण की विशिष्टि	एक टन	रु० 2.00	1980-11-16
4.	रेजर ब्लेडों के लिए स्टेनलेस इस्पात की शीत वेल्लित पट्टियां	IS : 9294-1979 रेजर ब्लेडों के लिए स्टेनलेस इस्पात की शीत वेल्लित पट्टियों की विशिष्टि	एक टन	(1) रु० 10.00 प्रति इकाई पहली 400 इकाइयों के लिए, और (2) रु० 5.00 प्रति इकाई 401 वीं इकाई और अगली इकाइयों के लिए	1981-03-16

[सं० सी० एम० डी/13 : 10]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1981-08-19

S.O. 2461.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Product/ Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dimethoate, technical	IS: 3902-1975 Specification for dimethoate, technical (first revision)	100 kg	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1000 units and (iii) Re. 1.00 per unit for the 1001st unit and above	1981-04-01
2.	Wrought aluminium and aluminium alloys bars, rods, tubes and sections for electrical purposes.	IS: 5082-1969 Specification for wrought aluminium and aluminium alloys, bars, rods, tubes and sections for electrical purposes.	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 200 units (ii) Rs. 5.00 per unit for the 201st to 500 units and (iii) Re. 1.00 per unit for the 501st unit and above	1981-04-01
3.	Methyl parathion dusting powders.	IS: 8960-1978 Specification for methyl parathion dusting powders.	One Tonne	Rs. 2.00	1980-11-16
4.	Cold-rolled stainless steel strip for razor blades	IS: 9294-1979 Specification for cold-rolled stainless steel strip for razor blades.	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 400 units and (ii) Rs. 5.00 per unit for the 401st unit and above	1981-03-16

[No. CMD/13: 10]

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1981

का० आ० 2462.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (i) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 317 लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका मार्च, 1981 में नवीकरण किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सी एम/एल संख्या	वैध		भारतीय मानक विशिष्टि की पद संख्या
		से	तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	85	81-01-01	81-12-31	IS : 10 (भाग 2)—1976
2.	208	81-02-16	82-02-15	IS : 539—1974
3.	244	81-03-16	82-03-15	IS : 1300—1966
4.	272	81-02-16	82-02-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
5.	391	81-04-01	82-03-31	IS : 226—1975
6.	392	81-04-01	82-03-31	IS : 432 (भाग 1 और 2)—1966
7.	393	81-04-01	82-03-31	IS : 961—1975
8.	396	81-04-01	82-03-31	IS : 226—1975
9.	398	81-04-01	82-03-31	IS : 961—1975
10.	575	81-04-01	82-03-31	IS : 2062—1969
11.	576	81-04-01	82-03-31	IS : 2062—1969
12.	608	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
13.	629	81-01-01	81-12-31	IS : 1855—1977 IS : 1856—1977
14.	663	81-03-01	82-04-30	IS : 692—1973
15.	671	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
16.	834	81-02-01	82-01-31	IS : 398 (भाग 2)—1976
17.	998	81-02-16	82-02-15	IS : 2552—1979
18.	1021	81-04-01	82-03-31	IS : 1875—1978
19.	1022	81-04-01	82-03-31	IS : 1875—1978
20.	1023	81-04-01	82-03-31	IS : 2830—1975
21.	1024	81-04-01	82-03-31	IS : 2831—1975
22.	1034	81-04-01	82-03-31	IS : 2830—1975
23.	1035	81-04-01	82-03-31	IS : 2831—1975
24.	1090	81-03-11	82-02-2	IS : 226—1975
25.	1091	81-03-01	82-02-28	IS : 1977—1975
26.	1133	81-04-01	82-03-31	IS : 7283—1974
27.	1176	81-01-01	81-12-31	IS : 1536—1976
28.	1184	81-03-01	82-02-28	IS : 325—1978
29.	1209	80-12-01	81-11-30	IS : 398—1976
30.	1210	81-02-16	82-02-15	IS : 1011—1968
31.	1227	81-03-16	82-03-15	IS : 325—1978
32.	1319	81-01-16	82-01-15	IS : 2645—1975
33.	1505	81-01-01	81-12-31	IS : 398 (भाग 2)—1976
34.	1552	81-03-01	82-04-30	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
35.	1591	81-04-01	82-03-31	IS : 3564—1975
36.	1605	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (भाग 4)—1976
37.	1608	81-04-01	82-03-31	IS : 10(भाग 4)—1976
38.	1650	81-03-16	82-03-15	IS : 398—1976
39.	1661	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
40.	1665	81-04-01	82-03-31	IS : 226—1975
41.	1758	81-01-01	81-12-31	IS : 3623—1978
42.	1759	81-01-01	81-12-31	IS : 3975—1979
43.	1762	81-01-01	81-12-31	IS : 2266—1977 IS : 2365—1977 और IS : 2581—1977
44.	1784	80-09-16	81-09-15	IS : 278—1978
45.	1872	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1966
46.	1921	81-03-01	82-04-30	IS : 1554 (भाग I)—1976
47.	1933	80-11-01	81-10-31	IS : 3901—1975
48.	1934	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1966
49.	1944	81-01-01	81-12-31	IS : 2418 (भाग 1)—1977
50.	1952	81-04-01	82-03-31	IS : 2879—1975
51.	2024	80-11-01	81-10-31	IS : 4783—1968
52.	2025	80-11-01	81-10-31	IS : 4766—1968
53.	2038	80-10-01	81-09-30	IS : 774—1971
54.	2118	80-11-01	81-01-31	IS : 3990—1975
55.	2224	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (भाग 2)—1976
56.	2239	81-02-01	82-01-31	IS : 2266—1977
57.	2249	81-02-16	82-02-15	IS : 10 (भाग 2)—1976
58.	2252	81-02-16	82-02-15	IS : 829—1978
59.	2270	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (भाग 4)—1976
60.	2286	81-04-01	82-03-31	IS : 3975—1979
61.	2305	81-04-01	82-03-31	IS : 3224—1979
62.	2438	80-11-01	81-10-31	IS : 4320—1967
63.	2471	81-03-01	82-02-28	IS : 561—1978
64.	2532	81-02-16	82-02-15	IS : 779—1968
65.	2590	81-03-16	82-03-15	IS : 2566—1965
66.	2592	81-03-16	82-03-15	IS : 561—1978
67.	2593	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
68.	2618	81-02-01	82-01-31	IS : 562—1978
69.	2745	81-03-16	82-03-15	IS : 565—1975
70.	2628	81-04-01	82-03-31	IS : 10 (भाग 4)—1976
71.	2844	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (भाग 4)—1976
72.	2876	81-04-01	82-03-31	IS : 10 (भाग 4)—1976
73.	2960	81-03-16	82-03-15	IS : 325—1978
74.	2990	81-03-16	82-03-15	IS : 1554 (भाग 1)—1976
75.	3004	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1979
76.	3149	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (भाग 2)—1976
77.	3242	81-03-01	82-02-28	IS : 335—1972
78.	3310	81-02-01	82-01-31	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
79.	3333	81-03-01	82-02-28	IS : 1726 (भाग 2)—1974
80.	3343	81-03-01	82-04-30	IS : 694—1977
81.	3347	81-03-16	82-03-15	IS : 1660—1967
82.	3354	81-03-16	82-03-15	IS : 722 (भाग 2 और 3)—1977
83.	3362	81-03-16	82-03-15	IS : 335—1972
84.	3363	81-03-16	82-03-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
85.	3604	81-01-01	81-12-31	IS : 1785 (भाग 1)—1966 IS : 1785 (भाग 2)—1967
86.	3612	81-02-01	82-01-31	IS : 5852—1977
87.	3628	81-01-01	81-12-31	IS : 6003—1970
88.	3640	80-12-16	81-12-15	IS : 1786—1966
89.	3702	81-02-10	82-01-31	IS : 6003—1970
90.	3703	81-02-01	82-01-31	IS : 1785 (भाग 1)—1966 IS : 1786 (भाग 2)—1967
91.	3716	81-02-16	82-02-15	IS : 1660—1967
92.	3728	81-03-01	82-02-28	IS : 2925—1975
93.	3731	81-03-01	82-02-28	IS : 694—1977
94.	3738	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
95.	3762	81-04-01	82-03-31	IS : 2548—1967
96.	3832	81-02-01	82-01-31	IS : 565—1975
97.	3901	81-02-01	82-01-31	IS : 1011—1968
98.	3910	79-08-16	81-08-15	IS : 1322—1970
99.	3945	81-03-01	82-02-28	IS : 694—1977
100.	4013	81-02-01	82-01-31	IS : 4323—1967
101.	4017	81-02-01	82-01-31	IS : 2865—1964
102.	4087	81-02-01	82-01-31	IS : 6439—1972
103.	4183	81-02-01	82-01-31	IS : 1547—1968
104.	4198	81-04-01	82-03-31	IS : 1554 (भाग I)—1976
105.	4199	81-02-01	82-01-31	IS : 1165—1975
106.	4201	81-02-16	82-02-15	IS : 7122—1973
107.	4205	81-02-16	82-02-15	IS : 2567—1978
108.	4212	81-02-16	82-02-15	IS : 10 (भाग II)—1976
109.	4226	81-01-01	82-12-31	IS : 1538 (भाग 1 से XXIII)—1976
110.	4227	81-03-01	82-02-28	IS : 415—1978
111.	4237	81-03-01	82-02-28	IS : 565—1975
112.	4247	81-03-01	82-02-28	IS : 1786—1979
113.	4259	81-03-16	82-03-15	IS : 1695—1960
114.	4267	81-04-01	82-03-31	IS : 3224—1971
115.	4371	81-02-16	82-02-15	IS : 2089—1977
116.	4646	80-09-16	81-09-15	IS : 1989 (भाग 1)—1978
117.	4737	81-01-01	81-12-31	IS : 1971—1975
118.	4897	81-03-01	82-02-28	IS : 561—1978
119.	4900	81-01-01	81-12-31	IS : 362—1968
120.	4941	81-01-16	82-01-15	IS : 10 (भाग II)—1976 और IS : 1341—1976
121.	4954	81-01-16	82-01-15	IS : 1308—1974
122.	4965	81-03-16	82-03-15	IS : 5225—1969
123.	4978	81-02-81	82-01-31	IS : 1554 (भाग I)—1976
124.	5025	81-03-01	82-02-28	IS : 4184—1967
125.	5030	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
126.	5040	81-03-01	82-02-28	IS : (भाग II)—1976
127.	5051	81-03-01	82-02-28	IS : 1239 (भाग 1)—1979
128.	5066	81-03-16	82-03-15	IS : 1786—1979
129.	5086	81-02-16	82-02-15	IS : 4984—1972
130.	5134	81-04-16	81-04-15	IS : 4174—1977
131.	5293	81-12-01	81-11-30	IS : 417—1974
132.	5355	81-02-16	82-02-15	IS : 6914—1973
133.	5356	81-02-16	82-02-15	IS : 6915—1973
134.	5489	80-09-16	81-09-15	IS : 1601—1960
135.	5516	81-03-01	82-02-28	IS : 1601—1960
136.	5553	81-03-16	82-03-15	IS : 1696—1974
137.	5574	81-03-01	82-02-28	IS : 2567—1978
138.	5610	81-03-16	82-03-15	IS : 1698—1974
139.	5685	81-04-01	82-03-31	IS : 1079—1973
140.	5727	81-03-01	82-02-28	IS : 1538 (भाग 1 से 23)—1976
141.	5752	81-02-16	82-02-15	IS : 564—1975
142.	5827	81-01-16	82-01-15	IS : 2580—1965
143.	5858	81-02-16	82-02-15	IS : 261—1966
144.	5878	81-02-16	82-02-15	IS : 561—1978
145.	5892	81-02-16	82-02-15	IS : 2039—1964
146.	5918	81-03-01	82-02-28	IS : 916—1975
147.	5919	81-03-01	82-02-28	IS : 943—1966 और IS : 944—1966
148.	5924	81-03-01	82-02-28	IS : 4246—1978
149.	5925	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
150.	5932	81-02-16	82-02-15	IS : 7610 (भाग 2)—1975
151.	5933	81-02-16	82-02-15	IS : 7610 (भाग 3)—1975
152.	5939	80-12-16	81-12-15	IS : 6914—1978
153.	5941	81-03-01	82-02-28	IS : 1475—1978
154.	5944	81-03-16	82-03-15	IS : 210—1978
155.	5959	81-03-16	82-03-15	IS : 1320—1972
156.	5963	81-03-16	82-03-15	IS : 4323—1967
157.	5965	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
158.	5976	81-04-01	82-03-31	IS : 10 (भाग 4)—1976
159.	5980	81-03-16	82-03-15	IS : 2567—1978
160.	5986	81-04-01	82-03-31	IS : 226—1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
161.	5987	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
162.	6000	81-03-01	82-02-28	IS : 8144—1976
163.	6020	81-04-01	82-03-31	IS : 1239 (भाग 1)—1979
164.	6464	81-02-16	82-02-15	IS : 226—1975
165.	6491	81-03-16	82-03-15	IS : 7538—1975
166.	6510	81-03-01	82-02-28	IS : 7121 —1973
167.	6620	81-01-01	81-12-31	IS : 4989—1974
168.	6640	81-01-16	82-01-15	IS : 2325—1963
169.	6655	81-03-01	82-02-28	IS : 4323—1967
170.	6678	81-02-01	82-01-31	IS : 2566—1965
171.	6679	81-02-01	82-01-31	IS : 2818—1971
172.	6702	81-02-01	82-01-31	IS : 5086—1969
173.	6714	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
174.	6732	81-02-01	82-01-31	IS : 1660 (भाग 1)—1967 IS : 1660 (भाग 2 और 3)—1972 IS : 1660 (भाग 4)—1977
175.	6742	81-02-16	82-02-15	IS : 366—1976
176.	6752	81-02-16	82-02-15	IS : 5312 (भाग 1)—1969
177.	6772	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
178.	6776	81-03-01	82-02-28	IS : 4355—1977
179.	6783	81-03-01	82-02-28	IS : 834—1975
180.	6784	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (भाग 2)—1975
181.	6785	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (भाग 2)—1975
182.	6788	81-03-01	82-02-28	IS : 3228—1965
183.	6789	81-03-01	82-02-28	IS : 3431—1975
184.	6791	81-03-01	82-02-28	IS : 6914—1978
185.	6802	81-03-16	82-03-15	IS : 7538—1975
186.	6809	81-03-01	82-02-28	IS : 1239(भाग 1)—1979
187.	6814	81-03-16	82-03-15	IS : 7370—1974
188.	6815	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
189.	6821	81-03-16	82-03-15	IS : 1697—1974
190.	6823	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
191.	6824	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
192.	6829	81-03-01	82-02-28	IS : 2141—1968
193.	6830	81-03-16	82-03-15	IS : 2834—1964
194.	6839	81-03-16	82-03-15	IS : 4151—1976
195.	6842	81-02-16	82-02-15	IS : 778—1971
196.	6846	81-03-16	82-03-15	IS : 4396—1967
197.	6849	81-03-16	82-03-15	IS : 1239 (भाग 1)—1979
198.	6865	81-04-01	82-03-31	IS : 1601—1960
199.	6866	81-04-01	82-03-31	IS : 8051—1976
200.	6891	81-04-01	82-03-31	IS : 1601—1960
201.	6907	81-04-01	82-03-31	IS : 3431—1975
202.	6921	81-04-01	82-03-31	IS : 458—1971
203.	7089	81-04-01	82-03-31	IS : 8500—1977
204.	7123	80-08-01	81-07-31	IS : 1239 (भाग 1)—1979
205.	7157	79-09-01	81-08-31	IS : 7193—1974
206.	7197	80-09-16	81-09-15	IS : 1374—1968
207.	7212	81-01-01	81-12-31	IS : 1221—1971
208.	7276	80-10-01	81-09-30	IS : 10 (भाग 4)—1976
209.	7352	81-02-16	82-02-15	IS : 1925—1974
210.	7427	81-01-01	81-12-31	IS : 1970 (भाग 1)—1974
211.	7433	81-01-01	81-12-31	IS : 1307—1975
212.	7453	81-01-16	82-01-15	IS : 1161—1979
213.	7455	81-01-16	82-01-15	IS : 3906 (भाग 1)—1974
214.	7462	81-01-16	82-01-15	IS : 7406 (भाग 1)—1974
215.	7492	81-02-01	82-01-31	IS : 398 भाग 1 और 2)—1976
216.	7495	81-02-01	82-01-31	IS : 7406 (भाग 1)—1974
217.	7506	81-02-16	82-02-15	IS : 2692—1978
218.	7514	81-02-16	82-02-15	IS : 3196—1974
219.	7516	81-02-16	82-02-15	IS : 6914—197 8
220.	7518	81-02-16	82-02-15	IS : 916—1975
221.	7522	81-02-16	82-02-15	IS : 814 (भाग 1 और 2)—1974
222.	7528	81-02-16	82-02-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
223.	7531	81-02-16	82-02-15	IS : 1891 (भाग 1)—1968
224.	7534	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (भाग 2)—1975
225.	7538	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
226.	7539	81-03-01	82-02-28	IS : 7291—1974
227.	7542	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (भाग 4)—1976
228.	7547	81-03-01	82-02-28	IS : 1554 (भाग 1)—1976
229.	7548	81-03-01	82-02-28	IS : 6595—1972
230.	7550	81-03-01	82-02-28	IS : 868—1956
231.	7551	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
232.	7552	81-03-01	82-02-28	IS : 1977—1975
233.	7564	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (भाग 3)—1974
234.	7566	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
235.	7565	81-03-01	82-02-28	IS : 1165—1975
236.	7568	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
237.	7572	81-03-01	82-05-31	IS : 1601—1960
238.	7574	81-03-01	82-02-28	IS : 4366 (भाग 1)—1972
239.	7575	81-03-01	82-07-31	IS : 565—1975
240.	7577	81-03-01	82-02-28	IS : 8259—1976
241.	7578	81-03-01	82-02-28	IS : 3976—1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
242.	7579	81-03-01	82-02-28	IS : 434 (भाग 1)—1964
243.	7580	81-03-01	82-02-28	IS : 1785(भाग 1)—1966
244.	7581	81-03-01	82-02-28	IS : 6003—1970
245.	7583	81-03-01	82-02-28	IS : 561—1978
246.	7605	81-03-16	82-03-15	IS : 6595—1972 और IS : 7538—1975
247.	7613	81-03-16	82-03-15	IS : 2653—1964
248.	7614	81-03-16	82-03-15	IS : 7121—1973
249.	7617	81-03-16	82-03-15	IS : 7121—1973
250.	7618	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (भाग 4)—1976
251.	7619	81-03-16	82-03-15	IS : 220—1972
252.	7633	81-04-01	82-03-31	IS : 1601—1960
253.	7641	81-04-01	82-03-31	IS : 203—1972
254.	7684	81-04-16	82-04-15	IS : 1161—1979
255.	7835	81-03-01	82-02-28	IS : 458—1971
256.	7923	80-08-16	81-08-15	IS : 780—1969
257.	7938	81-03-16	82-03-15	IS : 4654—1974
258.	8187	80-12-16	81-12-15	IS : 158—1968
259.	8264	81-01-01	81-12-31	IS : 4956—1977
260.	8283	81-01-16	82-01-15	IS : 1703—1968
261.	8284	81-01-16	82-01-15	IS : 8931—1978
262.	8285	81-01-16	82-01-15	IS : 2692—1964
263.	8286	81-01-16	82-01-15	IS : 1795—1974
264.	8287	81-01-16	82-01-15	IS : 781—1977
265.	8288	81-01-16	82-01-15	IS : 8934—1978
266.	8308	81-01-16	82-01-15	IS : 226—1975
267.	8324	81-03-16	82-03-15	IS : 1554 (भाग 1)—1976
268.	8348	81-02-01	82-01-31	IS : 1943—1964
269.	8350	81-02-01	82-01-31	IS : 2834—1964
270.	8351	81-02-01	82-01-31	IS : 1786—1979
271.	8354	81-02-01	82-01-31	IS : 10 (भाग 2 2)—1976
272.	8355	81-02-01	81-09-15	IS : 3196—1974
273.	8357	81-02-01	82-01-31	IS : 2834—1964
274.	8363	81-02-16	82-02-15	IS : 1061—1975
275.	8364	81-02-16	82-02-15	IS : 7610 (भाग 4)—1976
276.	8366	81-02-16	82-02-15	IS : 2567—1975
277.	8367	81-02-16	82-02-15	IS : 203—1972
278.	8369	81-03-01	82-04-15	IS : 5277—1969
279.	8374	81-03-01	82-02-28	IS : 5424—1969
280.	8375	81-03-01	82-02-28	IS : 4654—1974
281.	8376	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
282.	8380	81-03-01	82-02-28	IS : 4654—1974
283.	8381	81-03-01	82-02-28	IS : 944—1966
284.	8390	81-03-01	82-02-28	IS : 4323—1967
285.	8394	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (भाग 2)—1975
286.	8395	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (भाग 2)—1975
287.	8396	81-03-01	82-02-28	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
288.	8398	81-03-01	82-02-28	IS : 1785 (भाग 1)—1966
289.	8401	81-03-01	82-02-28	IS : 7122—1973
290.	8402	81-03-01	82-02-28	IS : 2567—1978
291.	8403	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
292.	8404	81-03-01	82-02-28	IS : 3903—1975
293.	8405	81-03-16	82-03-15	IS : 1161—1979
294.	8412	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
295.	8415	81-03-16	82-03-15	IS : 4964 (भाग 2)—1975
296.	8420	81-03-16	82-03-15	IS : 4654—1974
297.	8421	81-03-16	82-03-15	IS : 4654—1974
298.	8422	81-03-16	82-03-15	IS : 8054—1976
299.	8423	81-03-16	82-03-15	IS : 226—1975
300.	8426	81-03-16	82-03-15	IS : 419—1967
301.	8434	81-03-16	82-03-15	IS : 280—1978
302.	8441	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (भाग 2)—1976
303.	8448	81-03-16	82-03-15	IS : 1307—1973
304.	8449	81-03-16	82-03-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
305.	8451	81-03-01	82-02-28	IS : 1786—1979
306.	8457	81-03-16	82-03-15	IS : 3098—1965
307.	8458	81-03-16	82-03-15	IS : 7538—1975
308.	8459	81-03-16	82-03-15	IS : 1554— (भाग 1)—1976
309.	8464	81-04-01	82-03-31	IS : 1322—1970
310.	8465	81-03-16	82-03-15	IS : 2312—1967
311.	8468	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1966
312.	8472	81-03-16	82-03-15	IS : 694—1977
313.	8477	81-04-01	82-03-31	IS : 694—1977
314.	8497	81-04-01	82-03-31	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
315.	8515	81-03-16	82-03-15	IS : 8074—1976
316.	8623	81-04-16	82-04-15	IS : 3975—1979
317.	8628	81-04-16	82-04-15	IS : 226—1975

[सं० मी एम डी/13 : 12]

ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 1981-08-27

S.O.2462.—In Pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 317 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of March 1981.

SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid From	Valid To	Indian Standard Specification No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	85	81-01-01	81-12-31	IS : (Part II)—1976
2.	208	81-02-16	82-02-15	IS : 539—1974
3.	244	81-03-16	82-03-15	IS : 1300—1966
4.	272	81-02-16	82-02-15	IS: 398 (Part I & II)—1976
5.	391	81-04-01	82-03-31	IS : 226—1975
6.	392	81-04-01	82-03-31	IS : 432 (Part I & II)—1966
7.	393	81-04-01	82-03-31	IS : 961 -1975
8.	396	81-04-01	82-03-31	IS : 226 —1975
9.	398	81-04-01	82-03-31	IS : 961—1975
10.	575	81-04-01	82-03-31	IS : 2062—1969
11.	576	81-04-01	82-03-31	IS : 2062—1969
12.	608	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
13.	629	81-01-01	81-12-31	IS : 1855—1977 IS : 1856—1977
14.	663	81-03-01	82-04-30	IS : 692—1973
15.	671	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
16.	834	81-02-01	82-01-31	IS : 398 (Part II) —1976
17.	998	81-02-16	82-02-15	IS : 2552—1979
18.	1021	81-04-01	82-03-31	IS : 1875—1978
19.	1022	81-04-01	82-03-31	IS : 1875—1978
20.	1023	81-04-01	82-03-31	IS : 2830—1975
21.	1024	81-04-01	82-03-31	IS : 2831—1975
22.	1034	81-04-01	82-03-31	IS : 2830—1975
23.	1035	81-04-01	82-03-31	IS : 2831—1975
24.	1090	81-03-11	82-02-28	IS : 226—1975
25.	1091	81-03-01	82-02-28	IS : 1977—1975
26.	1133	81-04-01	82-03-31	IS : 7283—1974
27.	1176	81-01-01	81-12-31	IS : 1536—1976
28.	1184	81-03-01	82-02-28	IS : 325—1978
29.	1209	80-12-01	81-11-30	IS : 398—1976
30.	1210	81-02-16	82-02-15	IS : 1011—1968
31.	1227	81-03-16	82-03-15	IS : 325—1978
32.	1319	81-01-16	82-01-15	IS : 2645—1975
33.	1505	81-01-01	81-12-31	IS : 398(Part II) 1976
34.	1552	81-03-01	82-04-30	IS : 398 (Part I & II)—1976
35.	1591	81-04-01	82-03-31	IS : 3564—1975
36.	1605	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (Part IV)—1976
37.	1608	81-04-01	82-03-31	IS : 10 (Part IV) —1976
38.	1650	81-03-16	82-03-15	IS : 398—1976
39.	1661	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
40.	1665	81-04-01	82-03-31	IS : 226—1975
41.	1758	81-01-01	81-12-31	IS : 3623—1978
42.	1759	81-01-01	81-12-31	IS : 3975—1979
43.	1762	81-01--01	81-12-31	IS : 2266—1977 IS : 2365—1977 IS : 2581—1977
44.	1784	80-09-16	81-09-15	IS : 278—1978
45.	1872	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1966
46.	1921	81-03-01	82-04-30	IS : 1554 (Part I)—1976
47.	1933	80-11-01	81-10-31	IS : 3901—1975
48.	1934	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1966
49.	1944	81 01-01	81-12-31	IS : 2418 (Part I)—1977
50.	1952	81-04-01	82-03-31	IS : 2879—1975
51.	2024	80-11-01	81-10-31	IS : 4783—1968
52.	2025	80-11-01	81-10-31	IS : 4766—1968
53.	2038	80-10-01	81-09-30	IS : 774—1971
54.	2118	80-11-01	81-10-31	IS : 3900—1975
55.	2224	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (Part II)—1976
56.	2239	81-02-01	82-01-31	IS : 2266—1977
57.	2249	81-02-16	82-02-15	IS : 10 (Part II)—1976
58.	2252	82-02-16	82-02-15	IS : 829—1978
59.	2270	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (Part IV)—1976
60.	2286	81-04-01	82-03-31	IS : 3975—1979
61.	2305	81-04-01	82-03-31	IS : 3224—1979
62.	2438	80-11-01	81-10-31	IS : 4320—1967
63.	2471	81-03-01	82-02-28	IS : 561—1978
64.	2532	81-02-16	82-02-15	IS : 779—1968
65.	2590	81-03-16	82-03-15	IS : 2566—1965
66.	2592	81-03-16	82-03-15	IS : 561—1978
67.	2593	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
68.	2618	81-02-01	82-01-31	IS : 562—1978
69.	2745	81-03-16	82-03-15	IS : 565—1975
70.	2628	81-04-01	82-03-31	IS : 10 (Part IV)—1976
71.	2844	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (Part IV)—1976
72.	2876	81-04-01	82-03-31	IS : 10 (Part IV)—1976
73.	2960	81-03-16	82-03-15	IS : 325—1978
74.	2990	81-03-16	82-03-15	IS : 1554 (Part I)—1976
75.	3004	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1979
76.	3149	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (Part II)—1976
77.	3242	81-03-01	82-02-28	IS : 335—1972
78.	3310	81-02-01	82-01-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
79.	3333	81-03-01	82-02-28	IS : 1726 (Part II)—1974
80.	3343	81-03-01	82-04-30	IS : 694—1977

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81.	3347	81-03-16	82-03-15	IS : 1660—1967
82.	3354	81-03-16	82-03-15	IS : 722 (Part II & III)—1977
83.	3362	81-03-16	82-03-15	IS : 335—1972
84.	3363	81-03-16	82-03-15	IS : 398 (Part I & II—1976)
85.	3604	81-01-01	81-12-31	IS : 1785 (Part 1)—1966 IS : 1785 (Part II)—1967
86.	3612	81-02-01	82-01-31	IS : 5852—1977
87.	3628	81-01-01	81-12-31	IS : 6003—1970
88.	3640	80-12-16	81-12-15	IS : 1786—1966
89.	3702	81-02-01	82-01-31	IS : 6003—1970
90.	3703	81-02-01	82-01-31	IS : 1785 (Part I)—1966 IS : 1786 (Part II)—1967
91.	3716	81-02-16	82-02-15	IS : 1660—1967
92.	3728	81-03-01	82-02-28	IS : 2925—1975
93.	3731	81-03-01	82-02-28	IS : 694—1977
94.	3738	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
95.	3762	81-04-01	82-03-31	IS : 2548—1967
96.	3832	81-02-01	82-01-31	IS : 565—1975
97.	3901	81-02-01	82-01-31	IS : 1011—1968
98.	3910	79-08-16	81-08-15	IS : 1322—1970
99.	3945	81-03-01	82-02-28	IS : 694—1977
100.	4013	81-02-01	82-01-31	IS : 4323—1967
101.	4017	81-02-01	82-01-31	IS : 2865—1964
102.	4087	81-02-01	82-01-31	IS : 6439—1972
103.	4183	81-02-01	82-01-31	IS : 1547—1968
104.	4198	81-04-01	82-03-31	IS : 1554 (Part I)—1976
105.	4199	81-02-01	82-01-31	IS : 1165—1975
106.	4201	81-02-16	82-02-15	IS : 7122—1973
107.	4205	81-02-16	82-02-15	IS : 2567—1978
108.	4212	81-02-16	82-02-15	IS : 10 (Part II)—1976
109.	4226	81-01-01	82-12-31	IS : 1538 (Parts 1 to XXIII)—1976
110.	4227	81-03-01	82-02-28	IS : 415—1978
111.	4237	81-03-01	82-02-28	IS : 565—1975
112.	4247	81-03-01	82-02-28	IS : 1786—1979
113.	4259	81-03-16	82-03-15	IS : 1695—1960
114.	4267	81-04-01	82-03-31	IS : 3224—1971
115.	4371	81-02-16	82-02-15	IS : 2089—1977
116.	4646	80-09-15	81-09-15	IS : 1989 (Part I)—1978
117.	4737	81-01-01	81-12-31	IS : 1971—1975
118.	4897	81-03-01	82-02-28	IS : 561—1978
119.	4900	81-01-01	81-12-31	IS : 362—1968 & IS : 1341—1976
120.	4941	81-01-16	82-01-15	IS : 10 (Part II)—1976
121.	4954	81-01-16	82-01-15	IS : 1308—1974
122.	4965	81-03-16	82-03-15	IS : 5225—1969
123.	4978	81-02-01	82-01-31	IS : 1554 (Part 1)—1976
124.	5025	81-03-01	82-02-28	IS : 4184—1967
125.	5030	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
126.	5040	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (Part II)—1976
127.	5051	81-03-01	82-02-28	IS : 1239 (Part I)—1979
128.	5066	81-03-16	82-03-15	IS :1786—1979
129.	5086	81-02-16	82-02-15	IS : 4984—1972
130.	5134	80-04-16	81-04-15	IS : 4174—1977
131.	5293	80-12-01	81-11-30	IS : 417—1974
132.	5355	81-02-16	82-02-15	IS : 6914—1973
133.	5356	81-02-16	82-02-15	IS : 6915—1973
134.	5489	80-09-16	81-09-15	IS : 1601—1960
135.	5516	81-03-01	82-02-28	IS : 1601—1960
136.	5553	81-03-16	82-03-15	IS : 1696—1974
137.	5574	81-03-01	82-02-28	IS : 2567—1978
138.	5610	81-03-16	82-03-15	IS : 1698—1974
139.	5685	81-04-01	82-03-31	IS : 1079—1973
140.	5727	81-03-01	82-02-28	IS : 1538 (Parts I to XXIII)—1976
141.	5752	81-02-16	82-02-15	IS : 564—1975
142.	5827	81-01-16	82-01-15	IS : 2580—1965
143.	5858	81-02-16	82-02-15	IS : 261—1966
144.	5878	81-02-16	82-02-15	IS : 561—1978
145.	5892	81-02-16	82-02-15	IS : 2039—1964
146.	5918	81-03-01	82-02-28	IS : 916—1975
147.	5919	81-03-01	82-02-28	IS : 943—1966 & IS : 944—1966
148.	5924	81-03-01	82-02-28	IS : 4246—1978
149.	5925	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
150.	5932	81-02-16	82-02-15	IS : 7610 (Part II)—1975
151.	5933	81-02-16	82-02-15	IS : 7610 (Part III)—1975
152.	5939	80-12-16	81-12-15	IS : 6914—1978
153.	5941	81-03-01	82-02-28	IS : 1475—1978
154.	5944	81-03-16	82-03-15	IS : 210—1978
155.	5959	81-03-16	82-03-15	IS : 1320—1972
156.	5963	81-03-16	82-03-15	IS : 4323—1967
157.	5965	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
158.	5976	81-04-01	82-03-31	IS : 10 (Part IV)—1976
159.	5980	81-03-16	82-03-15	IS : 2567—1978
160.	5986	81-04-01	82-03-31	IS : 226—1975
161.	5987	81-04-01	82-03-31	IS : 1977—1975
162.	6000	81-03-01	82-02-28	IS : 8144—1976
163.	6020	81-04-01	82-03-31	IS : 1239 (Part I)—1979
164.	6464	81-02-16	82-02-15	IS : 226—1975
165.	6491	81-03-16	82-03-15	IS : 7538—1975
166.	6510	81-03-01	82-02-28	IS : 7121—1973
167.	6620	81-01-01	81-12-31	IS : 4989—1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
168.	6640	81-01-16	82-01-15	IS : 2325—1963
169.	6655	81-03-01	82-02-28	IS : 4323—1967
170.	6678	81-02-01	82-01-31	IS : 2566—1965
171.	6679	81-02-01	82-01-31	IS : 2818—1971
172.	6702	81-02-01	82-01-31	IS : 5086—1969
173.	6714	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
174.	6732	81-02-01	82-01-31	IS : 1660 (Part I)—1967 IS : 1660 (Part II & III)—1972 IS : 1660 (Part IV)—1977
175.	6742	81-02-16	82-02-15	IS : 366—1976
176.	6752	81-02-16	82-02-15	IS : 5312 (Part I)—1969
177.	6772	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
178.	6776	81-03-01	82-02-28	IS : 4355—1977
179.	6783	81-03-01	82-02-28	IS : 834—1975
180.	6784	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (Part II)—1975
181.	6785	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (Part II)—1975
182.	6788	81-03-01	82-02-28	IS : 3228—1965
183.	6789	81-03-01	82-02-28	IS : 3431—1975
184.	6791	82-03-01	82-02-28	IS : 6914—1978
185.	6802	81-03-16	82-03-15	IS : 7538—1975
186.	6809	81-03-01	82-02-28	IS : 1239 (Part I)—1979
187.	6814	81-03-16	82-03-15	IS : 7370—1974
188.	6815	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
189.	6821	81-03-16	82-03-15	IS : 1697—1974
190.	6823	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
191.	6824	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
192.	6829	81-03-01	82-02-28	IS : 2141—1968
193.	6830	81-03-16	82-03-15	IS : 2834—1964
194.	6839	81-03-16	82-03-15	IS : 4151—1976
195.	6842	81-02-16	82-02-15	IS : 778—1971
196.	6846	81-03-16	82-03-15	IS : 4396—1967
197	6849	81-03-16	82-03-15	IS : 1239 (Part I)—1979
198.	6865	81-04-01	82-03-31	IS : 1601—1960
199.	6866	81-04-01	82-03-31	IS : 8051—1976
200.	6891	81-04-01	82-03-31	IS : 1601—1960
201.	6907	81-04-01	82-03-31	IS : 3431—1975
202.	6921	81-04-01	82-03-31	IS : 458—1971
203.	7089	81-04-01	82-03-31	IS : 8500—1977
204.	7123	80-08-01	81-07-31	IS : 1239 (Part I)—1979
205.	7157	79-09-01	81-08-31	IS : 7193—1974
206.	7197	80-09-16	81-09-15	IS : 1374—1968
207.	7212	81-01-01	81-12-31	IS : 1221—1971
208.	7276	80-10-01	81-09-30	IS : 10 (Part IV)—1976
209.	7352	81-02-16	82-02-15	IS : 1925—1974
210.	7427	81-01-01	81-12-31	IS : 1970 (Part I)—1974
211.	7433	81-01-01	81-12-31	IS : 1307—1975
212.	7453	81-01-16	82-01-15	IS : 1161—1979
213.	7455	81-01-16	82-01-15	IS : 3906 (Part I)—1974
214.	7462	81-01-16	82-01-15	IS : 7406 (Part I)—1974
215.	7492	81-02-01	82-01-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
216.	7495	81-02-01	82-01-31	IS : 7406 (Part I)—1974
217.	7506	81-02-16	82-02-15	IS : 2692—1978
218.	7514	81-02-16	82-02-15	IS : 3196—1974
219.	7516	81-02-16	82-02-15	IS : 6914—1978
220.	7518	81-02-16	82-02-15	IS : 916—1975
221.	7522	81-02-16	82-02-15	IS : 814 (Part I & II)—1974
222.	7528	81-02-16	82-02-15	IS : 398 (Part I II)—1976
223.	7531	81-02-16	82-02-15	IS : 1891 (Part I)—1968
224.	7534	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (Part II)—1975
225.	7538	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
226.	7539	81-03-01	82-02-28	IS : 7291—1974
227.	7542	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (Part IV)—1976
228.	7547	81-03-01	82-02-28	IS : 1554 (Part I)—1976
229.	7548	81-03-01	82-02-28	IS : 6595—1972
230.	7550	81-03-01	82-02-28	IS : 868—1956
231.	7551	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
232.	7552	81-03-01	82-02-28	IS : 1977—1975
233.	7564	81-03-01	82-02-28	IS : 10 (Part III)—1974
234.	7566	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
235.	7565	81-03-01	82-02-28	IS : 1165—1975
236.	7568	81-03-01	82-02-28	IS : 1161—1979
237.	7572	81-03-01	82-05-31	IS : 1601—1960
238.	7574	81-03-01	82-02-28	IS : 4366 (Part I)—1972
239.	7575	81-03-01	82-07-31	IS : 565—1975
240.	7577	81-03-01	82-02-28	IS : 8259—1976
241.	7578	81-03-01	82-02-28	IS : 3976—1975
242.	7579	81-03-01	82-02-28	IS : 434 (Part I)—1964
243.	7580	81-03-01	82-02-28	IS : 1758 (Part I)—1966
244.	7581	81-03-01	82-02-28	IS : 6003—1970
245.	7583	81-03-01	82-02-28	IS : 561—1978
246.	7605	81-03-16	82-03-15	IS : 6595—1972 and IS : 7538—1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
247.	7613	81-03-16	82-03-15	IS : 2653—1964
248.	7614	81-03-16	82-03-15	IS : 7121—1973
249.	7617	81-03-16	82-03-15	IS : 7121—1973
250.	7618	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (Part IV)—1976
251.	7619	81-03-16	82-03-15	IS : 220—1972
252.	7633	81-04-01	82-03-31	IS : 1601—1960
253.	7641	81-04-01	82-03-31	IS : 203—1972
254.	7684	81-04-16	82-04-15	IS : 1161—1979
255.	7835	81-03-01	82-02-28	IS : 458 —1971
256.	7923	80-08-16	81-08-15	IS : 780—1969
257.	7938	81-03-16	82-03-15	IS : 4654—1974
258.	8187	80-12-16	81-12-15	IS : 158—1968
259.	8264	81-01-01	81-12-31	IS : 4956—1977
260.	8283	81-01-16	82-01-15	IS : 1703—1968
261.	8284	81-01-16	82-01-15	IS : 8931—1978
262.	8285	81-01-16	82-01-15	IS : 2692—1964
263.	8286	81-01-16	82-01-15	IS : 1795—1974
264.	8287	81-01-16	82-01-15	IS : 781—1977
265.	8288	81-01-16	82-01-15	IS : 8934—1978
266.	8308	81-01-16	82-01-15	IS : 226—1975
267.	8324	81-03-16	82-03-15	IS : 1554 (Part I) —1976
268.	8348	81-02-01	82-01-31	IS : 1943—1964
269.	8350	81-02-01	82-01-31	IS : 2834—1964
270.	8351	81-02-01	82-01-31	IS : 1786—1979
271.	8354	81-02-01	82-01-31	IS : 10 (Part II)—1976
272.	8355	81-02-01	81-09-15	IS : 3196—1974
273.	8357	81-02-01	82-01-31	IS : 2834—1964
274.	8363	81-02-16	82-02-15	IS : 1061—1975
275.	8364	81-02-16	82-02-15	IS : 7610 (Part IV)—1976
276.	8366	81-02-16	82-02-15	IS : 2567—1975
277.	8367	81-02-16	82-02-15	IS : 203—1972
278.	8369	81-03-01	82-04-15	IS : 5277—1969
279.	8374	81-03-01	82-02-28	IS : 5424—1969
280.	8375	81-03-01	82-02-28	IS : 4654—1974
281.	8376	81-03-01	82-02-28	IS : 226—1975
282.	8380	81-03-01	82-02-28	IS : 4654—1974
283.	8381	81-03-01	82-02-28	IS : 944—1966
284.	8390	81-03-01	82-02-28	IS : 4323—1967
285.	8394	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (Part II)—1975
286.	8395	81-03-01	82-02-28	IS : 4964 (Part II)—1975
287.	8396	81-03-01	82-02-28	IS : 398 (Part I & II)—1976
288.	8398	81-03-01	82-02-28	IS : 1785 (Part I)—1966
289.	8401	81-03-01	82-02-28	IS : 7122—1973
290.	8402	81-03-01	82-02-28	IS : 2567—1978
291.	8403	81-03-01	82-02-28	IS : 633—1975
292.	8404	81-03-01	82-02-28	IS : 3903—1975
293.	8405	81-03-16	82-03-15	IS : 1161—1979
294.	8412	81-03-16	82-03-15	IS : 564—1975
295.	8415	81-03-16	82-03-15	IS : 4964 (Part II)—1975
296.	8420	81-03-16	82-03-15	IS : 4654—1974
297.	8421	81-03-16	82-03-15	IS : 4654—1974
298.	8422	81-03-16	82-03-15	IS : 8054—1976
299.	8423	81 03-16	82-03-15	IS : 226—1975
300.	8426	81-03-16	82-03-15	IS : 419—1967
301.	8434	81-03-16	82-03-15	IS : 280—1978
302.	8441	81-03-16	82-03-15	IS : 10 (Part II)—1976
303.	8448	81-03-16	82-03-15	IS : 1307—1973
304.	8449	81-03-16	82-03-15	IS : 398 (Part I & II)—1976
305.	8451	81-03-01	82-02-28	IS : 1786—1979
306.	8457	81-03-16	82-03-15	IS : 3098—1965
307.	8458	81-03-16	82-03-15	IS : 7538—1975
308.	8459	81-03-16	82-03-15	IS : 1554 (Part I)—1976
309.	8464	81-04-01	82-03-31	IS : 1322—1970
310.	8465	81-03-16	82-03-15	IS : 2312—1967
311.	8468	81-04-01	82-03-31	IS : 1786—1966
312.	8472	81-03-16	82-03-15	IS : 694—1977
313.	8477	81-04-01	82-03-31	IS : 694—1977
314.	8497	81-04-01	82-03-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
315.	8515	81-03-16	82-03-15	IS : 8074—1976
316.	8623	81-04-16	82-04-15	IS : 3975—1979
317.	8628	81-04-16	82-04-15	IS : 226—1975

[No. CMD/13 : 12]

A. P. BANERJI, Addl. Director General

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1981

का० आ० 2463 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरण टर्मिनल से थल वायशेत तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बम्बई (प्ला० नं० 9, मि० कला दी० सोसायटी पनवेल, जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से थल वायशेत (आर० सी० एफ० प्रोजेक्ट) तक पाईपलाइन बिछाने के लिये

राज्य—महाराष्ट्र जिला—रायगढ़ तालुका—अलिबाग

गांव	सर्वेक्षण नंबर	एच० नं०	हेक्टेयर	ए	आर ई	सेंटेयर
बोरीस	73	1	0	12	2	
		2	0	02	2	
		4	0	02	0	
	72	4	0	06	2	
		2	0	18	7	
	69	5	0	01	5	
		1	0	13	0	
	53	3	0	07	5	
	58	5	0	11	9	
		3	0	08	0	
		2	0	20	0	
		1	0	06	0	
	60	1	0	32	2	
		2	0	14	2	
	57		0	01	0	
	61		0	08	0	
	63	3	0	20	0	
		2(1)	0	09	0	
		2(2)	0	04	0	
		जोड़	1	97	6	

[सं० 12016/34/81-प्रो०-I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 26th August, 1981

S.O. 2463.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Thal Vaishet (R.C.F. Project) in Maharashtra State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Bombay Offshore Project. Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel, Taluka Panvel, District Raigad; Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically where he wishes to be heard in person or by a legal practitioner,

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Thal Vaishet (R.C.F. Project).
State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Alibag.

Village	S. No.	H. No.	Area Hectare	Are	Centiare
Boris	73	1 Part	0	12	2
		2 Part	0	02	2
		4 Pt.	0	02	0
	72	4 Pt.	0	06	2
		2 Pt.	0	18	7
	69	5 Pt.	0	01	5
		1 Pt.	0	13	0
	53	3 Pt.	0	07	5
	58	5 Pt.	0	11	9
		3 Pt.	0	08	0
		2 Pt.	0	20	0
		1 Pt.	0	06	0
	60	1 Pt.	0	32	2
		2 Pt.	0	14	2
	57	Pt.	0	01	0
	61	Pt.	0	08	0
	63	3 Pt.	0	20	0
		2(1) Pt.	0	09	0
		2(2)Pt.	0	04	0
		Total	1	97	6

[No. 12016/34/81—Prod-I]

का० आ० 2464.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरण टर्मिनल से थल वायशेत तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 196 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (बम्बई प्लां० नं० 9 मि० क्लां० हौ० सोसायटी, पनवेल, जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से थल वायशेत (आर० सी० एफ० प्रोजेक्ट) तक पाईपलाइन बिछाने के लिये

राज्य—महाराष्ट्र जिला—रायगढ़ तालुका—अलिबाग

गांव	सर्वेक्षण	संबर	हेक्टेयर ए आर ई सेंटेयर
आगरसुरे	13	9	0-17-5
		14	0-00-2
	6	2	0-01-5
		3	0-07-0

गांव	सर्वेक्षण नम्बर		हेक्टेयर	आर ई	सेंटीयर
आगरसुरे—(जारी 4)	4	Pt.	0	04	5
	1	Pt.	0	13	5
	4	12 Pt.	0	10	0
		11 Pt.	0	02	8
		10 Pt.	0	04	0
	7	Pt.	0	11	2
	141	Pt.	0	26	0
	143	2 Pt.	0	01	8
	140	6 Pt.	0	16	0
		5 Pt.	0	05	0
	136		0	22	5
	138	2C+3B —————Pt. 4	0	09	0
		2C+3B —————Pt. 1	0	02	5
		2C+3B —————Pt. 3	0	00	5
	132	2 Pt.	0	03	5
		3 Pt.	0	21	0
	147	1A Pt.	0	01	3
		1B Pt.	0-	07	5
		2 Pt.	0	12	0
	126	1 Pt.	0	13	2
		3 Pt.	0	15	0
		4 Pt.	0	00	3
	120	Pt.	0	04	0
	118	3 Pt.	0	00	5
		5 Pt.	0	08	5
		2 Pt.	0	00	5
	121	1A+2A —————Pt. 2	0	021	0
		1A+2A —————Pt. 1	0	06	6
	107	1 Pt.	0	09-	8
		2 Pt.	0	03	7
		3 Pt.	0	05	0
		7 Pt.	0	12	8
	109	6 Pt.	0	01	0—
		जोड़	3	02	9

[सं० 12016/34/81-प्रा०-II]

टी० एम० परमेश्वरन, अवर सचिव

S.O. 2464.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Thal Vaishet (R.C.F. Project) in Maharashtra State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Bombay Offshore Project, Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel, Taluka-Panvel, District-Raigad; Maharashtra-State.

And every person making such an objection shall state specifically where he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Thal-Vaishet (R.C.F. Project).

State-Maharashtra District—Raigad Taluka—Alibag.

Village	S. No.	H. No.	Area Hectare	Are	Centare
Agarsure	13	9 Pt.	0	17	5
		14 Pt.	0	00	2
	6	2 Pt.	0	01	5
		3 Pt.	0	07	0
		4 Pt.	0	04	5
		1 Pt.	0	13	5
	4	12 Pt.	0	10	0
		11 Pt.	0	02	8
		10 Pt.	0	04	0
	7	Pt.	0	11	2
	141	Pt.	0	26	0
	143	2 Pt.	0	01	8
	140	6 Pt.	0	16	0
		5 Pt.	0	05	2
	136	Pt.	0	22	5
	137	2C+3B —————Pt. 1	0	09	0
		2C+3B —————Pt. 1	0	02	5
		2B+3A —————Pt. 3	0	00	5
	132	2 Pt.	0	03	5
		3 Pt.	0	21	0
	147	1A Pt.	0	01	3
		1B Pt.	0	07	5
		2 Pt.	0	12	0
	126	1B Pt.	0	13	2
		3 Pt.	0	15	0
		4 Pt.	0	00	3
	120	Pt.	0	04	0
	118	3 Pt.	0	00	5
		5 Pt.		08	5
		2 Pt.	0	00	5
	121	1A+2A —————Pt. 2	0	21	0
		1A+2A —————Pt. 1	0	06	6
	107	1 Pt.	0	09	8
		2 Pt.	0	03	7
		3 Pt.	0	05	0
		7 Pt.		12	8
	109	6 Pt.	0	01	0
		Total	3	02	9

[No. 12016/34/81-Prod-II]

T. N. PARAMESWARAN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1981

का० आ० 2465—भारत के राजपत्र तारीख 24 जनवरी, 1981 के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड II में पृष्ठ 277-282 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 289 तारीख 12 जनवरी, 1981 में :—

पृष्ठ 277 पर

अ. अधिसूचना में स्पष्टीकरण के प्रारम्भ में "इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जायगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिये स्वयं खनन सक्रियाएं करना चाहता है" के स्थान पर "इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियाएं करना चाहता है" पढ़िए ।

पृष्ठ 278 पर

अ. अनुसूची "क" में ग्राम शीर्षक के नीचे "चन्दा रेयतवाड़ी" के स्थान पर "चान्दा रेयतवारी" पढ़िए और उन सभी भागों पर जहां कहीं "चन्दा रेयतवाड़ी" आता है "चान्दा रेयतवारी" पढ़िए ।

ब. ग्राम नन्दगांव में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या में "3/2, 3/7, 3/6, व "3/3, 3/4" (भाग) के स्थान पर क्रमशः 3/2-3/7-3/6-"व 3/3-3/4" (भाग) पढ़िए ।

पृष्ठ 279 पर

अनुसूची "ख" रेखांक सं० 26/80 के नीचे ....." और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन किया गया है" के स्थान पर "और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन किया जाना है" ।

[सं० 19(43)/80 सी० एल०]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1981

का० आ० 2466.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 3 मई, 1980 के पृष्ठ 1307 से पृष्ठ 1314 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1251 तारीख 18 अप्रैल, 1980 में—

पृष्ठ 1309, पंक्ति 41—'भाग "ग"' के स्थान पर 'बिंदु "ग"' पढ़ें।

पृष्ठ 1311, पंक्ति 46-47, 'भाग "च"' के स्थान पर 'बिन्दु "च"' पढ़ें।

पृष्ठ 1311, पंक्ति 48,—'भाग "छ"' के स्थान पर 'बिंदु "छ"' पढ़ें।

पृष्ठ 1312, पंक्ति 40,—"268 (पी), 273 (पी)" के स्थान पर "468 (पी), 272 (पी), 273 (पी)" पढ़ें।

पृष्ठ 1312, पंक्ति 43,—"815 (पी)" के स्थान पर "816" पढ़ें।

[सं० 19/44/78 सी० एल वाल्यूम-II]

स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDA

New Delhi, the 5th September, 1981

S.O. 2466.—In the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal), No. S.O. 1251 dated the 18th April, 1980, published in the Gazette of India, Part II-Section 3—Sub-section (ii), dated the 3rd May, 1980, at pages 1314 to 1319,—

(1) at page 1315,—

(i) in line 11, for "line passes" read "lines pass";

(ii) in line 32, for "63(A)" read "63(P)";

(iii) in line 43, for "26(2P)" read "26/2(P)";

(iv) in line 45, for "14 to 214" read "14 to 249".

(v) in line 48, for "Chinagitala & meets at part 'B'" read "Chinagitola & meets at point B";

(vi) in line 50, for "part 'C'" read "point C";

(vii) in line 52, for "part 'D'" read "point D";

(2) at page 1316,—

(i) in line 30, for "495(P), 496/2(P), 498 to 501" read "495(P), 496(P), 496/2(P), 497 to 501".

(ii) in line 52, for "Amihar" read "Amjhar";

(3) at page 1317,—

(i) in line 30, for "part 'F'" read "point 'F'";

(ii) in line 31, for "part 'E' read point E' ";

(iii) in line 45, against Sl. No. 4 for "475" read "476";

(4) at page 1318,—

(i) in line 16, for "268(P), 273(P)" read "468(P), 272(P), 273(P)";

(ii) in line 18, for "815(P)" read "816";

(iii) in line 21, for "365 to 734" read "365 to 473";

(iv) in line 25, for "734 to 787" read "734 to 746";

(v) in line 26, for "Itwar" read "Itwa";

(5) at page 1319,—

(i) in line 2, for "60" read "66";

(ii) in line 3 (a) for "102" read "162"; and

(b) for "164" read "154";

(iii) in line 5, for "1 alon" read "along";

(iv) in line 13, for "M2" read "M1-M2";

(v) in line 19, for "ons" read "number";

[No. 19/44/78-CL. Vol. II]

SWARAN SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1981

का० आ० 2467.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग 2 के अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन"	जे० ई० पुरकिन यूनिवर्सिटी, ब्नो, चैकोस्लोवाकिया	उपर्युक्त चिकित्सा अर्हता 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ।

[सं० वी० 11015/9/80-एम० ई० (पी)]

सी० वी० एस० मणि, अपर सचिव

New Delhi, the 2nd September, 1981

S.O. 2467.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in part II of the Third Schedule to the said Act, namely :

In part II of the Third Schedule to the said Act, the following entries shall be added at the end, namely :—

"Doctor of Medicine"	J. E. Purkyn University, Brno, Czechoslovakia

The medical qualification noted above shall be recognised medical qualification for the period upto the 31st day of December, 1985.

[No. V.11015/9/80-ME(P)]

C. V. S. MANI, Additional Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1981

का० आ० 2468—यतः दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (च) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने डा० आर० के० बाली, बी० डी० एस० (पंजाब), एफ० आर० एस० एच० (लंदन), एफ० आई० सी० ओ०, एम० पी० एच० (अमेरिका), दन्त सर्जन, 20 बी०/1, डी० बी० गुप्ता रोड़, देवनगर करोलबाग, नई दिल्ली-110005 को 21 जुलाई, 1981 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 9 फरवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या वी०12013/1/77-एम० पी० टी० (पी० एम० एस०) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड (च) के अधीन मनोनीत" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"डा० आर० के० बाली, बी० डी० एस० (पंजाब) एफ० आर० एस० एच० (लंदन), एफ० आई० सी० ओ० एम० पी० एच० (अमेरिका), दन्त सर्जन 20 बी/1, डी० बी० गप्ता रोड़, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	केन्द्रीय सरकार 21-7-1981"

[संख्या वी० 12013/1/81-पी० एम० एस]

एम० ए० सुब्रामोनी, अवर सचिव

(Department of Health)

New Delhi, the 3rd September, 1981

S.O. 2468.—Whereas, the Central Government have in pursuance of clause (f) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), nominated Dr. R. K. Bali, B.D.S.(Pb), F.R.S.H (Lond), F.I.C.O., MPH(USA), Dental Surgeon, 20B/1, D.B. Gupta Road, Dev Nagar, Karolbagh, New Delhi-110005, to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 21st July, 1981;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 12013/1/77 MPT (PMS), dated the 9th February, 1978, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (f) of section 3", for serial No. 1 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

"Dr. R. K. Bali B.D.S.(Pb.) F.R.S. (Lond.), F.I.C.O. (MPH)(USA), 20B/1, D. B. Gupta Road, Dev Nagar, Karolbagh, New Delhi-110005.	Central Government 21-7-81" Dental Surgeon

[No. V. 12013/1/81-PMS]

N. A. SUBRAMONEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1981

का० आ० 2469.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की अनुसूची में एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपर्युक्त अनुसूची के "एब्रीविएशन फार रजिस्ट्रेशन" शीर्षक कालम में :—

(1) बर्दवान विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "30 अप्रैल, 1981" अंकों, वर्णों, एवं शब्द के स्थान पर "30 अप्रैल, 1982" अंक, वर्ण, एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(2) भागलपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियो में 30 अप्रैल, 1981" अंकों, वर्णों एवं शब्दों के स्थान पर "30 अप्रैल, 1982" अंक, वर्ण एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(3) मगध विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में 30 अप्रैल, 1981" के अंकों, वर्णों एवं शब्द के स्थान पर "30 अप्रैल, 1982" अंक वर्ण, एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(4) उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "30 अप्रैल, 1981" अंक, वर्ण और शब्द के स्थान पर "30 अप्रैल, 1982" अंक, वर्ण और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं० वी० 11015/7/81-एम० ई० (नीति)]

प्रकाश चन्द्र जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1981

S.O. 2469.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule in the said Act, namely :—

In the said Schedule, in the column "Abbreviation for registration":—

(1) In the entries relating to Burdwan University, for the figures, letters and word "30th April, 1981" the figures, letters and word "30th April, 1982" shall be substituted;

(2) in the entries relating to Bhagalpur University for the figures, letters ad word "30th April, 1981" the figures, letters and word "30th April, 1982" shall be substituted;

(3) in the entries relating to Magadh University, for the figures, letter and word "30th April, 1981" the figures, and word "30th April, 1982", shal be substituted;

(4) in the entries relating to North Bengal University, for the figures, letters and word "30th April, 1981" the figures, letters and word "30th April, 1982" shall be substituted.

[No. V.11015/7/81-M.E.(Policy)]

P. C. JAIN, Under Secy.

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1981

का० आ० 2470.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्रीमती अन्ना आर० मल्होत्रा को श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी के स्थान पर तीन वर्षों की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 10-56/81 डेस्क (यू)]

म० रा० कोल्हटकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(Department of Education)

New Delhi, the 31st August, 1981

S.O. 2470.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 5 read with sub-section (i) of section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Mrs. Anna R. Malhotra, Secretary, Ministry of Education and Culture to be a Member of the University Grants Commission for a term of three years vice Shri T. N. Chaturvedi.

[No. F. 10-56/81-Desk(U)]

M. R. KOLHATKAR, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1981

का० आ० 2471.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तद्द्वारा बम्बई पत्तन न्यास (सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक पेन्शन देना (संशोधन) विनियम, 1981 का अनुमोदन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाया गया और महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र 12 मार्च, 1981 और 19 मार्च, 1981 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

[सं० पी० डब्ल्यू० /पी०ई०बी०/23/81]

राम तिलक पांडेय, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 16th July, 1981

S.O. 2471.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the Regulation entitled Bombay Port Trust (Grant of Ex-gratia Pension to Retired Employees) (Amendment) Regulations, 1981, made by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise of the powers conferred by section 28 read with sub-section (2) of section 124, of the said Act, and published in the Maharashtra Government Gazette dated the 12th March, 1981 and the 19th March, 1981.

[No. PW-PEB-33/81.]

R. T. PANDEY, Under Secy.

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1981

पुरातत्व

का० आ० 2472.—केन्द्रीय सरकार, यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित संस्मारक के समीप अथवा संलग्न क्षेत्रों को खदान-प्रक्रिया अथवा निर्माण अथवा दोनों के लिए निषिद्ध करने का विचार रखती है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 5 जनवरी, 1980 में प्रकाशित हुई संस्कृतिक विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना संख्या का० आ० 40 दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् एक मास के अन्दर कथित क्षेत्रों में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी आपत्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	निषिद्ध घोषित किए जाने वाले राजस्व प्लाटों की संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	निषिद्ध घोषित किए जाने वाले क्षेत्र में यदि कोई आधुनिक संरचना हो तो उसका विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कर्नाटक	हासन	चेन्नराय पटना	श्रवण बेलगोला गांव	गोमतेश्वर प्रतिमा	ग्राम श्रवण बेल गोला	(हेक्टयर में)	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 162	2.214	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 164	1.678	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 171	1.922	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 172	1.922	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 173	0.960	प्राइवेट	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 174	3.267	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 175	1.598	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 247	5.389	प्राइवेट सरकारी आंशिक तौर पर गैर सरकारी व्यक्तियों को आवंटित	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 248	0.687	—वही—	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 249	0.272	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 250	2.053	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 251	4.248	सरकारी (चरा गाह)	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 252	1.740	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 253	0.920	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 254	1.112	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 255	1.405	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 256	1.638	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 257	1.729	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 258	0.809	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 259	1.355	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 260	0.607	सरकारी	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 261	0.950	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 265	0.292	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 267	0.566	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 268	1.608	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 269	0.526	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 270	0.505	सरकारी	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 272	0.920	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 273	1.598	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 274	5.179	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 275	2.731	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 276	1.740	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 277	1.214	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 278	3.905	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 280	15.215	सरकारी, आंशिक तौर पर गैर सरकारी व्यक्तियों को आवंटित	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 281	6.495	प्राइवेट	—	—

[सं० 2 ख/2/77-एम]

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 24th August, 1981

ARCHAEOLOGY

S.O. 2472.—Whereas the Central Government is of opinion that the areas near or adjoining the protected monument specified in the Schedule annexed hereto to be prohibited for purpose of mining operation or construction or both.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 31 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, and in supersession of the notification of the Department of Culture (Archaeological Survey of India), No. S.O. 40, dated the 18th December, 1979, published in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated the 5th January, 1980, the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said areas as prohibited.

Any objection made within one month after the issue of this notification by any person interested in the said area will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

S. No.	State	District	Tehsil	Locality	Name of Monument	Revenue plot number to be declared prohibited	Area	Ownership	Details of modern Structure, if any, in the area to be declared prohibited	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Karnataka	Hassan	Chennaraya patna	Sravanabelagola village	Gomateswara Statue	Village Sravanabelagola	(in Hectares)			
						Survey Plot No. 162	2.214	Private	..	..
						Survey Plot No. 164	1.678	Private	..	..
						Survey Plot No. 171	1.922	Private	..	..
						Survey Plot No. 172	1.922	Private	..	..
						Survey Plot No. 173	0.960	Private	..	..
						Survey Plot No. 174	3.267	Private	..	
						Survey Plot No. 175	1.598	Private	..	
						Survey Plot No. 247	5.389	Govt. partly allotted to private individual	..	..
						Survey Plot No. 248	0.687	—do—	..	..
						Survey Plot No. 249	0.272	Private	..	..
						Survey Plot No. 250	2.053	Private	..	..
						Survey Plot No. 251	4.248	Govt. (Grazing field)	..	..
						Survey Plot No. 252	1.740	Private	..	..
						Survey Plot No. 253	0.920	Private	..	..
						Survey Plot No. 254	1.112	Private	..	..
						Survey Plot No. 255	1.405	Private	..	..
						Survey Plot No. 256	1.638	Private	..	..
						Survey Plot No. 257	1.729	Private	..	..
						Survey Plot No. 258	0.809	Private	..	..
						Survey Plot No. 259	1.355	Private	..	..
						Survey Plot No. 260	0.607	Government	..	..
						Survey Plot No. 261	0.950	Private		
						Survey Plot No. 265	0.292	Private	..	..
						Survey Plot No. 267	0.566	Private	..	..
						Survey Plot No. 268	1.608	Private	..	..
						Survey Plot No. 269	0.526	Private	..	
						Survey Plot No. 270	0.505	Government	..	..
						Survey Plot No. 272	0.920	Private	..	..
						Survey Plot No. 273	1.598	Private	..	..
						Survey Plot No. 274	5.179	Private	..	..
						Survey Plot No. 275	2.731	Private	..	..
						Survey Plot No. 276	1.740	Private	.	..
						Survey Plot No. 277	1.214	Private	..	..
						Survey Plot No. 278	3.905	Private	..	..
						Survey Plot No. 280	15.215	Govt. partly allotted to private individuals	..	..
						Survey Plot No. 281	6.495	Private	..	..

[No. 2 B/2/77-M]

नई दिल्ली 31 अगस्त, 1981

(पुरातत्व)

का०आ० 2473—केन्द्रीय सरकार, यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित संस्मारक के समीप अथवा संलग्न क्षेत्रों को खदान-प्रक्रिया अथवा निर्माण अथवा दोनों के लिए निषिद्ध करने का विचार रखती है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 5 जनवरी, 1980 में प्रकाशित हुई संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं० 41, दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् एक मास के अन्दर कथित क्षेत्रों में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी आपत्ति पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	निषिद्ध घोषित किए जाने वाले राजस्व प्लाटों की संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	निषिद्ध घोषित किए जाने वाले क्षेत्र में यदि कोई आधुनिक संरचना हो तो उसका विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कर्नाटक	हासन	चेन्नराय पटना	जिनाथपुर तथा श्रवण बेलगोला गांव	चन्द्रगुप्त बस्ती	ग्राम जिनाथपुर	(हैक्टर में)			
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 58	0.171	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 59	0.474	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 60	1.202	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 61	0.384	सरकारी	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 67	1.214	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 69	6.120	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 68 (पूर्व संरक्षित क्षेत्र को छोड़कर)	21.253	सरकारी (चारा-गाह)	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 71 ग्राम श्रवण बेलगोला .	2.741	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 308	10.288	सरकारी आंशिक तौर पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को आवंटित		
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 309	1.214	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 310	1.365	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 315	2.420	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 316	0.980	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 318	1.365	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 320	2.680	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 321	0.474	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 322	0.616	प्राइवेट	—	—
						सर्वेक्षण प्लाट सं० 324 (पूर्व संरक्षित क्षेत्र तथा तालाब को छोड़कर)	37.231	सरकारी, आंशिक तौर पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को आवंटित	—	—

[सं० 2ख/2/77-एम०]

डा० (श्रीमती) देबला मित्रा, पदेन संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 24th August, 1981

(Archaeology)

S.O. 2473.—Whereas the Central Government is of opinion that the areas near or adjoining the protected monument specified in the Schedule annexed hereto to be prohibited for purpose of mining operation or construction or both.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 31 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, and in supersession of the notification of the Department of Culture (Archaeological Survey of India), No. S.O. 41, dated the 18th December 1979, published in the Gazette of India, Part II—Section 3, Subsection (ii) dated the 5th Janunary 1980, the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said areas as prohibited.

Any objection made within one month after the issue of this notification by any person interested in the said area will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue Plot number to be declared prohibited	Area	Ownership	Details of modern structures, if any in the area to declared prohibited	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Karnataka	Hassan	Channa-rayapatna	Jinnatpur and Sravanabelagola Villages	Chandragupta Basti	Village Jinnatpur	(in Hectares)			
						Survey Plot No. 58	0.171	Private	..	..
						Survey Plot No. 59	0.474	Private	..	..
						Survey Plot No. 60	1.202	Private	..	..
						Survey Plot No. 61	0.384	Government	..	..
						Survey Plot No. 67	1.214	Private	..	..
						Survey Plot No. 69	6.120	Private	..	..
						Survey Plot No. 68 (excluding the area already under protection)	21.253	Government (Grazing field)	..	..
						Survey Plot No. 71	2.741	Private	..	..
						Village Sravanabelagola				
						Survey Plot No. 308	10.288	Government, partly allotted to private individuals	..	..
						Survey Plot No. 309	1.214	Private	..	..
						Survey Plot No. 310	1.365	Private	..	..
						Survey Plot No. 315	2.420	Private	..	..
						Survey Plot No. 316	0.980	Private	..	..
						Survey Plot No. 318	1.365	Private	..	..
						Survey Plot No. 320	2.680	Private	..	..
						Survey Plot No. 321	0.474	Private	..	..
						Survey Plot No. 322	0.616	Private	..	..
						Survey Plot No. 324 (excluding the area already protected and the tank)	37.231	Government, partly allotted to private individual	..	..

[No. 2B/2/77-M]

DR. Mrs. D. MITRA, Ex-offico Joint Secretary and Director General, Archaeological Survey of India

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1981

का०आ० 2474—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 5 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुपूरक नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं।

संक्षिप्त नाम और लागू होना—अनुपूरक नियम, भाग 8 का० नि० 317 प्रभाग XXVI सी०सी० आई०।

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास-स्थान आवंटन (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं—का० नि० 371....खख—2 इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'आवंटन' से, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी निवास स्थान को अधिभोग में रखने के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है;

(ख) 'आवंटन' वर्ष से पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो मंडल अधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए परन्तु किसी भी दशा में कोई आवंटन वर्ष दो वर्षों से अधिक का नहीं होगा।

(ग) 'मंडल अधिकारी' से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या (विद्युत) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सहायक कार्यपालक इंजीनियर या अधीक्षण इंजीनियर भी है।

(घ) 'महानिदेशक (संकर्म)' से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का महानिदेशक (संकर्म) अभिप्रेत है और 'मुख्य इंजीनियर' से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर (सिविल) और (विद्युत) अभिप्रेत हैं।

(ङ) 'पात्र कार्यालय' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यालयों के लिए आशयित वास-सुविधा की दशा में सम्बद्ध नगर में अवस्थित लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यालय;

(ii) पूछताछ कार्यालय या पूछताछ कार्यालयों के समूहों के अनिवार्य अनुरक्षण कर्मचारिवृन्द के लिए उपलभ्य वास-सुविधा की दशा में, उस कार्यालय या कार्यालय-समूह में कार्यरत कर्मचारिवृन्द और जो सरकार द्वारा वास-सुविधा के आवंटन के प्रयोजन के लिए अनिवार्य अधिसूचित किए गए हैं;

(iii) विमान-क्षेत्रों में उपलभ्य वास-सुविधा की दशा में सम्बद्ध विमान क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारिवृन्द;

(iv) विनिर्दिष्ट संनिर्माण संकर्मों के लिए उपलभ्य वास-सुविधा की दशा में ऐसे संनिर्माण संकर्मों में नियोजित कर्मचारिवृन्द;

(v) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारिवृन्द की दशा में उस केन्द्र में कार्यरत सभी निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारिवृन्द;

(च) (1) "उपलब्धियों' से मूल नियम 45ग में यथापरिभाषित उपलब्धियां अभिप्रेत हैं परन्तु इसमें प्रतिकारात्मक भत्ते सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण : निलम्बित अधिकारी की दशा में 'उपलब्धियों' से वे उपलब्धियां मानी जाएंगी जो उसने उस आवंटन वर्ष के पहले दिन प्राप्त की हैं जिसमें वह निलम्बित किया गया है अथवा यदि वह आवंटन वर्ष के पहले दिन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस तारीख से ठीक पहले प्राप्त की गई है।

(छ) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, पत्नी अथवा पति और संतान, सौतेली संतान, वैध रूप से दत्तक ली गई संतान, माता-पिता, भाई अथवा बहनें, जो सामान्यतया अधिकारी के साथ निवास करते हैं और जो उस पर आश्रित हैं;

(ज) "सरकार" से, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(झ) अधिकारी का०नि० 327-खख-5 के उपबन्धों के अधीन जिस प्रकार के निवास स्थान का पात्र है, उसके संबंध में अधिकारी की "पूर्विकता तारीख" से वह पूर्वतन तारीख अभिप्रेत है जब से वह, छुट्टी की अवधि के सिवाय, निरन्तर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्यत्र सेवा के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है जो किसी विशिष्ट टाइप अथवा किसी उच्चतर टाइप के आवंटन के लिए सुसंगत है :—

परन्तु टाइप ए०बी०सी०डी० के निवास स्थानों के संबंध में, वह तारीख जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में, जिसमें विदेश सेवा की अवधि भी है, निरन्तर रहा है, उसकी उस टाइप के लिए पूर्विकता तारीख होगी :

परन्तु यह और कि जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो वहां उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की रकम से अवधारित की जाएगी। अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी, और जहां उपलब्धियां समान है वहां ज्येष्ठता सेवा काल की दीर्घता के अनुसार अवधारित की जाएगी—

(ञ) "अनुज्ञप्ति फीस" से इन नियमों के अधीन आवंटित निवास-स्थान के संबंध में मूल नियम के उपबन्धों के अनुसार मासिक रूप से देय धनराशि अभिप्रेत है;

(ट) "निवास स्थान" से ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत है जो तत्समय मंडल अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में है;

(ठ) "शिकमी देने" के अन्तर्गत किसी आवंटिती द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर अथवा उसके बिना, वास-सुविधा का सहभोग करना भी है।

स्पष्टीकरण—आवंटिती द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ वास-सुविधा का सहभोग शिकमी देना नहीं समझा जाएगा;

(ड) "स्थानांतरण" से उस स्टेशन या पद से, जहां अधिकारी कार्य कर रहा है, किसी अन्य स्टेशन या उस स्टेशन के किसी ऐसे पद पर स्थानांतरण अभिप्रेत है जिसके लिए अधिकारी के अधिभोग में का स्थान आशयित नहीं है और इसके विपर्ययेन स्थानांतरण इसमें सम्मिलित है;

(ढ) किसी अधिकारी के संबंध में "टाइप" से निवास स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है जिसका वह अनु०नि० 317-खख-5 के अधीन पात्र है।

(ण) "लगी हुई नगरपालिका" से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगरपालिका से लगी हुई है;

(त) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के सम्बन्ध में 'मकान' से ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो और जो स्थानीय नगरपालिका या किसी लगी हुई नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित हो।

स्पष्टीकरण—किसी भवन का कोई भाग जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए इस बात के होते हुए भी मकान समझा जाएगा कि उसका कोई भाग अनिवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है;

(च) किसी अधिकारी के संबंध में 'स्थानीय नगरपालिका' से वह नगरपालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उस अधिकारी का कार्यालय स्थित है ;

(छ) किसी अधिकारी के संबंध में 'कुटुम्ब के सदस्य' से यथास्थिति, पति-पत्नी या अधिकारी की उस पर आश्रित सन्तान अभिप्रेत है;

(ज) "नगरपालिका" के अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका समिति या बोर्ड, टाउन एरिया समिति, नोटिफाइड एरिया समिति और छावनी बोर्ड आते हैं।

लागू होना :—

ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के क्वार्टरों को लागू होंगे :—

(1) पूछताछ कार्यालयों में नियोजित कर्मचारिवृन्द को आवंटन के लिए मंडल अधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध क्वार्टर;

(2) विमान क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए नियोजित कर्मचारिवृन्द को आवंटन के लिए मंडल अधिकारी के नियंत्रण में उपलब्ध क्वार्टर;

(3) सन्निर्माण कार्य को सुकर बनाने के लिए मंडल अधिकारी के नियंत्रण में उपलब्ध क्वार्टर;

(4) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन अन्य क्वार्टर;

पति और पत्नी को आवंटन, अ० नि० 317—ख—4 :

(1) किसी अधिकारी को, यथास्थिति, जिसकी पत्नी या जिसके पति को पहले ही निवास स्थान आवंटित किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन कोई निवास स्थान तब तक आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता :—

परन्तु यह उपनियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं।

(2) जहां दो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन पृथक रूप से आवंटित निवास स्थानों के अधिभोगी हैं, एक दूसरे से विवाह कर लें वहां वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से एक अभ्यर्पित कर देंगे।

(3) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण उपनियम (2) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता तो निम्नतर टाइप* के निवास स्थान का आवंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा और यदि निवास स्थान एक ही टाइप के हैं तो मंडल अधिकारी के विनिश्चयानुसार उनमें से एक का आवंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा।

(4) उपनियम (1) से (3) तक में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यदि, यथास्थिति, पत्नी या पति को, जो इन नियमों के अधीन निवास स्थान का आवंटिती है, ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते एक ही स्टेशन पर बाद में निवास स्थान संबंधी कोई वास-सुविधा आवंटित कर दी जाती है तो यथास्थिति पत्नी या पति ऐसे आवंटन के एक मास के भीतर इन निवासस्थानों में से कोई एक अभ्यर्पित कर देगा :

परन्तु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं;

(ख) जहां दो अधिकारी, जो एक ही स्टेशन पर ऐसे पृथक निवास स्थानों के अधिभोगी हैं जिनमें से एक निवास स्थान इन नियमों के अधीन आवंटित किया गया है और दूसरा ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते, एक दूसरे से विवाह कर लें, वहां उनमें से कोई भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से किसी एक को अभ्यर्पित कर देगा;

(ग) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण (क) या खंड (ख) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूल में के निवास स्थान का आवंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा।

निवास स्थानों का वर्गीकरण अ०नि० 317—ख— 5 :

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारणतया कोई अधिकारी नीचे दी गई सारणी में दर्शित टाइप के निवास स्थान के आवंटन का पात्र होगा :—

निवास-स्थान का टाइप	उस आवंटन वर्ष के पहले दिन, जिसमें आवंटन किया जाता है, अधिकारी का प्रवर्ग या उसकी मासिक उपलब्धियां
ए	260 रुपए से अधिक
बी	500 रुपए से कम किन्तु 260 रुपए से कम नहीं
सी	1000 रुपए से कम किन्तु 500 रुपए से कम नहीं
डी	1500 रुपए से कम किन्तु 1000 रुपए से कम नहीं
ई	1500 रुपए और उससे अधिक

आवंटन के लिए आवेदन—अ०नि०—317—ख—6

(1) ऐसे अधिकारी को, जो निवास स्थान का आवंटन चाहता है या उस निवास स्थान के आवंटन को जारी रखना चाहता है जो उसे आवंटित किया गया, मंडल अधिकारी को आवंटन वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के 15 दिसम्बर के पूर्व या जब उसे ऐसा करने के लिए वह निदेश दे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसी तारीख तक इस निमित्त आवेदन करना चाहिए जो मंडल अधिकारी द्वारा विहित की जाए।

(2) नए नियुक्त किए गए अधिकारियों या स्थानांतरण पर आने वाले अधिकारियों की बाबत, कलैंडर मास की 20वीं तारीख तक प्राप्त आवेदन-पत्र पर, पश्चातुवर्ती मास में विचार किया जाएगा।

निवास स्थान का आवंटन और प्रत्यावर्तनाएं—317—ख—7

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय से सम्बद्ध निवास स्थान, विमान क्षेत्रों और सन्निर्माण स्थलों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारीवृन्द के लिए अलग रखे गए क्वार्टर अनिवार्य कर्मचारीवृन्द के लिए आरक्षित समझे जाएंगे और अ०नि० 317—ख—9 के अधीन अनुज्ञात प्रतिधारण की अवधि के होते हुए भी अधिभोगी को उसके स्थानांतरण आदि पर, जैसे ही उसका उत्तरवर्ती ड्यूटी पर आने की रिपोर्ट करता है या लोक सेवा के हित में वह क्वार्टर उसके प्रवर्ग के किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाता है, ऐसा क्वार्टर खाली करना होगा।

(सम्पदा निदेशालय का०ज्ञा० सं० 2/52/64-एसीसी ता० 20 मार्च, 1965 के उपबंध ऐसे आरक्षित वास-सुविधा के प्रतिधारण को विनियमित करेंगे)।

(क) पूछताछ कार्यालय से सम्बद्ध निवास-स्थान नियमित और निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारीवृन्द जो किसी पूछताछ कार्यालय से सम्बद्ध हैं या किसी पूछताछ कार्यालय पर अधिकारिता रखने हैं उस पूछताछ कार्यालय से सम्बद्ध निवास-स्थानों के आवंटन के लिए पात्र होंगे। मंडल अधिकारी किसी विशेष पूछताछ अधिकारी के लिए, निम्नलिखित प्रवर्गों में से कर्मचारीवृन्द के प्रवर्ग का विनिश्चय करेगा जिसके लिए उस टाइप का जिसका वह हकदार है या निम्नतर टाइप का एक-एक आवास अलग रखा जा सकेगा :—

(i) सहायक इंजीनियर (सिविल)
(ii) कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत)
(iii) सहायक इंजीनियर (विद्युत)
(iv) कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)
(v) सीवरमैन या झाड़ूकश
(vi) लिफ्ट मैकेनिक
(vii) वायर मैन या सहायक वायरमैन
(viii) नलसाज या सहायक नलसाज
(ix) पम्प चालक या सहायक पम्पचालक
(x) खलासी या बेलदार

यदि कर्मचारीवृन्द में से चयन किए गए प्रवर्ग के एक से अधिक व्यक्ति सरकारी निवास-स्थान के हकदार हैं तो आवंटन उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसकी उस प्रवर्ग में सबसे पहले की पूर्विकता हो। यदि कोई व्यक्ति पूर्वोक्त रीति में प्रस्थापित आवंटन स्वीकार नही करता है तो निवास-स्थान उस व्यक्ति को प्रस्थापित किया जाएगा जिसकी उस प्रवर्ग में उसके बाद की पूर्विकता तारीख होगी।

यदि मंडल अधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित पूर्विकता की अपेक्षाओं को पूरी करने के पश्चात् कोई निवास स्थान उपलब्ध है तो वे पूछताछ कार्यालय से सम्बद्ध अथवा उस पूछताछ कार्यालय पर अधिकारिता रखने वाले कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को उनकी पूर्विकता के अनुसार आवंटित कर दिए जाएंगे।

(ख) विमान क्षेत्रों से सम्बद्ध निवास स्थानों की दशा में आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो उप पैरा (क) में है।

(ग) सन्निर्माण कर्मचारीवृन्द के लिए अलग रखे गए निवास-स्थान के आवंटन में कर्मचारीवृन्द के निम्नलिखित प्रवर्गों को अधिमानता दी जाएगी :—

(i) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)
(ii) कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत)
(iii) सहायक इंजीनियर (सिविल)
(iv) सहायक इंजीनियर (विद्युत)
(v) कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)
(vi) कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत)
(vii) उपमंडल लिपिक
(viii) मोटर लारी ड्राइवर

(घ) वे व्यक्ति जिन्हें उप पैरा (क), (ख) और (ग) में यथा वर्णित अनिवार्य कर्मचारीवृन्द के लिए आशयित निवास स्थान आवंटित किए जाते हैं, यह लिखित वचन देंगे कि वे जब कभी उनसे ऐसी अपेक्षा की जाए, अपने सामान्य कार्य के घंटों के अतिरिक्त आपात ड्यूटी भी करेंगे। सामान्य कार्य घंटे के अतिरिक्त आपात ड्यूटी करने में असफल रहने पर सरकारी निवास स्थान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

(ङ) अन्य उपबन्धों के होते हुए भी, यदि आवंटन प्राधिकारी किसी प्रक्रम पर यह समझता है कि आवंटिती सरकारी सेवक की सेवाएं पूछताछ कार्यालयों निर्माण स्थलों, विमानक्षेत्रों में अनिवार्य नहीं हैं अथवा यदि आवंटिती ने अवधार किया है या ड्यूटी की उपेक्षा की है तो आवंटन, आनुकल्पिक निवास-स्थान की व्यवस्था किए बिना, रद्द किया जा सकेगा।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, किसी निवास स्थान के खाली होने पर वह मंडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना उस व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा जो अ०नि० 317-खण्ड-5 के अधीन उसी टाइप में परिवर्तन चाहता है और यदि उपलब्धता के लिए वह अपेक्षित नहीं है तो उस टाइप में बिना वास-सुविधा वाले उस आवेदक को जिसको उस निवास स्थान के टाइप में सबसे पहले की पूर्विकता हो, आवंटित किया जाएगा, परन्तु यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :—

(i) मंडल अधिकारी आवेदक को उस टाइप के निवास स्थान से उच्चतर टाइप का निवास स्थान आवंटित नहीं करेगा जिसका वह अ०नि०खण्ड-5 के अधीन पात्र है।

(ii) मंडल अधिकारी किसी आवेदक को उस टाइप से निम्नतर टाइप का निवास स्थान स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसका वह अ०नि० 317-खण्ड-5 के अधीन पात्र है।

(iii) मंडल अधिकारी आवेदक द्वारा निम्नतर प्रवर्ग के निवास स्थान के आवंटन के लिए अनुरोध करने पर उसे, उसकी पूर्विकता की तारीख के आधार पर उस टाइप से ठीक नीचे के टाइप का निवास स्थान आवंटित कर सकेगा जिसके लिए वह अ०नि० 317 खण्ड-5 के अधीन पात्र है।

(3) मंडल अधिकारी अनारक्षित निवास-स्थान की दशा में भी किसी अधिकारी का विद्यमान आवंटन, यदि अधिकारी के अधिभोग में के निवास स्थान को खाली कराया जाना अपेक्षित है तो, रद्द कर सकता है और उसे उसी टाइप का अनुकल्पिक निवास स्थान आवंटित कर सकता है और आपात दशा में अधिकारी के अधिभोगाधीन निवास स्थान के टाइप से ठीक नीचे के टाइप का अनुकल्पिक निवास स्थान आवंटित किया जा सकता है।

(4) खाली निवास स्थान, उपनियम (1) के अधीन किसी अधिकारी को आवंटित किए जाने के अतिरिक्त, एकही समय में यदि इस बात की आशंका है कि आवंटिती अधिकारी आवंटन को स्वीकार नहीं भी कर सकता है तो पात्र अधिकारियों को भी उनकी पूर्विकता के क्रम से प्रस्थापित किया जा सकेगा। आवंटन या प्रस्थापना का स्वीकार न किया जाना अथवा आवंटित निवास स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में न लेना-अनु०नि० 317-खण्ड-8 :—

(1) यदि कोई अधिकारी किसी निवास-स्थान का आवंटन, आवंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है अथवा स्वीकार करने के बाद भी आठ दिन के भीतर उस निवास-स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो वह उस आवंटन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे आवंटन का पात्र न होगा।

(2) यदि किसी अधिकारी को, जिसके अधिभोग में किसी निम्नतर टाइप का निवास स्थान है, ऐसे टाइप का निवास-स्थान आवंटित या प्रतिस्थापित किया जाता है जिसके लिए वह अनु० नि. 317-ख ख 5 के अधीन पात्र है या जिसके लिए उसने अनु० नि० 317 खण्ड 6 (1) (iii) के अधीन आवेदन किया है तो ऐसे, उक्त आवंटन को या आवंटन की प्रस्थापना को अस्वीकार कर देने पर, पूर्वतन आवंटित निवास-स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात :—

(क) ऐसा अधिकारी उस आवंटन वर्ष की शेष अवधि, तक, जिस वर्ष में उसने आवंटन या प्रस्थापना से इंकार किया है, दूसरे आवंटन के लिए पात्र नही होगा :

(ख) वर्तमान निवास-स्थान रखे रहने के दौरान उस पर वही अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी जो उसे भू०नि० 45-क के अधीन इस प्रकार आवंटित या प्रस्थापित निवास-स्थान के लिए संदत्त करनी पड़ती अथवा वह अनुज्ञप्ति

फीस जो उस निवास-स्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, दोनों में से जो भी अधिक हो।

आबंटन प्रभावी रहने की अवधि और तत्पश्चात कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि अनु० नि० 317-ख ख 9 :

(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि—

(क) अधिकारी के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्यारूढ़ न रह जाने के पश्चात् वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उपखण्ड (2) के अधीन अनुज्ञेय है ;

(ख) आबंटन मंडल अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता ;

(ग) सम्यक सूचना देकर अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता ;

(घ) अधिकारी निवास-स्थान का अधिभोग समाप्त नहीं कर देता।

(2) अधिकारी उसे आबंटित निवास-स्थान को उपनियम (3) पैरा (5) के अधीन रहते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उस अवधि पर्यन्त, अपने पास रख सकता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है : परन्तु यह तब जब कि वह निवास-स्थान उस अधिकारी या उस कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो।

घटनाएं	निवास-स्थान पर कब्जा बनाए रखने की अनुज्ञेय अवधि
1	2
(i) पद त्याग/पदच्युति या सेवा से हटाया जाना पूर्व सेवा का पर्यवासन अथवा बिना अनुज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति	एक मास
(ii) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	दो मास
(iii) आबंटित की मृत्यु	चार मास
(iv) सम्बद्ध नगर से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	दो मास
(v) किसी ऐसे कार्यालय को स्थानान्तरण जो इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के लिए पात्र नहीं है	दो मास
(vi) भारत से अन्यत्र सेवा पर जाना	दो मास
(vii) भारत में अस्थायी स्थानान्तरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	चार मास
(viiiक) छुट्टी (जो निवृत्ति पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)	छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु चार मास से अधिक नहीं।
(ख) प्रसूति छुट्टी	प्रसूति छुट्टी तथा उसी क्रम में मंजूर की गई छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु इस शर्त के अधीन रहते हुए कि यह पांच मास से अधिक नहीं होगी।
(ix) निवृत्ति-पूर्व छुट्टी या मू०नि० 86 के अधीन दी गई अस्वीकृत छुट्टी अथवा ऐसे सरकारी सेवकों को दी गई अर्जित छुट्टी जो मू०नि० 56-ञ के अधीन सेवा निवृत्त होते हैं	पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त किन्तु निवृत्ति पूर्व-छुट्टी के मामले में 180 दिन और अन्य मामलों में चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, इस में सेवा निवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि भी सम्मिलित है।
(x) भारत में या भारत से बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी	(क) यदि अधिकारी के अधिभोग में ऐसा कोई आवास है जो उस वास स्थान से निम्नतर टाइप का है, जिसका वह हकदार है तो अध्ययनार्थ छुट्टी की पूरी अवधि के लिए। (ख) यदि अधिकारी के अधिभोग में ऐसा कोई आवास है जो उस टाइप का है जिसका वह हकदार है तो, छह मास से अनधिक की अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि के लिए : परन्तु जहां अध्ययनार्थ छुट्टी छह मास से बढ़ जाती है वहां, उसमें छह मास के अवसान पर, या अध्ययनार्थ छुट्टी के प्रारम्भ की तारीख से, यदि वह ऐसा चाहे तो, उस वास-स्थान से, जिसका वह हकदार है, एक टाइप नीचे का वैकल्पिक स्थान आबंटित किया जा सकता है।
(xi) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए, परन्तु छह मास से अधिक नहीं।
(xii) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त।
(xiii) प्रशिक्षणार्थ जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यन्त।

टिप्पण : सरकारी आवास का कब्जा बनाए रखने की उक्त रियायती अवधि उस दशा में उपलब्ध नहीं होगी जब कोई क्वार्टर सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट पद के लिए अलग रखा जाता है।

स्पष्टीकरण : सारणी के मद (iv) और (v) के सामने उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि, कार्यभार त्यागने की तारीख से और उस अधिकारी को नया पद-ग्रहण करने से पूर्व मंजूर की गई और उसके द्वारा उपभोग की गई छुट्टी की अवधि यदि कोई हो, से संगणित की जाएगी : परन्तु यह सारणी में यथास्थिति मद (vi) या (ix) के अधीन उपबन्धित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए होगी।

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन किसी निवास-स्थान का कब्जा बनाए रखा जाता है तो आबंटन अनुज्ञेय रियायती अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा जब तक कि उसके अवसान पर तुरन्त अधिकारी उस स्थान पर किसी पात्र कार्यालय में कार्य पुनः आरंभ न कर दे।

(4) जब कोई अधिकारी बिना वेतन और भत्तों के चिकित्सा छुट्टी पर है तो वह उपनियम (2) के नीचे सारणी के मद (xii) के अधीन रियायत के आधार पर अपने निवास-स्थान का कब्जा बनाए रख सकता है :

परन्तु यह तब जब वह ऐसे निवास-स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नकद भेजता रहता है और ऐसी फीस दो मास से अधिक तक न भेजने की दशा में आबंटन रद्द हो जाएगा।

(5) वह अधिकारी जिसने उपनियम (2) के नीचे की सारणी की मद (i) और मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर निवास-स्थान का कब्जा बनाए रखा है, वह किसी पात्र कार्यालय में उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः नियोजित हो जाने पर, इस बात का हकदार होगा कि उस निवास स्थान का कब्जा बनाए रखे और वह इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के और किसी आबंटन का भी पात्र हो जाएगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसे पुनर्नियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियां उसे उस टाइप के क्वार्टर के लिए जिसका अधिभोग वह कर रहा है, हकदार नहीं बनाती है तो वह निम्नतर टाइप के निवास-स्थान के लिए आवेदन करेगा।

उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (4) या उपनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकारी पदच्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है या जब उसकी सेवा पर्यवसित की जाती है और उस विभाग के प्रधान का, जिसमें वह अधिकारी, वैसी पदच्युति, हटाए जाने या समापन के ठीक पूर्व नियोजित था, यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह मंडल अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस अधिकारी को किए गए निवास-स्थान का आबंटन या तो तुरन्त रद्द कर दे या उस तारीख से रद्द कर दे जो उपनियम (2) के नीचे की सारणी के मद (i) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्वतर है और जो वह विनिर्दिष्ट करे तथा मंडल अधिकारी तदनुसार कार्रवाई करेगा।

निवास-स्थान का खाली किया जाना अ०नि० 317-खण्ड-10 :

(1) क्वार्टर का खाली कब्जा आबंटिती सरकारी सेवक द्वारा कनिष्ठ इंजीनियर को या सहायक इंजीनियर को यदि उन क्वार्टरों के अनुरक्षण से सम्बद्ध कनिष्ठ इंजीनियर को ही स्वयं खाली कब्जा देना है, जो इन नियमों के अधीन विहित समय के भीतर दिया जाएगा।

(2) यदि किसी आबन्टन को रद्द कर दिया जाने या इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के अधीन रद्द समझे जाने के पश्चात् निवास-स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आबन्टित किया गया था या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में रहता है या रहा है, तो वह अधिकारी निवास-स्थान के उपयोग और अधिभोग के लिए नुकसानियों का संदाय करने का दायी होगा, जो उस दांडिक अनुज्ञप्ति फीस के बराबर होगी जो सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अवधारित की जाए। अनुज्ञप्ति फीस से सम्बन्धित उपबन्ध—अ० नि० 317 खण्ड-11

(1) जब वास-सुविधा या अनुकल्पिक वास-सुविधा का आबन्टन स्वीकार कर लिया जाए तो अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से अथवा आबन्टन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा।

कोई अधिकारी जो आबन्टन स्वीकार करने के पश्चात् उस वास-सुविधा का कब्जा आबन्टन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर नहीं लेता उससे उस तारीख से बारह दिन की अवधि तक अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी।

(2) जहां किसी अधिकारी को जो एक निवास-स्थान का अधिभोगी है दूसरा निवास-स्थान आबन्टित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास-स्थान का आवन्टन नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा। तथापि, निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास-स्थान को उस दिन तथा उसके बाद के एक दिन तक, बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए, अपने पास रख सकता है।

(3) ऐसे अधिकारी, जिनके पास अपना मकान है या वे अधिकारी जिनको आबन्टन हो जाने के पश्चात् मकान का स्वामित्व मिल गया है और जो सरकारी निवास-स्थान का अधिभोग कर रहे हैं, उतनी अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर की जाये।

निवास-स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू दिया जाना—अनु० नि० 317-खण्ड 12 :

(1) वह अधिकारी जिसको निवास-स्थान का आबन्टन किया गया है उसकी अनुज्ञप्ति फीस तथा उस नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो और जो उस निवास-स्थान की अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग या सेवा-व्यवस्था को उस अवधि के दौरान हो, जब निवास स्थान उसे आवन्टित कर दिया जाता है और उसे आबन्टित रहता है या, जहां आबन्टन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया गया है, वहां जब तक निवास-स्थान तथा उसमें सलग्न उपगृह खाली नहीं कर दिए जाते हैं और उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता है।

(2) जहां वह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आबन्टित किया गया है, न तो स्थायी सरकारी सेवक है और न स्थायीकृत, वहां वह प्रतिभू-सहित, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में, प्रतिभूति पत्र निष्पादित करेगा। यह प्रतिभू केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला स्थायी सरकारी सेवक होना चाहिए।

यह प्रतिभूति-पत्र अनुज्ञप्ति फीस तथा अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए होगा जो उस निवास-स्थान और अन्य सेवाओं की बाबत तथा उसके बदले में दिए गए किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हों।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रह जाता है तो अधिकारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित एक नया बन्धपत्र उस घटना या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगा, और यदि वह ऐसा न करे तो, जब तक कि मण्डल अधिकारी अन्यथा विनिश्चय न करे, उस निवास-स्थान का उसे आबन्टन उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

आबन्टन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि—अनु०नि० 317-खण्ड—13 :

(1) अधिकारी ऐसी सूचना दे कर, जो निवास-स्थान को खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व मण्डल अधिकारी के पास पहुंच जाए, किसी भी समय आबन्टन को अभ्यर्पित कर सकता है। निवास-स्थान का आबन्टन उस दिन के पश्चात् जिसको पत्र मण्डल अधिकारी को प्राप्त होता है, ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, रद्द किया गया समझा जाएगा। यदि अधिकारी सम्यक् सूचना न दे तो वह दस दिन की, अथवा दस दिन की सूचना देने में जितने दिन की कमी हो उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगी, परन्तु मण्डल अधिकारी कम अवधि की सूचना स्वीकार कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन निवास-स्थान अभ्यर्पित करने वाले अधिकारी के सम्बन्ध में, उसी स्टेशन पर सरकारी आवास-सुविधा का आबन्टन करने के लिए, ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

निवास-स्थान का परिवर्तन—अनु०नि० 317 खण्ड 14 :

(1) जिस अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आबन्टन किया गया है वह आवेदन कर सकता है कि उसको उसके बदले में उसी टाइप का अथवा उस टाइप का जिसका पात्र वह अनु० नि० 317 खण्ड 5 के अधीन है (जो भी निम्नतर हो), निवास-स्थान दिया जाए। किसी अधिकारी को आवन्टित एक टाइप के निवास-स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) परिवर्तन के लिए वे सभी आवेदन, जो मण्डल अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किए गये हों और किसी कलैण्डर मास के उन्नीसवें दिन तक प्राप्त हों, अगले मास की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, वे अधिकारी जिनके नाम पूर्ववर्ती मास की प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किए गए हैं, समुच्चयित रूप से उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती मास की सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। किसी विशिष्ट मास की सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम से अवधारित की जाएगी :

(3) परिवर्तन का अवसर उपनियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम से तथा अधिकारियों की अपनी पसन्द का यथासम्भव ध्यान रखते हुए दिया जाएगा :

परन्तु अधिवर्षिता की तारीख से ठीक छः मास पहले की अवधि के दौरान निवास के परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) यदि कोई अधिकारी निवास-स्थान के परिवर्तन की प्रस्थापना या आबन्टन जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर उसे स्वीकार नहीं करता तो उसके नाम पर, उस टाइप के निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(5) जो अधिकारी, निवास-स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता उससे ऐसे निवास स्थान के लिए अनु० नि० 317-खख 1 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी, जो उस निवास-स्थान के लिए, जो पहले ही उसके कब्जे में है, और जिसका आबन्टन बराबर बना रहेगा, मू० नि० 45-क के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त होगी।

कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु की दशा में निवास-स्थान का परिवर्तन अनु० नि० 317—खख 15 :

अनु०नि० 317-खख-14 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर करता है तो उसे निवास-स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकती है। परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास-स्थान में तथा उसी मंजिल पर होगा जिस टाइप का निवास-स्थान उस अधिकारी को पहले से आबन्टित है।

निवास-स्थानों का पारस्परिक विनियम अनु० नि० 317 खख 16 :

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास स्थान आबन्टित किए गए हैं, वे आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें अपने निवास-स्थानों का पारस्परिक विनियम करने की अनुज्ञा दी जाए। जब इस बात की उचित तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनियम के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह मास तक उसी स्थान में कर्तव्यारूढ़ रहेंगे और पारस्परिक रूप से विनियम में प्राप्त अपने निवास स्थानों में रहेंगे तब पारस्परिक विनियम की अनुज्ञा दी जा सकती है।

उन स्थानों के लिए स्थानान्तरण जहां कुटुम्ब नहीं रखा जा सकता—अनु० नि० 317 खख 17 :

यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी ऐसे स्थान को किया जाता है जहां उसे अपना कुटुम्ब साथ ले जाने के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञा नहीं दी जाती या सलाह नहीं दी जाती और इन नियमों के अधीन उसे आबन्टित निवासस्थान उसकी संतान को वास्तविक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित है तो उसे, प्रार्थना करने पर, अपनी संतान के चालू शैक्षणिक सत्र के अन्त तक मू०नि० 45-क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर निवास-स्थान रखने के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है। तथापि यह नियम आरक्षित आवास के मामले में लागू नहीं होता जिसमें मण्डल अधिकारी का आदेश का० ज्ञा० सं० 2/52/64-एसीसी 1 ता० 20 मार्च, 1965 आरक्षित आवास का कब्जा बनाए रखने को विनियमित करेगा।

निवास-स्थान का रख-रखाव—अनु० नि० 317-खख-18 :

(1) जिस अधिकारी का निवास-स्थान का आबन्टन किया गया है वह उसे और परिसरों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के समाधानप्रद रूप से साफ दशा में रखेगा। ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान से संलग्न किसी बाग, सहन या चार दिवारी में न तो सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष या झाड़ी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना काटेगा या छांटेगा। इस नियम के उल्लंघन में उगाये गए वृक्ष, पौधे या वनस्पति सम्बन्धित अधिकारी की जोखिम पर और उसके खर्च पर मण्डल अधिकारी या सम्बन्धित अन्य अधिकारी द्वारा हटवाए जा सकेंगे।

(2) आबन्टित परिसर या उसके आसपास मण्डल अधिकारी की अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

निवास-स्थान को शिकमी देना और सहभोग—अनु० नि० 317-खख-19 :

(1) कोई अधिकारी अपने को आबन्टित निवास-स्थान या उससे संलग्न उपगृहों, गैरजों और अस्तबलों का सहभोग इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के आबन्टन के पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ ही करेगा। सेवक-निवासों (या क्वार्टरों), उपगृहों और गैरेजों का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए, जिनके अन्तर्गत आबन्टिती के सेवकों का निवास भी है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी मण्डल अधिकारी अनुज्ञा दे।

(2) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास-स्थान को शिकमी नहीं देगा :

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास-स्थान में किसी अन्य अधिकारी को, जो सरकारी सुविधा का सहभोग करने के लिए पात्र है, देखभाल करने वाले के रूप में अ० नि० 317-खख-9 में विनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त, किन्तु छह मास से अधिक नहीं रख सकता है।

(3) जो अधिकारी अपने निवास-स्थान का सहभोग करे या उसे शिकमी दे वह ऐसा अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवास-स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिये और ऐसे किसी नुकसान के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा, जो निवास-स्थान को या उसकी सीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें की गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो। आबंटिती को उस दशा में सरकार द्वारा विनिश्चित नुकसानों का संदाय करना होगा जिसमें वह अनुज्ञा के बिना शिकमी पर (भागतः या पूर्णतः) देकर या सहभाग करके उसका दुरुपयोग करता है या निर्मिति संबंधी दुरुपयोग करता है।

(4) यदि आबंटिती द्वारा निवास के प्रयोजन के लिये आबंटित परिसर का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाता है तो यह आबंटन नियम का भंग होगा।

नियमों और शर्तों को भंग करने का परिणाम—अनु० नि० 317-खख-20

(1) यदि वह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है, अप्राधिकृत रूप से निवास-स्थान शिकमी देता है या सहभागी से अनुज्ञप्ति फीस ऐसी दर से लेता है जिसे मंडल अधिकारी अत्यधिक समझता है अथवा निवास-स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत निर्माण करता है अथवा निवास-स्थान या उनके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये करता है जिनके लिये वह अभिप्रेत है अथवा विद्युत या जल के कनेक्शन को बिगाड़ता है अथवा इन नियमों या आबंटन के निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है अथवा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें मंडल अधिकारी अनुचित समझे, निवास-स्थान या परिसर का उपयोग करता है या किये जाने की अनुज्ञा देकर नुकसान पहुंचाता है अथवा स्वयं ऐसा आचरण करता है या जो संपदा निदेशक की राय में उस अधिकारी के पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, अथवा आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी

आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझ कर देता है, तो मंडल अधिकारी, उस अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, निवास-स्थान का आवंटन रद्द कर सकता है । आवंटन उस दशा में भी रद्द किया जा सकेगा जब आवंटन प्राधिकारी की यह राय हो कि आवंटिती या उसके आश्रित का आचरण पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिकारी" पद के अन्तर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और ऐसे अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है ।

(2) यदि कोई अधिकारी उसे आवंटित निवास-स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपगृह, गैरेज को इन नियमों का उल्लंघन करके शिकमी देता है तो, ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उससे उतनी वर्धित अनुज्ञप्ति फीस ली जा सकेगी, जो मूल नियम 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुना से अधिक न हो । प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाये और किस अवधि के लिये वसूल की जाये, मंडल अधिकारी गुणा-गुण के आधार पर करेगा । इसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये जो मंडल अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाये निवास-स्थान का सहभोग करने से विवर्जित किया जा सकेगा ।

(3) जहां आवंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से शिकमी दिये जाने के कारण आवंटन को रद्द करने की कार्यवाई की जाती है वहां आवंटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर को खाली करने के लिये साठ दिन का समय दिया जायेगा। आवंटन परिसर खाली किये जाने की तारीख या आवंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर रद्द हो जायेगा ।

(4) जहां निवास-स्थान का आवंटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाय जो पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां, उस अधिकारी को मंडल अधिकारी के विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास-स्थान किसी अन्य स्थान में आवंटित किया जा सकेगा ।

(5) मंडल अधिकारी इस नियम के उपनियम (1) से (4) तक के अधीन सभी कार्यवाहियां या कोई कार्यवाई करने के लिये तथा ऐसे अधिकारी को, जो नियमों का तथा उसको जारी किये गये अनुदेशों को भंग करता है, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये वास-सुविधा के आवंटन के लिये अपात्र घोषित करने के लिये भी सक्षम होगा ।

(6) जहां इस नियम के अधीन कोई शास्ति अधीक्षण इंजीनियर या उससे नीचे पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाती है, वहां, व्यथित व्यक्ति शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेशों की अपने या अपने नियोजक द्वारा प्राप्ति के छब्बीस दिन के भीतर मुख्य इंजीनियर या महानिदेशक (संकर्म) को अभ्यावेदन कर सकेगा ।

(7) शास्ति अधिरोपित करने वाला मूल आदेश तब तक वैध रहेगा जब तक वह अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप उपान्तरित या विखंडित न हो जाये ।

आवंटन के रद्द किये जाने के पश्चात् निवास-स्थान में बने रहना—अनु० नि० 317-खख-21:

जहां कोई आवंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया जाता है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात् वह निवास स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आवंटित किया गया था या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना रहा है वहां ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान सेवाओं, फर्नीचर के उपयोग और अधिभोग के लिये उपनी नुकसानी और भाग-प्रभार का देनदार होगा जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित दंड अनुज्ञप्ति फीस के बराबर हो या उस अनुज्ञप्ति फीस का दोगुना जो वह संदत्त कर रहा था, इनमें से जो भी उच्चतर हो :

परन्तु किसी अधिकारी को उस निवास-स्थान को जो किसी विशेष पद के लिये अलग नहीं रखा जाता है, विशेष दशाओं में, मू० नि० 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से दोगुना या मू० नि० 45-क के अधीन पूल की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस से दोगुना, जो भी अधिक हो या उस अनुज्ञप्ति फीस का दोगुना, जो वह संदत्त कर रहा था, इनमें से जो भी उच्चतर हो, पर अनु० नि० 317-खख-9 के अधीन अनुज्ञात कालावधि से परे दो मास से अनधिक की कालावधि के लिये निवास-स्थान रखने के लिये मंडल अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

इन नियमों के जारी किये जाने के पहले किये आवंटनों का बना रहना अनु० नि० 317-खख 22 :

निवास-स्थान के किसी ऐसे विधि मान्य आवंटन के बारे में जो इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अस्तित्व में हो यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया आवंटन है भले ही वह अधिकारी जिसे वह आवंटन किया गया हो, उस टाइप का निवास-स्थान का हकदार न हो और उस आवंटन और उस अधिकारी के सम्बन्ध में इन नियमों के सभी पूर्वगामी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

नियमों का निर्वचन—अनु० नि० 317-खख-23 :

यदि इस प्रभाग के नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा ।

नियमों का शिथिलीकरण —अनु० नि० 317 खख-24 :

केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे इस प्रभाग के नियमों के सभी उपबन्धों को या उनमें से किसी को किसी अधिकारी या निवास-स्थान के मामले में या अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास-स्थानों के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर सकेगी ।

शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन—अनु० नि० 317-खख-25 :

केन्द्रीय सरकार इस प्रभाग के नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई शक्ति या सभी शक्तियां अपने नियंत्राधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें प्रत्यायोजित करना वह ठीक समझे ।

[एफ० सं० 28017/7/80/ई डब्लू 2]

जी० पी० ओहर, उप सचिव

प्रारूप आवंटन-पत्र

सं०

भारत सरकार आवंटन/तुरंत

के० लो० नि० वि० प्रभाग

सेवा में

———————

———————

प्रिय/महोदय/महोदया

पार्श्व में अंकित निवास-स्थान, 'केन्द्रीय नियम, 1981 के अधीन सरकारी निवास-स्थानों का आवंटन' के उपबंध के अनुसार आपको आवंटित किया जाता है । यह आवंटन उस अवधि के लिये किया जाता है जिसमें आप————————प्रभाग से संबद्ध रहते है और————————के रूप में————————अनुभाग/उप प्रभाग/प्रभाग के प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं ।

1. निवास स्थान की विशिष्टियां	2. टाइप
3. असुसज्जित निवास स्थान के बदले में	4. टाइप
5. सुसज्जित	

2. आप से अनुरोध है कि इस पत्र को जारी करने/प्राप्त करने की तारीख से पांच दिन के भीतर आप अपनी स्वीकृति भेज दें। स्वीकृति संलग्न प्रारूप में दो प्रतियों में होनी चाहिये और इसे अधोहस्ताक्षरी को (नाम से) सम्बोधित करके भेजा जाना चाहिये।

3. यदि पांच दिन की विहित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो आवंटन अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा और आपके मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

4. यदि आप अस्थायी सरकारी सेवक हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है। आप किसी स्थायी सरकारी से सेवक का प्रतिभूति बंध-पत्र अपनी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करें। बंध-पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये।

5. यदि आवंटन स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको सम्बद्ध के० लो० नि० वि० पूछताछ कार्यालय से इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर आवंटित निवास-स्थान का कब्जा ले लेना चाहिये। ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कब्जा लेने में असफल रहने की दशा में आपको आवंटन के आठवें दिन से अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करना होगा और आवंटन को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीय

कार्यपालक इंजीनियर

——— प्रभाग के० लो० नि० वि०

तारीख 19....

प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित

1. उप प्रभाग
2. रोकड़िया————प्रभाग/बिल सहायक।
3. लेखापाल————प्रभाग
4. अ० इं० परिक्षेत्र (सर्किल) को इसके अधीन प्राप्त अनुमोदन की तारीख से सूचनार्थ।
5. ले० ले० प०/सी एम कार्यालय।

प्रारूप स्वीकृति पत्र

सेवा में

कार्यपालक इंजीनियर

————प्रभाग

के० लो० नि० वि०

विषय : निवास-स्थान की स्वीकृति।

महोदय,

मैं आपके पत्र सं०..... ता०.....द्वारा मुझे आवंटित किये गये निवास स्थान सं०.....का आवंटन स्वीकार करता हूं। यह पत्र मुझे ता०.....को प्राप्त हुआ।

मेरी उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) वेतन ————

(ii) विशेष वेतन, यदि कोई हो ————

(iii) पेंशन, और मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान का पेंशन समतुल्य ————

(iv) मंहगाई वेतन, यदि कोई हो ————

(v) नगर प्रतिकारात्मक भत्ता ————

(vi) कोई अन्य भत्ता, जो मंहगाई भत्ता, सवारी भत्ता या मकान भाड़ा भत्ता आदि से भिन्न हो। ————

जोड़ ————

मैं केन्द्रीय सरकार का स्थायीकृत/स्थायी सेवक हूं। ————

मैं अस्थायी सरकारी सेवक हूं और मेरे प्रतिभू की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

(i) प्रतिभू का नाम

(ii) प्रतिभू का पदनाम

(iii) कार्यालय/मंत्रालय, जहां नियोजित है

संपदा निदेशालय या पुनर्वास विभाग या किसी अन्य सरकारी विभाग/स्वशासी निकाय/अर्ध सरकारी/पब्लिक उपक्रम कार्यालय द्वारा कोई भी अन्य सरकारी निवास स्थान मुझे या मेरी पत्नी/मेरे पति को आवंटित नहीं किया गया है।

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि नियुक्ति के स्थान पर मेरे अपने नाम से या मेरी पत्नी/मेरे पति या कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के नाम से मेरे स्वामित्व में कोई मकान या फ्लेट नहीं है। मैं यह भी वचन देता हूं कि जब मैं या मेरे कुटुम्ब का कोई सदस्य इस स्टेशन पर कोई मकान अर्जित करेगा तो, मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा।

यदि वर्तमान पद से मेरा स्थानांतरण हो जाता है तो साधारण पूल में या अन्यथा औपचारिक रूप से आवंटन का इंतजार किये बिना दो सप्ताह के भीतर मैं क्वार्टर खाली कर दूंगा।

मैंने के० लो० नि० वि० के नियंत्रणाधीन सरकारी निवास-स्थानों के आवंटन की ज्ञापत नियमों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और इन नियमों का पालन करने का करार करता हूं।

भवदीय

हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम/पद नाम/ता०

प्रतिभू बंधपत्र

मैं, श्री————जो श्री————

का पुत्र और इस समय————में————

के रूप में नियोजित हूं, श्री————द्वारा उस निवास स्थान के संबंध में, जो सरकार ने उसे अब आवंटित किया है तथा ऐसे अन्य निवास-स्थान, अतिरिक्त वास-सुविधा, अतिरिक्त सेवक क्वार्टर या गैरेज के लिये, जो सरकार उसे समय-समय पर आवंटित करे, अनुज्ञप्ति फीस और अन्य देय रकमों का भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) संदाय किये जाने के लिये प्रतिभू हूं (इसके अन्तर्गत मेरे वारिस, निष्पादक और प्रशासक भी हैं)।

मैं, अर्थात् प्रतिभू उस समय तक जब तक उसका खाली कब्जा सरकार को परिदत्त नहीं कर दिया जाता है, सभी हानि और नुकसान के लिये सरकार को क्षतिपूर्ति करूंगा। मैं, अर्थात् प्रतिभू सरकार द्वारा मांग की जाने पर तुरन्त तथा आपत्ति किये बिना ऐसी सब रकमों का सरकार को संदाय करने का वचनबद्ध करता हूं, जो सरकार को ऊपर बताये गये रूप में देय हों। मैं करार करता हूं जो सरकार उक्त रकमों को मुझे संदेय वेतन में से वसूल कर सकेगी (और सरकार ऐसा करने के लिये अप्रतिसंहरणीय रूप में प्राधिकृत होगी) इस प्रकार वसूल की जाने वाली रकम के बारे में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

मैंने जो बाध्यता स्वीकार की है वह सरकार द्वारा समय बढ़ाये जाने या उक्त श्री————(आवंटिती का नाम) के प्रति अन्य उदारता बरते जाने के कारण या किसी भी अन्य ऐसे विषय या ऐसी बात से न तो उन्मोचित होगी और न प्रभावित होगी, जिसका प्रतिभूओं से संबंधित विधि के अधीन प्रभाव, यदि यह उपबंध न होता तो मुझे मेरे ऐसे दायित्व से मुक्त करना होता।

यह प्रत्याभूति न तो मेरी मृत्यु से उन्मोचित होगी और न मैं सरकार की लिखित सहमति के बिना, तब तक किसी भी समय इसका प्रतिसंहरण कर सकूंगा जब तक कि ऐसे किसी निवास-स्थान, सेवक क्वार्टर या गैरेज का जो आबंटिती के अधीभोग में है, खाली कब्जा सरकार को परिदत्त नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु यह प्रत्याभूति उस तारीख से तथ्यतः समाप्त हो जायेगी जिस तारीख को श्री.....को भारत सरकार की किसी सेवा में स्थायी या स्थायीवत् घोषित किया जाता है ।

सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस दस्तावेज पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे सरकार देगी ।

नई दिल्ली में आज तारीख.....को उक्त.....ने इस पर हस्ताक्षर किये और परिदान किया ।
साक्षी के हस्ताक्षर.....

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

उसका पता..... पदनाम.....
और उसका व्यवसाय.....कार्यालय जिससे संलग्न है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रतिभू स्थायी सरकारी सेवक है उसकी आयु.....है और उसका वेतन.....रु० है ।

उस विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर, जिसके कार्यालय में प्रतिभू नियोजित है ।

तारीख :

कार्यालय स्टाम्प

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 31st August, 1981

S.O. 2474.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following additions to the Supplementary Rules, namely :—

Short title and application.—Supplementary Rules, Part VIII-S.R. 317 Division xxvi-BBI—

(1) These rules may be called the Allotment of Government Residence (Under the Control of the Central Public Works Department) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions—S.R. 317 — — :BB-2

In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) 'Allotment', means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(b) 'Allotment year' means the year beginning on the 1st January or such other period as may be notified by the Divisional Officer but in no case an allotment year shall extend beyond two years.

(c) 'Divisional Officer' means the Executive Engineer (Civil) or (Electrical) of the Central Public Works Department and includes an Assistant Executive Engineer or Superintending Engineer of the Central Public Works Department.

(d) 'Director General (Works)' means the Director General (Works) of the Central Public Works Department and Chief Engineer means the Chief Engineers (Civil) and (Electrical) of Central Public Works Department.

(e) 'Eligible Office' means,—

(i) in the case of accommodation meant for all offices of the Central Public Works Department, all offices of the Central Public Works Department located in the city concerned;

(ii) in the case of accommodation available for the essential maintenance staff of the enquiry office or groups of enquiry offices the staff working in that office or group of office and who are notified by the Government as essential for the purpose of allotment of accommodation;

(iii) in the case of accommodation available in aerodromes, the staff working in the aerodrome concerned;

(iv) in the case of accommodation available for specific construction works, the staff employed on such construction works;

(v) in the case of accommodation meant for work charged staff of Central Public Works Department all the work charged staff working at that station.

(f) 'emoluments' means the emoluments as defined in Fundamental Rules 45-C but excluding the compensatory allowances.

Explanation : In the case of an officer who is under suspension the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or if he is placed under suspension, on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments;

(g) 'family' means the wife or husband, as the case may be, and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters who ordinarily reside with and are dependent on the officer;

(h) 'Government' means the Central Government unless the context otherwise requires;

(i) 'priority date' of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible under provisions of S. R. 317 BB-5 means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant of a particular type or a higher type in a post under the Central Government or State Government or on foreign service except for periods of leave;

Provided that in respect of type A B C D residence the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government or State Government including the periods of foreign service shall be his priority date for that type;

Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments; and where the emoluments are equal, by the length of service;

(j) 'licence fee' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these Rules;

(k) 'residence' means any residence for the time being under the administrative control of the divisional Officer;

(l) 'subletting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person.

Explanation : Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting;

(m) 'temporary transfer' means a transfer which involves an absence for a period not exceeding four months;

(n) 'transfer' means a transfer from the station or post where the officer is working at any other station or any post at the station for which the accommodation in occupation of the officer is not intended and vice-versa;

(o) 'type' in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under Supplementary Rule 317 BB-5.

(p) "adjoining municipality" means any municipality contiguous to a local municipality ;

(q) 'house in relation to an officer or member of his family', means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.

Explanation : A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes;

(r) 'local municipality' in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;

(s) 'member of family' in relation to house owning officer means the wife or husband, as the case may be, or dependent child of the officer;

(t) 'municipality', includes a municipal corporation, municipal committee or board, a town area committee, a notified area committee, and contonment board.

Application : S.R. 317 — — B B—3

These rules shall apply to the following categories of quarters :—

(1) quarters available at the disposal of Divisional Officers for allotment to staff employed in enquiry offices;

(2) quarters available at the disposal of divisional officers for allotment to staff employed on the maintenance of aerodromes;

(3) quarters available at the disposal of divisional officers to facilitate construction works;

(4) other quarters under the Central Public Works Department.

Allotment to Husband and Wife, S.R. 317. B.B—4

(1) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered :

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judirial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall within one month of the marriage surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered as required under sub-rule (2), the allotment o fthe residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period, and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the Divisional Officer may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (3),—

(a) If a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any one of the residences within one month of such allotment :

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(b) Where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, any one of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage.

(c) If a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b), the allotment of the residence in the Central Public Works Department pool shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

Classification of Residences—S.R. 317 — B.B.5 —

Save as otherwise provided by these rules, an officer shall generally be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below :—

Type of residence.	Category of officer or his monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made.
	A. Less than Rs. 260.
	B. less than Rs. 500 but not less than Rs. 260.
	C. Less than Rs. 1,000 but not less than Rs. 500.
	D. Less than Rs. 1500 but not less than Rs. 1,000.
	E. Rs. 1,500 and above

Applications for Allotment—S.R. 317 B.B.—6

(1) An officer who seeks allotment of a residence or the continuance of allotment of a residence which has been allotted to him should apply in that behalf to the divisional officer before the 15th December of the year preceding the year of allotment or when directed to do so by him and in such form and manner and by such date as may be prescribed by the divisional officer.

(2) In respect of the newly appointed officers or those coming on transfer, applications received before the 20th day of the calender month shall be considered for allotment in succeeding month.

Allotment of Residences and Officers—S.R. 317 BB—7

(1) Residences attached to an enquiry office of the Central Public Works Department, residences earmarked for Central Public Works Department staff at aerodromes and the construction sites shall be deemed to be reserved for the essential staff and will have to be vacated by occupant on his transfer, etc. as soon as his successor reports for duty or other person of his category is allotted that quarter in the interest of public service, notwithstanding the period of retention allowed under S.R. 317—BB-9. (The provision of Directorate of Estates O.M. No. 2/52/64-ACC.I dated the 20th of the March, 1965 shall regulate retention of such reserved accommodation)—

(a) Residences attached to enquiry offices : The regular and work-charged staff who are attached to an enquiry office or have jurisdiction over an enquiry office shall be eligible for allotment of residences attached to that enquiry office. The divisional officer will decide for the particular enquiry officer, the categories of staff out of the following categories for which one residence each of the entitled or lower type of accommodation may be earmarked :—

(i) Assisstant Engineer (Civil)
(ii) Junior Engineer (Electrical)
(iii) Assistant Engineer (Electrical)
(iv) Junior Engineer (Clvil)
(v) Sewerman or Sweeper
(vi) Lift Mechanic
(vii) Wireman or Assistant Wireman
(viii) Plumber or Assistant Plumber
(ix) Pump Operator or Assistant Pump Operator
(x) Khalasi or Beldar.

If more than one person of the selected categories of the staff are eligible for allotment of Government residence, the allotment shall be made to the person with the earliest priority date in that category. If any person offered an allotment in the aforesaid manner does not accept the allotment, the residence shall be offered to a person with the next

priority date in the same category. If any residences are available after meeting the priority requirements as decided by the divisional officer, they shall be allotted to other members of staff attached to the enquiry office or having jurisdiction over that enquiry office in accordance with their dates of priority.

(b) In the case of residences attached to aerodromes, the procedure for allotment shall be the same as per sub-para (a).

(c) The following categories of staff shall have preferance in the allotment of residences earmarked for construction staff :—

(i) Executive Engineer (Civil)
(ii) Executive Engineer (Electrical)
(iii) Assistant Engineer (Civil)
(iv) Assistant Engineer (Electrical)
(v) Junior Engineer (Civil)
(vi) Junior Engineer (Electrical)
(vii) Sub-Divisional Clerk.
(viii) Motor Lorry Driver.

(d) Persons who are allotted residences which are meant for essential staff as mentioned in sub-paras (a), (b) and (c) shall give a written undertaking that they will attend to emergency duty outside their normal working hours whenever called upon to do so. Failure to attend to emergency calls outside normal duty hours will involve randelation of the allotment of the Government accommodation.

(e) Notwithstanding other provisions, allotment may be cancelled without providing alternative accommodation if the allotting authority at any stage considers that the services of the allottee Government servant is not essential at the enquiry offices, working sites and acrodromes, or in the case of misconduct or negligence of duty on the part of the allottee.

(2) Save as otherwise provided in these rules, a residence on falling vacant, will be allotted by the divisional officer preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type under the provisions of S.R. 317-BB-5 and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earilest priority date for that type of residence subject to the following conditions :—

(i) the divisional officer shall not allot a residence of a type higher than that to which the applicant is eligible under S.R. 317-BB-5.

(ii) the divisional officer shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than that to what he is eligible under S.R. 317-BB-5.

(iii) the divisional officer, on request from an applicant for allotment of a lower category residence, may allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under S.R. 317-BB-5 on the basis of his priority date for the same.

(3) The divisional officer may even in case of non-reserved accommodation cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

(4) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1) be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority date, if it is apprehended that the allottee officer may not accept the allotment.

Non-acceptance of Allotment or Offer|or Failure to occupy the Allotted Residence after Acceptance—S.R. 317-BB.8.

(1) If any officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date or receipt of the letter of allotment he shall not be eligible for another allotment for period of one year from the date of the allotment letter.

(2) If an officer occupying a lower type of residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under S.R. 317-BB-5 or for which he has applied under S.R. 317-BB-6, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely :—

(a) that such an officer shall not be eligible for another allotment for the remaining period of the allotment year in which he has declined the allotment or offer ;

(b) while retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had paid under F.R. 45-A in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher.

Period for which Allotment subsists and the Concessional Period for further Retention—S.R. 317-BB-9.

(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until,

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-clause (2) after the officer cases to be on duty in an eligible office of the Central Public Works Department ;

(b) it is cancelled by the divisional officer or is deemed to have been cancelled under any provision of these rules ;

(c) it is surrendered by the officer with due notice . or

(d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may subject to sub-rules (3) and (5) be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof provided that the residence is required for the bona fide use of the officer or members of his family.

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence
1	2
(i) Resignation, dismissal or removal from service termination of service or unauthorised absence without permission.	1 month.
(ii) Retirement or terminal leave.	2 months.
(iii) Death of the allottee	4 months.
(iv) Transfer to a place outside the city concerned.	2 months.
(v) Transfer to an office which is not eligible for accommodation under these rules.	2 months.
(vi) On proceeding on foreign service in India	2 months.
(vii) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	4 months.
(viii) Leave (other than leave (a) preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave).	For the period of leave but not exceeding 4 months.
(b) Maternity leave.	For the period of maternity leave plus the leave granted in continuation subject to maximum period of five months

1	2
(ix) leave preparatory to retirement or refused leave granted under F.R. 86 or earned leave granted to Government Servants, who retire under F.R. 56(j)	For the full period of leave on full average pay, subject to a maximum of 180 days in the case of leave preparatory to retirement and 4 months in other cases, inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(x) Study leave in or outside India	(a) In case the officer is in occupation of accommodation below his entitlement, for the entire period of study leave. (b) In case the officer is in occupation of his entitled type accommodation, for the period of study leave but not exceeding six months : Provided that where the study leave extends beyond six months he may be allotted alternative accommodation, one type below his entitlement, on the expiry of six months or from the date of commencement of the study leave, if he so desires.
(xi) Deputation outside India.	For the period of deputation but not exceeding six months.
(xii) Leave on medical grounds	Full period of leave.
(xiii) On proceeding on training	For the full period of training.

Note : The above concessional period for retention of Government accommodation not available when any quarter has been earmarked for a specific post by the Government.

Explanation : The period permissible on transfer mentioned against items (iv) and (v) in the Table shall count from the date of relinquishing charge plus the period of leave, if any, sanctioned to and availed of by the officer before joining duty at the new office subject to a maximum limit provided under items (vi) or (ix) as the case may be of the Table.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional period unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office at that place.

(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xii) of the Table below sub-rule (2) :

Provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months the allotment shall stand cancelled.

(5) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or item (ii) of the Table below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office within the period specified in the said Table be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules :

Provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him; he shall apply for allotment of a lower type of residence.

6. Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) of sub-rule (4) of sub-rule (5) when an officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the office in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may require the divisional officer to cancel the allotment of the residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item—(i) of the Table below sub-rule (2) as he may specify and the divisional officer shall act accordingly.

Vacation of Residence—S.R. 317-BB-10

(1) The vacant possession of the quarters shall be given by the allottee Government servant to Junior Engineer or to Assistant Engineer in case Junior Engineer himself is to hand over the vacant possession, concerned with the maintenance of those quarters within the period prescribed under these rules.

(2) When after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence equal to the panel licence fee as may be determined in accordance with the policy formulation approved by the Government.

Provisions relating to Licence Fee : S.R.—317-BB-11

(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.

An officer who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of 12 days.

(2) Where an officer, who is in occupation of a residence is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

(3) House owning officers or those who owns a house after allotment and are occupying Government accommodation shall pay licence fee as decided by the Government from time to time.

Personal Liability of the Officer for payment of Licence Fee till the residence is vacated and furnishing of security by temporary officers—S.R. 317-BB-12

(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules, until the residences along with the out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Central Government with a surety, who shall be a permanent Government servant serving under the Central Government for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residences and services and any other residences and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reason, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact; and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the divisional officer be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

Surrender of an Allotment and Period of Notice—S.R. 317-BB-13.

(1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the divisional officer at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the divisional officer or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice, he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short often days, provided that the divisional offirer may accept a notice for a short period.

(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

Change of Residence—S.R. 317-BB-14.

(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under S.R. 317-BB-5 whichever is lower. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) All applications for change made in the form prescribed by the divisional officer and received upto the 19th day of a calendar month shall be included in the waiting list in the succeeding month. For purposes of this rule the officers whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior en block to those whose names are included in subsequent months. The inter se seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Changes shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officer's preference as far as possible :

Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation.

(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of residence of that type.

(5) If an officer who after accepting a change of residence fails to take possession of the same he shall be charged licence fee for such residence in accordace with the provisions of sub-rule (1) of S.R. 317-BB-11 in addition to the normal licence fee under F.R. 45-A for the residence already in his possession, the allotment of which shall continue to subsist.

Change of Residence in the event of Death of a Member of the Family—S.R. 317-BB-15.

Notwithstanding anything contained in S.R. 317 BB-14 an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence provided that the change will be given in the same type of residence and in the same floor as the residence already allotted to the officer.

Mutual Exchange of Residences—S.R. 317 BB-16.

Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty at the same place and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

Transfer to Non-family Station—S.R. 317-BB-17.

If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the bona fide educational needs of his children, he may be allowed on request to retain the residence on payment of the rent under F.R. 45-A till the end of current academic session of his children. However, this rule is not applicable in case of reserved accommodation where the orders of Directorate of Estates O.M. No. 2/52/64-Acc J dated the 20th March, 1965 will regulate retention of reserved accommodation.

Maintenance of Residences—S.R. 317-BB-18.

(1) The offer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Central Public Works Department and the local civil authorities. Such officers shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or Central Public Works Department nor cut or lop off any existing tree or shrub in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the Central Public Works Department. Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the divisional officer or other authority concerned at the risk and cost of the officer concerned.

(2) No additions or alterations shall be made in and around the premises allotted without the permission of the divisional officer.

Subletting and Sharing of Residences—S.R. 317-BB-19.

(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with the employees eligible for allotment of residence under these rules. The servants' quarters, out-houses and garages may be used only for the bona fide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Divisional Officer.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence :

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other officer eligible to share accommodation under these rules as a caretaker for the period specified in S.R. 317-BB-9, but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear. The allottee shall have to pay damages as decided by the Government in cases of misuse on account of subletting (partly or fully) sharing without permission or for the structural misuse.

(4) The premises allotted for residential purpose, if used for any other purpose by the allottee shall constitute violation of the allotment rules.

Consequences of Breach of Rules and Conditions—S.R. 317-BB-20.

(1) If an officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges licence fee from the sharer at a rate which the divisional officer consider excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of these rules or the terms and conditions of the allotment of uses the residence or premises or allows the residence or premises to be used for any purpose which the divisional officer considers to be improper or conducts him-

self in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the divisional officer may without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him cancel the allotment of the residence. Allotment is liable to cancellation if in the opinion of the allotting authority, the conduct of the allottee or his dependent is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with the neighbours.

Explanation :—In this sub-rule the expression 'Officer' includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the officer.

(2) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses or garages, appurtenant thereto in contravention of these rules, he may without prejudice to any other action that may be taken against him be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under F.R. 45-A. The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the divisional officer on merits. In addition the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the divisional officer.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee and any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with the neighbours, the officer at the discretion of the divisional officer may be allotted another residence in the same class at any other place.

(5) The divisional officer shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) of this rule and also to declare the officer who commits a breach of the rules and instructions issued to him to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

(6) Where any penalty under this rule is imposed by any officer of the rank of Superintending Engineer or below, the aggrieved person may within twenty-one days of the receipt of the orders by him or his employer imposing the penalty, file a representation to the Chief Engineer or Director General (Works).

(7) The original order imposing the penalty shall stand unless it is modified or rescinded as a result of the representation.

Overstay in Residence after cancellation of Allotment—S.R. 317-BB-21.

Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the panel licence fee or twice the licence fee the officer was paying, whichever is higher, as may be determined by Government fro mtime to time :

Provided that an officer, as a special case, may be allowed by the divisional officer to retain a residence which is not earmarked for a particular post, on payment of twice the standard licence fee under F.R. 45A or twice the pooled standard licence fee under F.R. 45-A or twice the licence fee the officer was paying, whichever is higher, for a period not exceeding two months beyond the period permitted under S.R. 317-BB-9.

Continuance of Allotment made Prior to the Issue of these Rules S.R. 317-BB-22.

Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules under the rules then in force shall be deemed an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation of that allotment and that officer accordingly.

Interpretation of Rules--S.R. 317 BB-23.

If any question arises as to the interpretation of the rules in this Division, it shall be decided by the Central Government.

Relaxation of Rules—S.R. 317-BB-24.

The Central Government may for reasons to be recorded in writing relax all or any of the provisions of the rules in this Division in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

Delegation of powers Functions—S.R. 317-BB-25.

The Central Government may delegate any or all the powers conferred upon it by the rules in this Division to any officer under its control subject to such conditions as it may deem fit to impose.

[F. No. 28017/7/80-EW 2]

D. P. OHRI, Dy. Secy.

DRAFT ALLOTMENT LETTER

No.—————— ALLOTMENT/IMMEDIATE

GOVERNMENT OF INDIA

C.P.W.D. Division Dated the

To

————————

————————

————————

Dear Sir/Madam,

The marginal noted residence is hereby allotted to you in accordance with the provision of the 'Allotment of Govt. residences under the Central Rules, 1981. This allotment is made for the period you remain attached to... ....

1. Particulars of residence	2. Type	....Division and
3. in lieu of unfurnished residence	4. Type	functioners. ......in charge
5. furnished		of...... .....Section/Sub
		Division/Division

2. You are requested to send your acceptance within 5 days from the date of receipt/issue of this letter. The acceptance should be in the enclosed form in duplicate and should be addressed to the undersigned (by name).

3. If no acceptance is received within the prescribed period of 5 days, the allotment will be deemed to have been refused and your case will be dealt with accordingly.

4. If you are a temporary Govt. servant, you are required to furnish a surety bond from a permanent Central Govt. servant along with your acceptance. The bond should be on the prescribed form.

5. If the allotment is accepted you should take possession of the allotted residence from the C.P.W.D. Enquiry Office concerned within 8 days of the date of receipt of this letter. In case of failure to take the possession within the time specified above, you will be liable to pay licence fee with effect from the 8th day and the allotment shall be liable to cancellation.

Yours faithfully,
Executive Engineer
———Division, CPWD.

Dated, the.................19

Copy forwarded to :

1. ....Sub-Division.
2. Cashier.................Division/Bill Asstt.

3. Accountant..................Division.
4. S. E. ....Circle for information w.c.f. approval received under.
5. A & A/Cs office.

DRAFT ACCEPTANCE LETTER

The Executive Engineer

————————————Division,

C.P.W.D.

Subject : Acceptance of residential accommodation.

Sir,

I accept the allotment of residence No————made to me vide your letter No.———— dated ————received by me on——————(Dated).

Full details of my emoluments are given below :

(i) Pay———— ————
(ii) Special pay if any ————
(iii) Pension, and pension equivalent of Death-cum-Retirement gratuity. ————
(iv) Dearness pay, if any ————
(v) City Compensatory Allowance————
(vi) Any other allowance other than Dearness Allowance, Conveyance allowance, House Rent etc.

Total :—

I am a quasi permanent/permanent Central Govt. servant
I am a temporary Govt. Servant : and the particulars of my surety are given below :—

(i) Name of surety
(ii) Designation of surety
(iii) Office/Ministry where employed

No other Govt. accommodation is allotted to me or to my wife/husband to date, either by the Directorate of Estates or by the Department of Rehabilitation or by any other Govt. Deptt./Autonomous body/Semi Govt./Public Undertaking Office.

I certify that I do not own a house or flat in the station of posting either in my own name or in the name of my wife/husband, or any other member of my family. I also undertake to inform you if and when I or any member of my family acquire a house at this station.

I agree to vacate the quarter within two weeks of my transfer from the present post, without waiting for a formal allotment in general pool or otherwise.

I have carefully read the Rules regarding Allotment of Govt. Residences at the disposal of C.P.W.D. to its Employees and hereto agree to abide by these rules.

Yours faithfully,

Signature
Name in Block letters
Designation.

...............Date.

SURETYBOND

I, Shri———————— son of Shri———— ———— employed as ———— in the ———————— hereby stand surety which expression shall include my heirs, executors and administrator to the president of India (hereinafter called the Govt.) (which expression includes his successors and assignees) for payment by Shri ————————of licence fee and other dues in respect of the residence now allotted to him by Govt. as also for any residences, addl. accommodation, extra servant quarter or garages that may be allotted to him from time to time by the Government.

2. I, the survey, shall indemnify the Govt. against all loss and damages until delivery of vacant possession of the same is made to the Govt. I, the surety, hereby undertake to pay to the Govt. forthwith on demand by Govt. and without tenure all such sums as may be due to the Govt. as aforesaid and I hereby agree that the Govt. shall be at liberty (and be hereby irrecoverably authorised to do so) to recover the said sums from the salary payable to me and the decision of the Govt. as to the amount so to be recovered shall be final.

3. The obligations undertaken by me shall not be discharged or in any was affected by an extension of time or any other indulgance granted by the Govt. to the said Shri ———————— (Name of the allottee) or by any other matter of thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provisions have the effect of so releasing me from my such liabilities.

4. This guarantee shall not be discharged by my death nor shall it be recoverable by me at any time, excant with the consent in writing of the Government, untill the delivery of vacant possession of any such residence servant quarter or garage, which is in occupation of the allottee of the Government quarter.

5. Provided, however, that this guarantee shall inso-facto terminate from the date Shri ———————— is declared permanent or quasi-permanent in any service in the Government of India.

6. The Government have agreed to bear the stamp duty, if any, for this document.

Signed and delivered by the said ————————at New Delhi the day of————————19

Signature, Address & Occupation of witness.

(Signature of surety)
Designation ————
Office to————
which ————
attached————

Certified that the above surety is a permanent Govt. servant. He is ———— ————years of age and his pay is Rs. ————.

Signature of the Head of the Deptt. the office in which the surety is employed.

Dated :

Offire Stamp :

Copy

No. 2/52/64-Acc. 1

Government of India

Ministry of Works & Housing

New Delhi, the 20-3-65

OFFICE MEMORANDUM

Sub :—Extension of Govt. accommodation allotted free of rent to Govt. servants in the event of leave, transfer, death, resignation etc.

The orders contained in this Min.'s office Memo No. W-II-82(8)/53, W.II.27(2)/55 and 2/213|59-Acc. dated the 28-5-1954, 24-11-1955 and 25-5-1960 respectively provide that :

(i) An officer allotted residential accommodation on rentfree basis may be allowed to retain the residence free of rent while on leave upto a maximum period of one month subject to the condition that he is likely to return to the same post from which he proceeds on leave. Where, however, the period of leave granted to such an officer exceeds one month and the officer concerned is permitted to retain the residence by the competent authority

during such period, usual rent in accordance with the rules in force shall be recovered for any period of leave exceeding one month.

(ii) A female officer who has been allotted residential accommodation free of rent may be permitted to enjoy the rent free concession during the entire period of maternity leave provided that the accommodation is not required for the substitute if any engaged during the absence on leave of the officer concerned and she is likely to return to the same post from where she proceeds on leave.

(iii) On transfer from one station to another, the officer may be allowed to retain the residence, free of rent for a period of first 15 days and thereafter on payment of rent under fundamental Rule 45-A but not exceeding two months from the date of handing over of the charge.

(iv) In the event of death of the officer, his family may be allowed to retain the residence, free of rent for a period of one month from the date of the officers' death and thereafter for a further period of 3 months on payment of rent under fundamental Rule-45-A.

(v) On resignation, rent free concession to the officer will cease from the date of resignaion. However, in the case of dismissal or removal or retirement from services, he may be allowed to retain the residence for a period of one month, free of rent.

The retention of residence in cases mentioned above is to be allowed only if the same is required for the bonafide use of the officer or his family as the case may be and the residence can be conveniently spared by the competent authority.

2. A question has been raised if allottees of reserved residences could as well be allowed to retain the accommodation after handing over charge. The position is that a reserved residence is intended for occupation by the officer who actually holds the post. He is not entitled to retain it during the period of leave unless the competent authority permits him to do so. The allotment subsists only during the period of incumbency and immediately on change of incumbency, the successors incumbent becomes the allottee of the residence in question. It will, therefore, normally be necessary for the successors incumbent to occupy the residence immediately after taking over. If not withstanding these considerations a reserved residence can be made available to the out going incumbent of the post or his family, the Govt. of India have decided that the concessional periods mentioned in the preceding para may be allowed by the competent authority to the allottee of the reserved residence in similar contingencies irrespective of the fact whether the allotment is on rent free basis or on rent paying basis provided that it is not determined to the interest of new incumbent of that post and the accommodation can be conveniently spared and it does not involve any loss of revenue or extra cost of the Govt. The administrative Ministry/Department of the Govt. of India will be the competent authority for this purpose.

3. These orders issue with the concurrence of the Controller and Auditor General of India in so far as the officers working under him are concerned.

4. This O.M. issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Estates) vide their U.O. No. 4900-Estates/64 dated 13-10-1964.

Sd/-
H. S JAIN, Under Secy.

To

All the Ministries/Departments etc. of the Govt of India.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1981

का० आ० 2475—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, प्रादेशिक कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, रायपुर को, जिसके कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[संख्या ई० 11011/42/79-हिन्दी]
कान्ति देब, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 31st August, 1981

S.O. 2475.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Regional Office, Directorate of the Field Publicity, Raipur, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E.11011/42/79-Hindi]
KANTI DEB, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1981

का० आ० 2476—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा मुख्य बंदोबस्त आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह इसके द्वारा बंदोबस्त आयुक्त श्री एम० बी० भल्ला को निम्नलिखित शक्तियां सौंपते है :—

1. उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील सुनने की शक्तियां ।
2. उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण अपील सुनने की शक्तियां ।

[सं० 1(2)/विशेष सैल/81-एस० एस०-II]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 14th August, 1981

S.O. 2476.—In exercise of the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by Sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), he hereby delegates to Shri M. B. Bhalla Settlement Commissioner, the following powers :—

1. Powers to hear appeals under section 23 of the said Act.
2. Powers to hear revisions under section 24 of the said Act.

[No. 1(2)|Spl. Cell|81-SSII.]

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1981

का० आ० 2477—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त, इसके द्वारा बंदोबस्त आयुक्त के रूप में शक्तियों का प्रयोग कर रहे, हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग के उपसचिव को, मुआवजा पूल की सभी अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियों, जिन्हें प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत हरियाणा सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है, के निपटान के लिये उक्त अधिनियम के नियम 87, 88, 90 (1) (क), 90(1) (ख), 90 (11), 90(12) और 101 के अधीन अपनी शक्तियां सौंपते है ।

[सं० 1(14)/विशेष सैल/75-एस०एस०-II]
गोविंद जी मिश्र, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त

New Delhi, the 21st August, 1981

S.O. 2477.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Deputy Secretary, Rehabilitation Department, Government of Haryana exercising the powers of the Settlement Commissioner, his powers under rules 87, 88, 90(1)(a), 90(1)(b), 90(11), 90(12) and 101 framed under the said Act, for the purpose of disposal of all acquired evacuee properties forming part of the Compensation Pool, transferred to the Government of Haryana, under administrative and financial arrangements.

[No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS II.]

G. J. MISRA, Chief Settlement Commissioner.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1981

का० आ० 2478—बम्बई पत्तन ट्रस्ट बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त विवाद को संदर्भ संख्या 1974 का सी० जी० आई० टी० 2/16 में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, बम्बई को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित किया और उक्त अधिकरण ने 10 अक्तूबर, 1978 को पंचाट दिया ;

और केन्द्रीय सरकार की राय में इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट प्रश्न पर उपर्युक्त पंचाट की व्याख्या के बारे में एक सन्देह उत्पन्न हुआ है और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न को व्याख्या के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, बम्बई को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

1974 के संदर्भ संख्या सी० जी० आई० टी०-2/16 में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के पैराग्राफ 56 और 57 में निर्दिष्ट इस आशय के निर्देशों की पृष्ठभूमि में कि संबंधित कर्मकारों को पीर पाओं और बूचर आइलैंड के बीच प्रतिवर्ष बारी-बारी से लगाया जाना चाहिए, क्या बम्बई पत्तन ट्रस्ट की संबंधित कर्मकारों समान संख्या के बैचों का पीर पाओ से बूचर आईलैंड में और बूचर आइलैंड से पीर पाओ में स्थानांतरित करने की कार्यवाही पंचाट की भावना के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो उपर्युक्त पंचाट के अनुसार रोटेशन का यथार्थ पैटर्न क्या होना चाहिए ?

[सं० एल-31025/1/81-डी 4 ए०]

नन्द लाल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 10th April, 1981

S.O. 2478.—Whereas in an industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay and their workmen, the Central Government referred the said dispute to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay for adjudication in reference No. CGIT-2/16 of 1974 and the said Tribunal gave an award on the 10th October, 1978 ;

And whereas, in the opinion of the Central Government, a doubt has arisen as to the interpretation of the said award on the question specified in the Schedule hereto annexed and the Central Government considers it desirable to refer the question for interpretation ·

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

In the back ground of the directions contained in paragraphs 56 and 57 of the Award of the Central Government Industrial Tribunal in reference No. CGIT-2/16 of 1974 to the effect that workmen concerned should by rotated between Pir Pau and Butcher Island yearly, whether the action of the management of Bombay Port Trust in transferring batches of equal number of concerned workmen from Pir Pau to Butcher Island and vice versa is in conformity with letter and spirit of the award ? If not, what precisely should be the pattern of the rotation in terms of the above said Award ?

[No. L-31025(1)/81-D.IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

672 GI/81—7

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1981

का० आ० 2479—केन्द्रीय सरकार अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि से वित्तपोषित क्रियाकलापों की निम्नलिखित रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा विवरण तथा उक्त निधि के वर्ष 1981-82 की प्राप्तियों और व्ययों के प्राक्कलन सहित प्रकाशित करती है।

भाग-1

(1) सामान्य :

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि का गठन अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) के अधीन अभ्रक खान उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण से संबंधित स्कीमों के वित्त पोषण के लिए किया गया है।

2. अधिनियम में, निर्यात की गई सभी अभ्रक पर मूल्यानुसार तथा छः प्रतिशत की अधिकतम दर पर सीमाशुल्क के उदग्रहण के लिए उपबन्ध किया गया है। उपकर की दर, जो कि पहले मूल्यानुसार 2½ प्रतिशत थी, 15 जुलाई, 1974 से 3 1/2 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। संग्रहणों का आवंटन विभिन्न अभ्रक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में उनके औसत उत्पादन के अनुपात में कल्याणकारी उपायों में संबंधित व्यय के लिए किया जाता है।

भाग-2

व्यवस्थित सुविधाएं

(क) चिकित्सा :

अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा अभ्रक श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। उनके अन्तर्गत अस्पतालों, प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्रों का प्रावधान और अनुरक्षण गृहोपचार सहित क्षयरोग के उपचार की सुविधाएं, आयुर्वेदिक औषधालय सहित औषधालय सेवाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान अभ्रक खनिकों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए कल्याण संगठनों द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय अस्पताल चलाए जाते रहे :—

क्रम संख्या अस्पताल का नाम		पलंगों की संख्या
1	2	3
1. केन्द्रीय अस्पताल कर्मा (बिहार)		100
2. केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर (राजस्थान)		30
3. केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेडु, (आन्ध्र प्रदेश)		30
4. क्षेत्रीय अस्पताल, तिसरी (बिहार)		30
5. क्षेत्रीय अस्पताल, तालपुर, (आन्ध्र प्रदेश)		10
6. केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेडु (आन्ध्र प्रदेश) से संलग्न क्षयरोग वार्ड		20
7. क्षयरोग अस्पताल, कर्मा, बिहार		50
8. क्षेत्रीय अस्पताल, सईदापुरम		10 (आहार से साथ)

इसके अलावा अभ्रक उत्पादन करने वाले तीन राज्यों में निम्नलिखित अन्य प्रकार के चिकित्सा संस्थान भी लगातार कार्य करते रहे :—

चिकित्सा संस्थान का नाम	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
1	2	3	4	5
एलोपैथिक औषधालय	1	5	3	9
आयुर्वेदिक औषधालय	2	8	4	14
चलते-फिरते व स्थिर औषधालय	—	—	1	1
प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र	4	—	3	7
चलते-फिरते चिकित्सालय एकक	1	3	—	4
होम्योपैथिक एकक	1	—	—	1
लघु समुदाय केन्द्र	—	5	—	5

कल्याण संगठन क्षयरोग से पीड़ित खनिकों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करता रहा। क्षयरोग अस्पतालों और क्लिनिकों की स्थापना के अलावा क्षयरोग/सिलिकोसिस से पीड़ित अभ्रक खनिकों के विशेष उपचार की व्यवस्था करने के लिए क्षयरोग सेनेटोरियम, मदार (अजमेर) में चार पलंग आरक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अस्पताल गंगापुर में 10 पलंगों के अलग वार्ड हैं। कल्याण निधि क्षयरोग और छाती के रोगों के सरकारी अस्पताल, नैल्लौर में छः पलंगों का केवल अभ्रक खनिकों और उनके परिवारों के प्रयोग के लिए आरक्षण जारी रहा।

क्षयरोग के ऐसे रोगी को 9 मास की अवधि तक के लिए 50 रुपये प्रतिमास का निर्वाह भत्ता दिया जाता है, यदि वह परिवार के लिए स्वयं ही कमाने वाला सदस्य हो। आलोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान बिहार में 8 मरीजों, राजस्थान में 5 मरीजों और आन्ध्र प्रदेश में 3 मरीजों को निर्वाह भत्ता मंजूर किया गया।

विविध चिकित्सा सुविधाएं :

घातक दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत, निधि से खनिक की पत्नी को 200 रुपये की एक मुश्त अदायगी और पांच वर्ष की अवधि के लिए देय 25 रुपये प्रतिमास के भत्ते की अदायगी और प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए उसके 15 वर्ष के होने तक या विवाह करने तक, जो भी पहले हो, 15 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति की अदायगी के रूप में वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

आलोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत (आंध्र प्रदेश) कालीचेडु में पांच मामलों में 2850 रुपये और कर्मा (बिहार) में मृतकों के छः आश्रितों को 1218.06 रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

तेतुलमारी कोढ़ अस्पताल में कोढ़ से पीड़ित बिहार के अभ्रक खनिकों के उपचार के लिए व्यवस्था जारी रही। कैंसर से पीड़ित अभ्रक खनिकों के उपचार के लिए केन्द्रीय अस्पताल कल्ला (आसनसोल) और रांची में रांची में मानसिक रोगों के अस्पताल में मानसिक रोगों से पीड़ित खनिकों के उपचार व्यवस्था जारी रही। कैंसर से पीड़ित अभ्रक खनिकों के उपचार की योजना के अन्तर्गत अस्पताल में पलंगों के आरक्षणों की अनुमति दी गई है, जिसमें सामान्यतः 9 मास से अनाधिक अवधि के लिये मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई और कुछ अपवाद वाले मामलों में यह अवधि 9 मास से अधिक हो सकती है, यदि उपचार कर रहे चिकित्सा प्राधिकारी ऐसा चाहते हैं।

ऐसे रोगी, जिन्हें हक प्राप्त नहीं है, अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों से उपचार भी प्राप्त करते हैं। उनके उपचार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधि संगठनों को सहायक अनुदान दिया जाता है।

अभ्रक खान श्रमिकों को 20 रुपये प्रति जोड़ा ऐनक से अनाधिक लागत पर ऐनकें सप्लाई की जाती हैं।

(ख) शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं :

अभ्रक श्रमिकों और उनके आश्रितों को शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, कल्याण संगठनों द्वारा बहुद्देशीय संस्थान चलाए जाते हैं। प्रत्येक संस्थान में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और एक महिला कल्याण केन्द्र शामिल हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यकलापों का विस्तार करने हेतु कल्याण संगठन ने सहायक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी खोले हैं। मनोरंजन के प्रयोजनार्थ अभ्रक खनन क्षेत्रों में रेडियो सेट स्थापित किए गए हैं और अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन के अन्तर्गत मनोरंजन क्लब, पुस्तकालय और रीडिंग कक्ष कार्य कर रहे हैं। शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा प्राथमिक स्कूल/मिडिल स्कूल/हाई स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले संस्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

क्रमांक	संस्थाओं का ब्यौरा	आंध्र प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	बहुद्देशीय संस्थान (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और महिला कल्याण केन्द्र सहित)	—	9	5	14
2.	लघु समुदाय केन्द्र	1	6	8	15
3.	प्रारम्भिक स्कूल	4	3	—	7
4.	मिडिल स्कूल	—	4	—	4
5.	हाई स्कूल	2	1	—	3
6.	सहायक केन्द्र	—	1	—	1
7.	खनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास/होस्टल	2	4	1	7
8.	चलते फिरते सिनेमा एकक	1	3	1	5
9.	विभागीय सिनेमा एकक रेडियो सेट	20	—	8	28
10.	मनोरंजन क्लब	14	—	—	14
11.	भजन मंडली	9	—	9	18
12.	पुस्तकालय और वाचनालय	—	—	10	10

अभ्रक खनिकों को भ्रमण एवं अध्ययन दौरों की सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है। चलते फिरते सिनेमा एकक के माध्यम से शैक्षिक एवं धार्मिक महत्व की फिल्में दिखाई जाती हैं।

स्कूलों और कालेजों में अभ्रक खनिकों के पढ़ रहे पुत्रों/पुत्रियों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

अभ्रक खनिकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर खेल-कूद आयोजित किए जाते हैं और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते हैं।

(ग) पेय जल की सुविधाएं :

अभ्रक खनन क्षेत्रों में पेय जल की कमी एक चिरकालिक समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए कुंए खोदने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, मालिकों को कुंए खोदने के लिए दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में कालीचेडु गांव में एक स्थायी जल प्रदाय योजना चल रही है। तुरीमेरला जल प्रदाय योजना, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 76,750 रुपये की राशि मंजूर की है, का कार्य सभी पहलुओं में पूरा किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को अनुरक्षण के लिये अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन, कालीचेडु, आन्ध्र प्रदेश को अभी तक सौंपना है।

आलोच्य वर्ष के दौरान अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि बिहार द्वारा "बिना लाभ या हानि के" आधार पर विभागीय ट्रक द्वारा पेय जल की व्यवस्था की गई।

(घ) आवास :

दो आवास योजनाएं अर्थात् अपना मकान बनाओ योजना और टाइप-1 आवास योजना (कम लागत आवास योजना) चल रही है।

अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान के लिए 1500 रुपये की वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है (600 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में और मासिक किस्तों में बिना ब्याज के रूप में 900 रुपये, जो सौ वर्ष से अनाधिक अवधि में वसूल किए जाएंगे) इस योजना के अन्तर्गत अब तक 630 मकानों को पूरा किया जा चुका है।

टाइप-1 आवास योजना के अन्तर्गत, साधारण क्षेत्रों में मानक अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 6825 रुपये हैं और कपास पैदा करने वाली काली या उभरी हुई भूमि वाले क्षेत्रों में 7825 रुपये या मकानों के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम है, आर्थिक सहायता दी जाती है। कार्य आदेश जारी होने के साथ खान प्रबन्धकों को आर्थिक सहायता का 20 प्रतिशत अग्रिम रूप में दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 58 मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

इससे पूर्व विभागीय कालोनी योजना के अन्तर्गत 120 मकान और आर्थिक सहायता प्राप्त आवास योजना की पुरानी योजना के अन्तर्गत 6 मकान बनाए गए थे। आवास कार्यक्रमों की गति को तेज करने के लिए और योजनाओं को अधिक आकर्षित बनाने के लिए एक आवास उप समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है। इसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(ङ) उपभोक्ता सहकारी भंडार :

दो उपभोक्ता सहकारी भंडार एक आन्ध्र प्रदेश में और एक बिहार में श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं की उचित दर पर व्यवस्था करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

भाग—3

वर्ष 1980-81 की प्राप्तियां और व्यय इस प्रकार हैं :—

पहली अप्रैल, 1980 को अथशेष	63,25,235.10
महालेखाकार, बिहार से प्राप्त सूचना के आधार पर लिए गए आंकड़े	103,04,301.37
	1,66,29,536.47
वर्ष 1980-81 के दौरान प्राप्तियां	1,01,29,158.80
कुल	2,67,58,695.27
वर्ष 1980-81 के दौरान व्यय	75,29,241.39
31 मार्च, 1981 को अन्त शेष	1,92,29,453.88

भाग—4

वर्ष 1981-82 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय

बजट अनुमान	रुपये लाखों में
प्राप्तियां	100.00
व्यय	93.02

[फाईल सं० जैड-16016/1/81-खान-3]

आर० के० दास, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 1981

S.O. 2479.—In pursuance of sub-section (4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 1946) the Central Government hereby publish the following report of the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ending 31st March, 1981 together with a statement of accounts for that year and an estimate of receipts and expenditure of the said fund for the year 1981-82.

PART—I

1. General :

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) for financing schemes relating to the Welfare of Labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of customs, on all mica exported, upto a maximum rate of 6-1/4 per cent ad-valorem. The rate of cess, which was 2½ per cent ad valorem previously, has been increased to 3½ per cent with effect from the 15th July, 1974. The collections are allocated for expenditure on welfare measures among the various mica producing areas in proportion to their average production.

PART—II

Facilities—Provided

A. Medical :

Various types of medical facilities for mica workers and their dependants are provided free of cost by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treatment of T.B. including domiciliary treatment dispensary services including Ayurvedic dispensaries and other facilities, etc. The following Central and Regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisations for the treatment of mica miners and their dependants during the year under report :

S. No.	Name of the Hospital	Bed Strength
1	2	3
1.	Central Hospital, Karma, (Bihar)	100
2.	Central Hospital, Gangapur (Rajasthan)	30
3.	Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	30
4.	Regional Hospital, Tisri (Bihar)	30
5.	Regional Hospital, Talupur (Andhra Pradesh)	10
6.	T.B. Ward attached to Central Hospital Kalichedu (Andhra Pradesh)	20
7.	T.B. Hospital, Karma, (Bihar)	50
8.	Regional Hospital, Sydapuram	10 (Dietary)

In addition, the following other medical institutions also continued to function in the three mica producing States :

Medical Institutions	Andhra Pradesh	Bihar	Rajasthan	Total
Allopathic Dispensaries .	1	5	3	9
Ayurvedic Dispensaries .	2	8	4	14
Mobile-cum-Static Dispensaries . .	..	..	1	1
Maternity and Child Welfare Centres . . .	4	..	3	7
Mobile Medical Unit .	1	3	..	4
Homeopathic Unit ..	1	..	..	1
Small Community Centres	..	5	..	5

The Welfare Organisations have been endeavouring to provide adequate facilities for tre tm^nt of the miners suffering from T.B. Apart from setting up of T.B. Hospitals and clinics, four beds remained reserved at T.B. Sanatorium, Madar (Ajmer), for providing specialized treatment to mica miners suffering from T.B./Silicosis. Besides, there is a 10 bedded segregated war in the Central Hospital, Gangapur, for the purpose. Six beds in the Govt. Welfare Fund T.B. & Chest Disease Hospital, Nellore, continued to be reserved for the exclusive use of mica miners and their families.

A subsistence allowance of Rs. 50 per month is granted to a T.B. patient for a period upto 9 months where he happens to be the only earning member of the family. During the period under report 8 patients in Bihar, 5 patients in Rajasthan and 3 patients in Andhra Pradesh were sanctioned Subsistence Allowance.

Miscellaneous Medical Facilities

Under the Fatal Accident Benefit Scheme, the Fund continued to provide financial assistance to the spouse of a miner in the form of a lumpsum payment Rs. 250 and a monthly allowance of Rs. 25 payable for a period of five years and a monthly scholarship of Rs. 15 pay ble in respect of each school going child till he/she attains age of 15 or is married, whichever is earlier.

During the period under report, an amount of Rs. 2,850 to five cases in Kalichedu, Andhra Pradesh and Rs. 1218.06 p. to six dependents of the deceased in Karma, Bihar, was paid under this Scheme.

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from Leprosy at the Tetulmari Leprosy Hospital. For the treatment of mica miners suffering from c ncer arrangements continued at the Central Hospital, Kalla (Asansol), and for metal diseases at the Mental Hospital, Kanki, Ranchi. Under the scheme for the treatment of mica miners suffering from cancer, reservation of beds in a hospital have been allowed which provides free treatment generally for a period not exceeding 9 months and in exceptional cases, this period can be more than 9 months if the treating medical authority so desires.

The non-entitled patients also get treatment from the hospitals run by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. For their tre tment, Grant-in-aid is paid by the concerned State Govts. to the Fund Organisations. Spectacles are supplied to the mica mine workers at a cost not exceeding Rs. 20 per pair of spectacles.

(B) Educational and Recreational f cilities :

For providing education and recreational facilities to mica workers and their dependents, various Multipurpose Institutes, each comprising of an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre, are run by the Welfare Organisations. In order to expand the Adult Education activities, Feeder and Adult Education Centres have also been opened by the Welfare Organisations. For recreational purpose, Radio Sets have been installed in mica mining areas and recreation clubs as well as library and reading rooms have been functioning under the Mica Mines Labour Welfare Organisations. In order to provide educational facilities, Primary Schools/Middle Schools/High Schools are run by the Welfare Organisations. The number of Institutions providing the above facilities are as under :

S No.	Particulars of institutions	A.P.	Bihar	Rajasthan	Total
1.	Multipurpose Institutes (with an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre) .	..	9	5	14
2.	Small Community Centres . . .	1	6	8	15
3.	Primary/Elementary Schools . . .	4	3	..	7
4.	Middle Schools .	..	4	..	4
5.	High Schools .		1	..	3
6.	Feeder Centres .	..	1	..	1
7.	Boarding Houses/Hostels for miners' children .	2	4	1	7
8.	Mobile Cinema Unit .	1	3	1	5
9.	Departmental Radio Sets . . .	20	—	8	28
10.	Recreation Clubs .	14	..	..	14
11.	Bhajan Mandalies .	9	..	..	9
12.	Library & Reading Rooms . .	..	..	10	10

Facilities for excursion-cum-study tour are also provided to the mica miners. Films of educational and religious value are exhibited through a mobile cinema units.

Scholarships are awarded to the sons/daughters of mica miners studying in schools and colleges for their studies.

Games and Sports are organised periodically, to provide recreation to mica miners and prizes are also awarded to the winners.

(C) Drinking water facilities :

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica mining areas. With a view to resolve this problem, a scheme for sinking of wells has been introduced. Under this scheme, 70% of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, whichever is less, is paid to the mine owners for sinking wells. In Kalichedu village in Andhra Pradesh, a permanent water supply scheme is in vogue. The work on the Turimerla Water Supply Scheme, for which a sum of Rs. 76,750 was sanctioned by the Central Government, is complete in all respects. The State Government is yet to hand over the scheme to the Mica Mines Labour Welfare Organisation, Kalichedu, Andhra Pradesh, for maintenance.

Supply of drinking water on departmental truck on 'No profit, no loss' basis was arranged by the Mica mines labour Welfare Fund, Bihar, during the year under report.

(D) Housing : Two Schemes, viz. Build Your Own House Scheme and Type. I Housing Scheme (Low Cost Housing Scheme) are in vogue.

Under Build Your Own House Scheme, financial assistance to the tune of Rs. 1,500 per tenement (Rs. 600 in the form of subsidy and Rs. 900 in the form of inter free loan recoverable in monthly instalments spread over a period not exceeding 9 years) is paid. 630 houses have so far been completed under this scheme.

Under Type I Housing Scheme, subsidy payable is 75% of standard estimated cost, which is Rs. 6,825 in ordinary area and Rs. 7,825 in black cotton or swelly soil area or 75% of actual cost of construction of houses whichever is less. 20% of the subsidy is payable in advance to the mine management, with the issue of work order. 58 houses have so far been completed under this scheme.

Earlier, 120 houses were built under the Departmental colony scheme and another 6 houses under subsidized house scheme were constructed. With a view to accelerate the pace of housing programmes and to make the schemes more attractive, a Housing Sub-Committee was constituted, which has since submitted its report. This is being examined in the Ministry.

(E) Consumers Co-operative stores

Two Consumers Co-operative Stores, one each in Andhra Pradesh and Bihar, have been functioning to provide the workers their daily necessities at reasonable rates.

PART III

The receipts and expenditure for the year 1980-81 are as follows :

Receipts	
Opening Balance as on 1st April 1980 .	63,25,235.10
Figures adopted on the basis of the information received from Accountant General Bihar.	1,03,04,301.37
	1,66,29,536.47
Receipt during the year 1980-81	1,01,29,158.80
Total	2,67,58,695.27
Expenditure during the year 1980-81 .	75,29,241.39
Closing balance as on 31st March, 1981	1,92,29,453.88

PART IV

Estimated receipts and expenditure for the year 1981-82

Budget Estimates	(Rs. in lkahs)
Receipts	100.00
Expenditure	93.02

[F. No. Z. 16016/1/81-M.III]
R.K. DAS, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1981

का०आ० 2480.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बजरंग खान, जवाजा, राजस्थान के प्रबन्धमण्डल से संबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्ता होंगे, जिनका मुख्य कार्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैं० बजरंग खान, जवाजा, राजस्थान के प्रबन्ध-मण्डल की श्री राम सिंह, मेट, श्री राम सिंह की पत्नी श्रीमती गैंदी और श्री राम सिंह की पुत्री श्रीमती गंगा की सेवाओं को समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-29012/10/81-डी० III (बी)]
के० के० हांडा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1981

S.O. 2480.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bajarang Mines, Jawaja, Rajasthan and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Ramraj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Bajrang Mines, Jawaja, Rajasthan in terminating the services of Shri Ram Singh, Mate, Smt. Gaindi, wife of Shri Ram Singh, Smt. Ganga, daughter of Shri Ram Singh is justified ? If not, to what reliefs the workmen are entitled to ?"

[No. L-29012/10/81-D.III(B)]
K. K. HANDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1981

का०आ० 2481.—24 जून, 1981 को उड़ीसा राज्य के धेनकनाल जिले में जगन्नाथ कोलियरी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की औपचारिक जांच की जाए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी जांच करने के लिए उड़ीसा सरकार के राजस्व बोर्ड के सदस्य श्री के० राममूर्ति को नियुक्त करती है और इस जांच के लिए असेसरों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी नियुक्त करती है, अर्थात् :—

(1) श्री दामोदर पाण्डेय,
संयुक्त महा सचिव
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ,
रामगढ़ छावनी।

(2) श्री एच० बी० घोष,
सेवा निवृत्त अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट,
13/जी/2, साखरीपाड़ा रोड, कलकत्ता।

[सं० एल-11012/10/81-एम-I]

New Delhi, the 1st September, 1981

S.O. 2481.—Whereas an accident occurred in the Jagannath Colliery in District Dhenkepal of Orissa State, on the 24th June, 1981 causing loss of lives ;

And whereas the Central Government is of opinion that a formal inquiry into the causes of and the circumstances attending the accident ought to be held ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri K. Ramamurty, Member, Board of Revenue, in the Government of Orissa, to hold such inquiry and also appoints the following persons as assessors in holding the inquiry, namely :—

(1) Shri Damodar Pandey,
Joint General Secretary,
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh,
Ramgarh Cantonment.

(2) Shri H. B. Ghose,
Retired Chairman and Managing Director,
Central Mine Planning and Design Institute,
13/G/2, Sankharipara Road,
Calcutta.

[No. N. 11012/10/81-M.I]

नई दिल्ली, 4 सितम्बर 1981

का० आ० 2482—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट स्थानों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों का प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1 उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, केन्द्रीय श्रम संस्थान भवन, सिम्प्रोन, मुम्बई 400022	केंद्रीय श्रम संस्थान भवन मुम्बई स्थित कारखाना सलाह सेवा के महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ऐसे स्थान, जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं ।
2 क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय श्रम संस्थान कलकत्ता ।	केन्द्रीय श्रम संस्थान कलकत्ता के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ऐसे स्थान, जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है।
3 क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय श्रम संस्थान मद्रास ।	क्षेत्रीय श्रम संस्थान, मद्रास के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ऐसे स्थान, जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं।

[सं० ए० 42011 (36)/81 फैक]
जे० के० जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1981

S.O. 2482.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government to be state Officers for the purposes of the said Act, and directs that the said officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposesd, on the state Officers by or under the said Act, within the limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
1. Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Central Labour Institute Building, Sion Bombay-400022.	Premises under the administrative control of the Director General, Factory Advice Service and labour Institute at the Central Labour Institute, Bombay which are within the local limits of his jurisdiction.
2. Regional Director, Regional Labour Institute Calcutta.	Premises under the administrative Control of the Regional Labour Institute, Calcutta. which are within the local limits of his jurisdiction.
3. Regional Director, Regional Labour Institute, Madras.	Premises under administrative Control of the Regional Labour Institute, Madras, which are within the local limits of his jurisdiction.

[No. A-42011/36/81-Fac.]
J. K. Jain, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1981

का० आ० 2483—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1116 तारीख 16 मार्च 1981 के द्वारा सीमेंट उद्योग में सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 16 मार्च, 1981 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 16 सितम्बर, 1981 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस०-11017/2/81-डी० 1ए०]

New Delhi, the 2nd September, 1981

S.O. 2483.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),

declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1115 dated the 16th March, 1981, the Services in the Cement Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 16th March, 1981;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months;

[No. S-11017/2/81-D.I.A.]

का० आ० 2484.— केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1118 तारीख 16 मार्च, 1981, द्वारा जिंक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 17 मार्च, 1981 से छः मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्र सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उपयोग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 17 सितम्बर, 1981 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[(सं० 11017/4/81-डी-1 (ए) (ii)]

S.O. 2484.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 1118 dated the 16th March, 1981, the Zinc Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 17th March, 1981;

And wheeras the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Indusrtial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 17th September, 1981.

[No. S-11017/4/81-D.I.A.(ii)]

का० आ० 2485.— केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1117 तारीख 16 मार्च, 1981, द्वारा सीसा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 25 मार्च, 1981 से छः मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्र सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 25 सितम्बर, 1981 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस-11017/4/81-डी-ए (i)]

S.O. 2485.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1117 dated the 16th March, 1981, the lead mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 25th March, 1981;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powes conferred by the poviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 25th September, 1981.

[No. S-11017/4/81-D.I.A. (I)]

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1981

का० आ० 2486.— केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 945 तारीख 3 मार्च, 1981 द्वारा मैगनेसाइट खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 4 मार्च, 1981 से छः मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त अधिनियम को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उपयोग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 4 सितम्बर, 1981 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11017/3/81-डी-1(ए)]
एल० के० नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1981

S.O. 2486.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 945 dated the 3rd March, 1981, the Magnesite mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 4th March, 1981;

And whereas, the Central Government is of opinion that public inteest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 4th September, 1981.

[No. S-11017(3)/81-D.I(A)]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 3rd September, 1981

S.O. 2487.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation of the management of Mouthdih Unit of Poidih Colliery of M/s. Eastern Coalfield Ltd., Sitarampur Sub-Area, Distt. Burdwan and their workmen, which received by the Central Government on the 28-8-1981.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 91/80

PARTIES :

Employers in relation to the management of Mouthdih Unit of Poidih Colliery of Eastern Coalfields Ltd., Sitarampur Sub-Area Dt. Burdwan.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Management's Personnel.
For the Workmen—Shri Ashes Maiti, Secretary, A.I.T.U.C.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal.

Dated, the 22nd August, 1981

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 had referred the following dispute to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Calcutta for adjudication. Thereafter it was transferred to this Tribunal by Government of India, Ministry of Labour Order No. S-11025(U)/80-D.IV(B), dated the concerned workmen entitled ?"

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Mouthdih Unit of Poidih Colliery under Sitarampur Sub-Area of Eastern Coalfields Ltd., in converting the 33 workmen, as shown in the annexure, from piece rated category to time-rated category and fixing their wages at the lowest stage of the time-rate from April, 1977, was justified ? If not to what relief are the concerned workmen entitled ?"

ANNEXURE

1. Br. Ghurbari Rajbhar
2. Sadan
3. Basith Harijan
4. Bihari Harijan
5. Lalyan Shee
6. Puran Mia
7. Kharthir Mia
8. Choorthu Mia
9. Rajaudih Mia
10. Safli Mia
11. Grli Mia
12. Ch. Mozid Mia
13. Hadish Mia
14. Darati Mia
15. Moti Mistri
16. Shamlal Mistri
17. Joti Mistri
18. Moul Bodi
19. Ramlal Mistri
20. Br. Sitam Rajbhar
21. Br. Ramdhari
22. Br. Shuamlal
23. No. 2 Metich
24. Ramnaran
25. Ch. Ramdhari
26. No. 1 Hari
27. Ramraj Keshwer
28. Jhari Harijan
29. Dharam Abu
30. Prasad Rajbhar
31. Sajoo Gowala
32. Ramchandra Rajbhar
33. Mantu Dhebar Chanki."

2. After taking time on several dates for filing written statements, a joint petition of compromise dated 3rd July, 1981 was filed by the parties on 3-7-81 stating that they have settled the matter on the terms and conditions mentioned in the petition of compromise and prayed that the award may be passed accordingly. The petition of compromise has been signed by the representative of both the employer and employees. I have gone through it and it is beneficial to the employees.

3. Accordingly an award is passed in terms of the petition of compromise which shall form part of the award.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3, DHANBAD.

Ref. No. 91 of 1980 (new)
42 of 1979 (old)

Parties : Employers in relation to the management of Poidih Colliery under Sitarampur Sub-Area of Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their Workmen.

Humble petitioner of both the parties most respectively shewets.

(1) That the Govt. of India, Ministry of Labour by notification No. 91|ITC-3(80)-31 dated 5-1-81 referred the above dispute for adjudication.

(2) That in the mean time the parties have jointly and emicably settled the above mentioned dispute on the following terms and conditions.

(a) That it is agreed that Mr Ghurbari Rajbhar & 32 others shall be given protection of wages with effect from Jan'78 i.e. their date of regularisation as T.R. workers.

(b) That such protection will not exceed the maximum ceiling of the Category in which they are personally working.

(c) That the union agrees that the instant dispute stands fully resolved by virtue of this settlement and their will be no further claim.

(d) That this settlement will be implemented within 1 (one) month from the date of award.

(e) That both the parties agreed that they will bear their own cost.

The petitioners therefore pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the terms of the settlement and pass an award accordingly.

For this act of kindness the petitioner, as in duty bound shall ever pray

Dated 3rd July, 1981

Sd|-
Ashes Maiti
Representative of Employees.

Prem Chand Ray
Representative of Employer
J. N. SINGH, Presiding Officer
[No. L-19012(53)/78-D. IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 4th September, 1981

S.O. 2488.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th August, 1981.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Reference Case No. CIT-1 of 1980

Ref. :—Government of India, Ministry of Labour, New Delhi Order No. L-12012|58|79-D. II. A dated 27th May, 1980.

In the Matter of an Industrial Dispute,

BETWEEN

The Management of State Bank of India.

AND

Their Workmen represented by the General Secretary, State Bank of India Staff Association, New Delhi.

Appearances :

For the Management : Shri S. S. Sharma

For the Association : Shri C. D. Chaturvedi in person

Date of Award : 25-7-1981

AWARD

The Central Government vide order dated 27th May, 1980 referred the following Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (to be referred as the Act hereinafter) :—

"Whether the action of the Management of State Bank of India in Terminating the services of Shri C.D. Chaturvedi, Clerk-cum-Typist, State Bank of India, Main Branch at Ajmer with effect from 6-8-77 on the reason of 'loss of confidence' without conducting domestic enquiry is justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. The workman Shri C. D. Chaturvedi was represented by the State Bank of India Staff Association. The Association filed the claim through the Deputy Secretary of the Rajasthan Region on 29th July, 1980. The Association in the Statement of Claim averred that before joining the State Bank of India at Ajmer Shri C. D. Chaturvedi was in the State Bank of Bikaner and Jaipur. Shri Chaturvedi joined the State Bank of India at Ajmer as a Clerk|Typist on 12th September, 1970 and was confirmed on permanent staff of the bank with effect from 12th March, 1971. His services were terminated on 6th August, 1977 in terms of Para 522(i) of the Sastry Award without assigning any reasons by the Branch Manager, State Bank of India, Ajmer. It has been further stated that Shri Caturvedi had discharged his duties to the entire satisfaction of the superiors. Before joining the State Bank of India, Shri Chaturvedi was working in the State Bank of Bikaner & Jaipur at Lachhamangarh Branch till 7th September, 1970 as Cashier-cum-Clerk. He resigned that bank with effect from 7th September, 1970 for betterment of his career Upto 7th September, 1970 there was no complaint nor any departmental enquiry was pending and the service certificate was issued by that bank. After the termination of his services by the Bank of India, Shri Chaturvedi enquired about the reasons and for the first time he came to know on 19th August, 1977 that an investigation has been made by the CBI for certain acts and omssions during the perod when he was serving the State Bank of Bikaner and Jaipur and on the basis of CBI report, State Bank of India appears to have lost confidence in him. In the Statement of Claim it has been submitted that the action of the respondent bank has caused—grave injury and has cost stigma upon him in-as-much-as the CBI report indcated that Shri Chaturvedi had demanded and accepted illegal gratification from the customers at Lachhmangarh. Such a serious charge should have been made a matter of criminal proceedings or at least a regular domestic enquiry should have been conducted against Shri Chaturvedi. Nothing of this sort was done by the State Bank of India; not even a show-cause-notice was issued to the workman and he was neither shown the contents of the CBI report. In the Statement of claim, which is rather unnecessarily lengthy, the Association has claimed that the order is void and on three grounds among others. Firstly, it was mala fide and victimising, secondly, the order came within the purview of retrenchment as contained in Section 2(oo) of the Act and thirdly it was violative of principles of natural justice.

3. To this Statement of Claim, the respondent bank filed its reply on 22nd October, 1980. In this reply, the bank raised three preliminary objections. Firstly, that Shri C. D. Chaturvedi had not given any authority to the Association to raise this dispute Secondly, the State Bank of Bikaner & Jaipur and the CBI should have been joined as parties and thirdly, that no industrial dispute was involved in the case as the impugned order effected only one worker. On merits it was stated that there were several complaints against three officials of the State Bank of Bikaner & Jaipur at Lachhmangrah and the concerned bank enquired the matter through the CBI. The CBI made a report against all the three officials including Shri Chaturvedi. The State Bank of Bikaner and Jaipur sent a copy of the CBI report to the State Bank of India which did not deem it proper that a departmental enquiry should be conducted against Shri Chaturvedi because the lapses found in the CBI report did not pertain to the period of his service in this bank Had any domestic enquiry been conducted Shri Chaturvedi coulld have raised objection that the State Bank of India has no jurisdiction. But the report did not contain sufficient material on which the bank bona fidely came to the conclusion of lose of confidence in the employee. On account of loss of confidence, the bank was entitled to take section under Paragraph 522(i) of the Sastry Award. It was denied in the reply that such action could not be taken under Paragraph 522(i) of the Sastry Award. For the allegations of victimisation and, malice it was stated that the section of the bank was bona fide and was not taken with a view to victimise Shri Chaturvedi. In the end it was stated that the bank is prepared to furnish details of the evidence of the witnesses to prove the charges against Shri Chaturvedi.

4. The first party i.e. the staff association made an application to give an interim Award in favour of the workman. Notice of that application was given to the respondent, Bank. Both the parties agreed that before taking any oral evidence in the matter, it may be heard on legal points raised in the pleadings and if the case is decided on those points, the question of oral evidence shall not arise. The matter was, therefore, heard taking the documentary evidence as such and hearing the case on law points.

5. Before the arguments could proceed a preliminary objection was raised by Shri S S. Sharma, representative of the bank that the workman should not be allowed to be represented through the advocate as this is against the provisions of the Act when the opposite party has not given the consent. Some arguments were heard on this point but it was felt that since the worker was being represented by the advocate from sometime past, it may be a sort of implied consent. Hence the case was argued by Dr. Chaturvedi, advocate for the workman and Shri S. S; Sharma as representative of the bank.

6. I have duly considered the arguments raised by respective parties. Let us take the preliminary objections first. The first objection is regarding want of authority on behalf of the workman in favour of the Dy. Secretary, S. B:I: Staff Association, but on record such authority is existing. The workman Shri C. D. Chaturvedi has authorised State Bank of India Association to represent his case. This objection, therefore, is not sound. It may be stated here that throughout the hearing, the worker Shri C. D. Chaturvedi was present and was briefing the advocate and he has filed certain docu-

ments also under his signatures and has filled written arguments also. Hence whatever has been pleaded by the Association is in fact pleading by the workman himself. Under section 11(A), the workman whose services have been terminated can represent his case without the medium of Association also. Hence there is no flaw in the representation of the case before the Tribunal. On the second preliminary objection about the non joinder of previous employer of the workman i.e. State Bank of Bikaner and Jaipur and CBI., the learned representative for the bank almost conceded that these are not necessary parties. Obviously since the impugned order was passed by State Bank of India, none else was a necessary party. The third preliminary objection that the case does not involve industrial dispute, as it effects only one worker is also not sound on account of section 2(A) of the Act. Under this section "termination of the services of even an individual workmen shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workma is a party to the dispute. In this manner, all the three preliminary objections fall on the ground.

7. Now we come to other points of the dispue. The learned counsel for the Association argued that action taken by the bank is malafide in as much as they have taken action on the basis of some investigations conducted by another bank. Admittedly, the worker has not committed any misconduct in the State Bank of India. Hence whatever the misconduct it was dehors the employment in the State Bank of India. The past misconduct was absolutely is relevant factor and could not form the basis for any action. In this connection, Dr. R. G. Chaturvedi relied upon some observations made in N. B. Shukla Vs. Bank of Baroda (1979-LLJ-291) and S. B. Palvalkar vs. Bank of India (1980 FLR-55). In Palvarkars case the observations are at page 63 and in Shukla's case these observations are at page 294. In Panvalkar's case, the observations are as under:

"In the matter before me, it has not been the case even of the Bank that it apprehended that the petitioner would or did misuse or abuse the post be held with the Bank (as in the Johnson Pumps case) or that the reason which let to his removal had anything to do with the Bank or his duties as an Officer of the Bank. The Bank may have found it difficult or may not have wanted to hold an enquiry as the acts of the petitioner had nothing to do with the Bank or his duties as an employee of the Bank. That however, would not permit the Bank to cover up such a defect and yet be rid of an unwanted employee by ingeniously passing an innocent-looking order of termination simplicitor in colourable exercise of power." And in Shukla's case, the observations are as under: "Article 522(1) of the Sastry Award provides that in cases not involving disciplinary action for misconduct, the employment of a permanent employee may be terminated by 3 months' notice or on payment of 3 month's pay and allowance in lieu of notice Article 522(1) makes an exception in cases involving disciplinary action for misconduct, for which a separate procedure for enquiry has been provided by Art. 521, which also enumerates the nature of misconduct for which disciplinary action can be taken by the Bank. It comprises of acts and omissions by an employee qua the Bank, in his capacity as an employee of the Bank and in the discharge of his duties as such employee. It is nobody's case, and rightly so, that the alleged misconduct imputed to the petitioner by the enquiry officer pertained to the petitioner's duties as an employee of the Bank. Admittedly the misconduct alleged against him by the enquiry office was qua the affairs of the society and not the Bank. Hence there was no question of the Bank following the separate procedure of enquiry envisages by Art. 521 which provides for the furnishing of a charge-sheet and the matter in which the enquiry is to be conducted." These observations, in my view, do not form the basis of judgment. Ratio decidendi of these cases is the violation of the principles of natural justice. It has not been laid down in these cases, that gross misconduct in earlier appointment or employment can never occasion the loss of confidence in the mind of the latter employee. Suppose a person is convicted for embesslement committed during previous employment, the latter employer can very reasonably lose confidence in the person as such a convict would only bring bad name to the employer and shall be a risk to the institution. The discharge in those circumstances would be legitimate and bonafide exercise of power. How or on what material the loss of confidence has to be concluded is a different matter but in principle, it cannot be said that whatever the misconduct, it cannot be seen by the subsequent employer. Hence, merely because the alleged misconduct related to previous employment, it cannot be said that the action of the subsequent employer State Bank of India was malafide in the sense that it was based on no or irrelevant material. It is not the case of the workman that there was any personal malice against him. In such a situation the argument that impugned termination was malicious and an act of victimisation cannot be sustained.

8. The next point seriously argued by both the parties related to retrenchment. On the one hand, it was argued on behalf of the workman that even discharge in terms of para 522(1) of the Sastri Award is retrenchment, Shri S. S. Sharma, on behalf of the Bank contended that discharge on account of lose of confidence is not retrenchment an there is no question of surplus-age which is the basis of retrenchment. On these points several authorities were cited before me by both the parties. On behalf of the workman, it was argued that concept of retrenchment under went considerable change after the authoritative pronouncement of the Supreme Court in State Bank of India Vs. N. Sundarmuni (AIR 1976 S. C. 1111) followed by Hindusthan Steel Ltd. V|s P.O. Labour Court, Orissa (AIR 1977 S. C. 31). These authorities, he argued were followed in many other cases and even in latest judgment of Supreme Court in Mohanlal V|s Bharat Electronics. (AIR|48|S.C. 1253) The position has been reiterated that termination of workman for whatever reason unless covered by the express exceptions contained in Section 2(oo) is 'retrenchment'. On the other hand, the learned representative of the Bank Shri S. S. Sharma argued that the constitutional bench of the Supreme Court decided that there can be no retrenchment unless the workman is discharged as surplus age. That judgment was delivered by the bench of five judges and could not have been overruled or differred by the smaller benches in the cases of Hindusthan Steel Ltd. and of Sundarmany. He further contended that inspite of the observations in these two cases, the Kerala and Calcutta High Courts have maintained that there could be no retrenchment without the element of surplus age in the impugned order.

9 I have duly considered the rulings referred to by the representative respective counsele. The rule of precedents enjoins upon the subordinate courts to follow the latest rulings of the highest court. In he latest ruling, in Mohanlal's case, all the previous rulings have been duly considered and the position of law has been observed in para 6, 7 and 8 as under:

Section 2(oo) reads as under:—

"2(oo) 'retrenchment' means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include—

(a) voluntary retirment of the workman; or

(b) retirement of the workmen on reaching the age of Superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or

(c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health."

Niceties and mentises apart, termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever would constitute retrenchment except in cases excepted in the section itself. The excepted or excluded cases are where termination is by way of punishment inflicted by way of disciplinary action, voluntary retirement of the workman, retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman con-

cerned, contains a stipulation in that behalf, and termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health. It is not the case of the respondent that the termination in the instant case was a punishment inflicted by way of disciplinary action. If such a position were adopted the termination would be as initio void for violation of principle of natural justice or for not following the procedure prescribed for imposing punishment. It is not even suggested that this was a case of voluntary retirement or retirement on reaching the age of superannuation or absence on account of continued ill-health. The case does not fall under any of the excepted categories. There is thus termination of service for a reason other than the excepted category. It would indisputably be retrenchment within the meaning of the word as defined in the Act. It is not necessary to dilate on the point nor to refer to the earlier decisions of this Court in view of the later two pronouncements of this Court to both of which one of us was a party. A passing reference to the earliest judgment which was the sheet-anchor till the later pronouncements may not be out of place. In Hariprasad Shivshankar Shukla Vs. A. B. Divikar, 1957 S C R 121; (AIR 1957 SC 121) after referring to Pipriach Sugar Mills Ltd. Vs. Piperiach Sugar Mills Mazdoor Union, 1956 SCR 872 (AIR 1957 SC 95) a Constitution Bench of this Court quoted with approval the following passage from the aforementioned case (at page 126 AIR).

"But retrenchment connotes in its ordinary acception that the business itself is being continued but that a portion of the staff or the labour force is discharged as surplusage and the termination of services of all the workmen as a result o the closer of the business cannot therefore be properly described as retrenchment."

This observation was made in the context of the closure of an undertaking and being conscious of this position, the question of the correct interpretation of the definition of the expression 'retrenchment' in Section 2 (00) of the Act was left open. Reverting to that question, the view was reaffirmed but let it be remembered that the two appeals which were heard together in Shukla's case were cases of closure, one Barsi Light Railway Company Ltd., and another Shri Dinesh Mills Ltd., Baroda. With specific reference to these cases, in State Bank of India Vs. N. Sundra Money, (1976) 3 S C R 160; (AIR 1976 S C 1111) Krishna Iyer. J. speaking for a three judges bench, interpreted the expression 'termination ....for any reason whatsoever' as under: (at page 1114 of AIR).

break-down of the Section 2 (00) unmistakably expands the sementics of retrenchment 'Termination ....for any reason whatsoever are the key words. Whatever the reason an every termination spells retrenchment. So, the sole question is-has the employees' service been terminated? Verbal apparel apart, the substance is decisive, A termination takes place where a term expires either by the active step of the master or the running out of the stipulated term. To protect the weak against the strong this policy of comprechensive definition has been effectuated. Termination embraces not merely the sent may be a hard case, but we can visualise abutermination howsoever produced. May be, the present may be a hard case, but we can visualise abuses by employers, by suitable verbal devices, circumventing the armour of section 25-F and Section 2(oo). Without apeculating on possibilities, we may agree that 'retrenchment' in no longer terra incognita but area coverred by an expansive definition. It means, to end, conclude, cease. In the present case the employment ceased, concluded, ended on the expiration of nine days-automatically may be, but cessation all the same. That to write into the order of appointment the date of termination confers no moksha from Section 25-F (b) is infe-

rable from the proviso to Section 25-F (1). True, the section speaks of retrenchment by the employer it is urged that some act of violation by the employer to bring about the termination is essential to attract section 25-F and auomatic extinguishment of service by effluxion of time cannot be sufficient."

It would be advantageous to refer to the facts of that case to appreciate the interpretation placed by this Court on the relevant section. State Bank of India appointed the respondent by an order of appointment which incorporated the two relevant terms relied upon by the bank at the hearing of the case. They were : (1) the appointment is purely a temporary one for a period of 9 days but may be terminated earlier, without assigning any reason therefore at the Bank's discretion; (ii) the employment, unless terminated earlier, will automatically cease at the expiry of the period i.e. 18-11-1972. It is in the context of these facts that the Court held that where the termination was to be automatically effective by a certain date as set out in the order of appointment it would nonetheless be a retrenchment within the meaning of Section 2(00) and in the absence of strict compliance with the requirements of Section 25-F, termination was held to be invalid.

Continuing this line of approach, in Hindusthan Steel Ltd. v. The Presiding Officer, Labour Court Orissa, (1977) 1 SCR 856; (AIR 1977 SC 31), a Bench of three Judges examined the specific contention that the decision in Sundara Money's case, (AIR 1976 SC 1111) runs counter to the construction placed on that section by a Constitution Bench and therefore, the decision is per incurias. This court analysed in detail Shukla's case (AIR 1957 SC 121) and Sundara Money's case (AIR 1976 SC 1111) and ultimately held that the court did not find anything in Shukla's case which is inconsistent with why has been held in Sundara Money's case. In reaching this conclusion it was observed but in Shukla's case the question arose in the context of closure of the whole of the undertaking while in Hindustan Steels case and Sundra Money's case the question was not examined in the context of closure of whole undertaking but individual termination of service of some employees and it was held to constitute retrenchment within the meaning of the expression. This question again cropped up in Santosh Gupta vs. State Bank of Patiala (1980) 3 SCR 340 ; (AIR 1980 SC 1219). Rejecting the contention for reconsideration of Sundara Money's case on the ground that it conflicted with a Constitution Bench decision in Shukla's case and adopting the ratio in Hindusthan Steel's case that there was nothing in the two aforementioned decisions which is inconsistent with each other and taking note of the decision in Delhi Cloth and General Mills Ltd. vs. Shambhu Nath Mukherjee (1978) a SCR 591; (AIR 1978 SC 8) wherein this Court had held that striking off the name of a workman from the rolls by the management was termination of service which was retrenchment within the meaning of Section 2(00) the Court held that discharge of the workman on the ground that she had not passed the test which would enable her to obtain confirmation was retrenchment within the meaning of Section 2(00) and, therefore, the requirements of Section 25-F had to be complied with. It was pointed out that since the decision in Shukla's case, the Parliament stepped in and introduced Section 25-PF and Section 25-PPF by providing that compensation shall be payable to workman in case of transfer or closure of the undertaking, as if the workman had been retrenched. The effect of the amendment was noticed as that every case of termination of service by act of employer even if such termination was as a consequence of transfer of closure of the undertaking was to be treated as 'retrenchment' for the purposes of notice, compensation, etc. The court concluded as under:

"Whatever doubts might have existed before Parliament exacted Ss. 25-FF and 25-PPF about the width of S. 25-F there cannot be any doubt that the expression 'termination of service for any reason whatsoever now covers every kind of termination of service except those not expressly provided in other provisions of the Act such as Sections 25-FF and 25-FFF."

The reading of the above observations leaves no manner of doubt in my mind that the earlier rulings of the Supreme Court in H. S. Shukla and Pipariah Mills have been confined in the later judgments only to cases of closure of an undertaking. Otherwise, the Hon'ble Supreme Court in the later rulings have taken a wider view of the definition of retrenchment. These two earlier rulings were specifically examined in Hindusthan Steel case with a view to see whether Sundara Money's case runs counter to them. It was held that in Shukla's case AIR 1957, Supreme Court 121, the question arose in the context of closure of the whole undertaking. In this manner, the decisions of the Supreme Court from Sundara Money's case onward do not leave any scope to doubt that termination of the services of a worker for whatever reason is retrenchment unless it is covered under the specific exceptions contained in the statutory definition in Section 2(oo). In other words the idea of surplusage which was considered to be the basis for retrenchment was not followed by the Supreme Court in these rulings. If that be so, there can be no doubt that the order of discharge under para 522(1) of the Sastri Award is 'retrenchment' even though it might be based on loss of confidence in the worker by the employer.

10. Learned representative for the Bank Shri Sharma relied upon three cases to show that inspite of the rulings in Hindusthan Steel and Sundara Money surplusage is still the essential ingredient of retrenchment. The first case relied upon him is Narsi Reddy Vs. C.M., A.P.S.R.I.C Musheerabad (1978 Lab. I.C. 1510). In this case the workman was given notice declaring that he is deemed to have resigned his service and consequently ceased to be in service on account of remaining absent for a period exceeding the maximum period for which extra-ordinary leave may be the regulation. In that case the regulation provide that in such a situation the employee shall be deemed to have resigned his appointment and to ceased to be in service. In that case it was held that there can be no retrenchment unless the order of termination is passed by the employer but it cannot be said that in that case the wider interpretation of retrenchment taken in Sundara Money's case was not followed. This is very clear from reading para 9 of the judgment in which it has been laid down that if an employee loses his lien in service in terms of certain regulation then it is not a case of retrenchment. Obviously the facts are entirely different from the present case. The services of Shri Chaturvedi stunt terminated on account of a positive order and deliberation of the employer. The second case relied upon was Dabar Vs. State of West Bengal. In that case more or less a provision similar to Narsi Reddy's case existed. The workman remained absent from duty for about one and half year. The relevant clause of the Standing order provided as under :—

'If the workman remains absent beyond the period of leave originally granted or subsequently extended by the Manager or the Personnel Officer, he shall lose his lien on his appointment unless (a) he returns within 10 days of the expiry of the sanctioned leave and (b) explains to the satisfaction of the Manager or Personnel Officer the reason of his inability to resume his duty just after the expiry of his leave In case the workman loses the lien on his appointment his name shall be kept on the waiting list of the applicants for jobs.'

11. Obviously the ratio of this judgment was not that there can be no retrenchment without the element of surplusage. The ratio of clearly was that if termination is brought about by the operation of some regulation or the standing order, then the case is not of retrenchment. The following observations are quiet relevant :—

'But where on a provision in the standing order as in Cl. 9(3) aforesaid the employee himself brings-in termination of his service by his own default, it cannot be said that it would amount to retrenchment because the employer himself does not effect such termination though it may possess the character of automatic termination as in case of termination by running out of time stipulated in the contract of service. In this view, we are unable to accept the contention of Mr. Ghosh that if we hold that the impugned termination was really one as contemplated by Cl. 9(3) of the standing order as aforesaid as urged by Mr. Ganguly, even then such termination would be invalid for non-fulfilment of the requirements of S. 25 F of the said Act.'

12. The third case relied on behalf of the bank is Kamlesh Kumar Rajani Kant Mehta Vs. Presiding Officer, C.G.I.T. 336. In that case the services of thet employee of the bank were discharged on the ground of loss of faith. The point was raised that it is a case of retrenchment and the order was had because retrenchment compensation was not given. The case law was discussed including the Supreme Court cases and the learned Judge summarised his conclusions as under:—

"We summarise that the criterion or retrenchment is superfluity or surplusage of labour or staff in a running business caused by any reason whatsoever such as, economy, rationalisation in industry, installation of new labour saving machinery or devices standardisation or improvement of plant or technique and the like. Surplusage or superfluity is the fulcrum round which the concept of retrenchment must turn. In a line, if there is no superfluity, there can be no retrenchment."

13. These observation of course go to support the contention of the bank that when services are terminated on the ground of loss of faith, the question of retrenchment of the worker does not arise. However, in my view these observations run counter to the latest judgment of the Supreme Court in Mohanlal Vs. Bharat Electronics (1981 Lab. I.C. 806) referred to earlier. That was a case of termination of the services of a temporary workman for unsatisfactory work. The Hon'ble Supreme Court held that it is a case of retrenchment. It may here be noted that Shri Chaturvedi, workman in this case, was holding a permanent post since 12th March, 1971. His services were terminated on 6th August, 1977. If services of even a temporary worker cannot be terminated without retrenchment benefits except in case of express excluded category, there is no reason to hold the view that discharge under Rule 522(i) of the Sastry Award on the ground of loss of faith should not be treated as a case of retrenchment. Relevant portion of this paragraph is as under :—

"In cases not involving disciplinary action for misconduct and subject to clause (6) below, the employment of a ptrmanent employee may be terminated by three months' notice or on payment of three months' pay and allowance in lieu of notice."

14. A bare reading of this Paragraph shows that services under this clause cannot be terminated unless positive decision is taken by the management on certain facts. In other words without positive decision and order on the part of the management action cannot be taken under this paragraph. In the written arguments it has been contended on behalf of the bank that the situation has been brought about by the worker himself and therefore it cannot be said that termination of the services have been brought by an act of the management. The effect seemingly was to bring the case within the ambit of Narsi Reddy's case and Babur's case discussed earlier, but in these two cases the Regulation Standing Order itself provided for deemed designation and loss of lieu on account of long absence. The Regulation and the Standing Order concerned came into operation automatically as soon as employees remained on long absence. Here the case is entirely different. The conclusion of loss of confidence was arrived it on reading the C.B.I. report dated 31st July, 1973. It cannot, therefore, be said that the termination of services of Shri Chaturvedi was not a result of positive act on the part of the management. Hence as noted earlier, the above two rulings in which the later Supreme Court cases were differentiated do not apply to actions under Paragraph 522(i) of the Sastry Award.

15. In the written arguments a reference has been made this connection to the following rulings :—

(1) 966-II LLJ. 59

(2) 1961-I LLJ. 167

(3) 19[illegible] LLJ. 563

16. These are the cases decided much earlier than Sundermony's case and in my view after that case these decisions have lot much of their authoritative value and they cannot be treated to be valid presedents on the question of retrenchment. In written arguments it has been stressed and in the oral arguments also it was so stressed that Pipraich Mills and Barsi Light Railway case reported in 1957-I LLJ. 235 and 243 still held the field. In my view the latest judgment of the Supreme Court have limited the effect of those rulings only to the cases of closure. On the point of retrenchment, as such the position of law summarised in Mohanlal's case has to be accepted. In the written arguments reference has been made to two more cases on this point. They are (1) 1972-Lab. I.C. 5675 and 1972 Lab. I.C. 1962. I have gone through both these rulings. In 1972 Lab. I.C. 668 the question of retrenchment did not arise at all. In that case the simple question was whether the termination of the services under Regulation 48 of the Air India Service Regulations on the ground of loss of confidence involved termination on misconduct. The Court held that it does not involve misconduct as such and Sections 33 and 33A of the Act are not attracted. In 1972-Lab. I.C. 1262 the question arose whether the employer can terminate the services on the ground of loss of faith and whether such termination can be termed as dismissal so as to attract the jurisdiction of the Tribunal. In that case the question of retrenchment in such a situation was neither raised nor decided. There can be no doubt that the employer can terminate the services of an employee if they bonafidely came to the conclusion of loss of confidence but the question is whether in such a situation provisions regarding retrenchment are attracted or not. These 1972 rulings do not shed any light on the precise point of retrenchment and cannot be taken help of in favour of the Bank.

17. After anxious consideration of the case law on the point, I am of the view that even an order passed under Paragraph 522(i) of the Sastry Award is an order of retrenchment. If that be so, there is no scope for not quashing the impugned order, as admittedly retrenchment benefits have not been given, it is settled law that if the order is invalid from the very beginning, it has to be quashed in its entirely and the workman has to be reinstated with back wages. This position is borne out from a number of authorities. Apart from Sundara Money's case, there is an authority of the Supreme Court in S.K. Verma Vs. Industrial Tribunal [1980 (41) FLR 351].

18. Now we come to the third point viz. whether the principles of natural justice have been violated in this case. The worker has contended that even when the services were terminated on the basis of loss of confidence, the termination cannot be ordered without giving hearing to the concerned worker. On the other hand the management has contended that in cases of loss of confidence no domestic enquiry can be held and no hearing whatsoever is required before action is taken against the workman. However, no authority on this precise point was cited on behalf of the management. The only case cited before me was of K. R. Mehta Vs. Presiding Officer, C.G.I.T. (1980-I LLJ. 337). That case was certainly the case of loss of confidence and is quite relevant. In that case the customer removed .650 bales of cotton from the Godown of the Bank while they had deposited such lesser amount. Shri Mehta who was incharge of the godown was discharged from service wihout holding any domestic enquiry. However, from the narration of facts in para 3 of the judgment it is clear that the petitioner was called upon to give his explanation how delivery of 650 bales had beer given by the petitioner to the Association. He did give his explanation in which he admitted the delivery of the 650 bales but he stated that tht delivery was taken when he was attending the office. He further stated that he had informed the Association to take delivery only after taking prior permission of the bank. The worker in that case expressed regret also. From the above narration of the facts it is clear that principles of natural justice were followed in that case in-asmuch-as the authorities took explanation or unauhorised removal of the bales. The worker more or less admitted the whole facts. The bank instead of punishing the employee for misconduct simply discharged his services. In that case the only question involved was whether such discharge of the worker was retrenchment or not. The violation of the principles of natural justice was not a question raised or decided in that case. Obviously because those principles were followed in taking explanation of the employee.

19. On the other hand there are two cases of the Bombay High Court which show on what material and in what manner the loss of confidence has to be concluded and whether the principles of natural justice apply in such cases. The first case is N.B: Shukla Vs. Bank of Baroda and another (1979-I LLJ 291). In that case the employee Shri Shukla was discharged by giving him three months notice. The allegation against him was that he had cheated or misconducted as a member of the Managing Committee of Bank of Baroda Employees Cooperative Housing Society. The matter was enquired into by the Registrar of Cooperative Societies through an Advocate who submitted an adverse report against Shri Shukla. The bank addressed a letter to Shri Shukla setting out the findings of the Enquiry Officer and called upon the petitioner to submit his written explanation. In the writ filed by Shri Shukla, a point was raised whether principles of natural justice were followed or not. In that case it was held that preliminary report could not be the basis of termination of the services of Shri Joshi. The report by the Enquiry Officer who was an Advocate was not held to be an enquiry by quasi judicial authority. The present case is certainly much weaker. In this case the report was by the C.B.I. and no explanation whatsoever was ever sought from the employee.

20. The next case is of S. V. Panvalkar Vs Bank of India [1980 F.I.R.(41)55] is also similar. In that case also employee Panvalkar was the chief promoter of a Cooperative Housing Society. Against him also an enquiry was instituted by the Registrar, Cooperative Societies. The Enquiry Officer Shri Godbole made an adverse report against Shri Panvalkar. The bank addressed a letter to Shri Panvalkar and explanation was obtained. The bank after finding the explanation to be unsatisfactory terminated his services. In the writ petition by the worker the bank raised the plea of loss of confidence stating that on the basis of Shri Godbole's report the bank bona fidely formed the opinion of loss of faith. His Lordship dealing with the point observed as under :—

> "Mr. Vahanvati urged that once it is held that loss of confidence is bona fide, the order is immune from challenge even if the opinion is erroneous. It is one thing to form a bona fide opinion, be it erroneous. It is altogether a different thing to remove by a seemingly innocuous order of termination an unwanted employee by claiming bona fides. In this case, bona fides could have been established by the Bank by simply telling the petitioner; "We have received Godbole's report, prima facie we are impressed by it, show cause why your services should not be terminated. Instead of doing so, the Bank chose to act ex-parte on the basis of that report and decided to get rid of the petitioner willy—nilly under the guise of a seemingly innocuous order of termination affecting loss of confidence. Mr. Vahanvati's contention that even if an enquiry had been held against the petitioner, the same would have served no useful purpose in view of Godbole's order, merely indicates that the Bank had decided to be rid of the petitioner. If the Bank had already made up its mind to do so on the basis of Godbole's report, Mr. Vahanvati is right that inviting the petitioner's explanation would have been an idle formality. Surely not exactly a convincing glimpse of bona fides on the part of the Bank as Mr. Vahanvati seeks to make out. Mr. Vahanvati urged that the petitioner had taken a loan from the Bank for purchasing a flat, that the petitioner had also sanctioned loans to other employees for purchasing flats and hence, even in his dealings with the Bank. The Bank had lost confidence in the petitioner. There is nothing to commend this contention except the ingenuity with which it has been advanced. No such ground has even been made out by the Bank in its letter dated 7th Decem-

ber 1971, in which the only ground given for the purported loss of confidence is the petitioner's dealings with the affairs of the Society and nothing else. The loss of confidence affected by the Bank had nothing to do with the petitioner's dealing with the Bank but only his dealings with the Society."

21. It is very clear that the present case is very much weaker for the bank in-as-much-as in Panvalkar's case Godbole was exercising statutory authority under Section 58 of the Cooperative Societies Act and "about this report" the explanation of the employee was sought. Here the C.B.I. report stands interior to Godbole's report and no explanation whatsoever was sought by the bank from the worker. In my view, therefore the impugned order terminating the services of the petitioner has been passed in violation of the principles of natural justice.

22. During the course of oral arguments the bank had not raised the plea that they are prepared to submit evidence before the Tribunal to support the case of loss of confidence but in the written arguments they have stated their preparedness for producing the evidence. In my view as the order is void and illegal on the point of retrenchment, the question of opportunity of producing oral evidence does not arise. Secondly it is doubtful whether in cases of loss of confidence the Tribunal should allow the employer to produce evidence in the Court as if it is a case of misconduct. The request of the bank for production of oral evidence cannot, therefore, be allowed.

23. After considering all the facts and circumstances of the case I am of the view that the order of termination must be quashed and the worker be reinstated in service with all back wages.

24. I, therefore, pass the following award :—

"The order of the bank dated 6th August, 1977 terminating the services of Shri C. D. Chaturvedi is quashed. Shri Chaturvedi is ordered to be reinstated in service with full back wages and other service benefits, as if the impugned order had never been passed.

25. I pass an award accordingly. It may be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.

[No. L-12012/58/79-D.II(A)]

RAM RAJ LAL GUPTA, Presiding Officer

S.O. 2489.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on the 29th August, 1981.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-6 of 1980

Reference :

Government of India, Ministry of Lubour, New Delhi order No. L. 12012/87/79/D.II.A Dated 6-11-80.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Smt. Kamla Bai (Ex-part time Sweepress, Kota) through P. K. Mazdoor Sangh, Kota.

AND

Regional Manager, Punjab National Bank, Jaipur.

APPEARANCES :

For the Union—None

For the Management—Shri P. D. Dube, P. Officer

Date of Award : 9th June, 1981.

AWARD

The following dispute was referred to by the Government of India vide order dated 6-11-80 issued by Desk Officer, Ministry of Labour for adjudication :—

"Whether the action of the Management of the Punjab National Bank in relation to Rampura Bazar Branch, Kota in stopping from employment, Smt. Kamalabai wife of Shri Ramswaroop, a parttime Sweeperess with effect from 1-9-78, is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. That notices were sent twice to Smt. Kamla on the address given on the order of reference but they returned as refused. Then a further notice was sent to the Conciliation Officer but no appearance was made on behalf of the Union. Non-appearance of the Union goes to show lack of interest in the matter. A No Dispute Award is therefore, passed.

3. Let this Award be sent to Government of India for publication under Section 17(1) of the I.D. Act, 1947.

[No. L. 12012(87)/79-D.II(A)]

RAM RAJ LAL GUPTA, Presiding Officer.

S.O. 2490.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on the 29th August, 1981.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

PRESIDED BY : SHRI RAM RAJ LAL GUPTA PRESIDING OFFICER.

Case No. CIT-2 of 1981.

Reference :

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi order No. L-12012/74/79-D.II.A Dated 9th January, 1981.

In the matter of an Industrial Dispute.

BETWEEN

General Secretary, Rajasthan Bank Employees Unlon, Provincial Office, Madho Bangh, Jodhpur.

AND

General Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur Head office SMS Highway, Jaipur.

APPEARANCES :

For the Union : Shri Ram Lal Khandelwal
For the Management : None
Date of Award : 20-6-81.

AWARD

The following dispute was referred to this Tribunal by the Central Government through the Desk Officer, Ministry of Labour, New Delhi vide order dated the 9th January, 1981:—

'Whether the action of the Management of State Bank of Bikaner and Jalpur in terminating the services of Shri Gauri Shankar Vyas, Clerk with effect from 30-12-72 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?'

2. On 20th June. 1981 Shri R. L. Khandelwal appeared on behalf of the union. He stated that the concerned Bank has settled the matter with the worker and it has been agreed that the workman shall be taken on job. Certain other conditions have also been settled out of Court. He filed a written application to that effect in which it was prayed that the case may be closed. Under the circumstances a No Dispute award is passed as prayed by the union.

3. Let this Award be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the I.D. Act. 1947.

[No. L-12012(74)/79-D.II(A)]

RAM RAJ LAL GUPTA, Presiding Officer

New Delhi, the 4th September, 1981

S.O. 2491.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Cantonment Board, Shillong and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th August, 1981.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 5 of 1981

PARTIES:

Employers in relation to the Cantonment Board, Shillong

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. A. K. Baratlam. Executive Officer, Cantonment Board.

On behalf of Workmen—Mr. S. K. Sanyal, Assistant Secretary of the Union.

STATE: Meghalaya. INDUSTRY: Cantonment.

AWARD

This is a reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 on the basis of an order of the Government of India, No. L-13012(3)/80-D.II(B) dated 6th January, 1981 for adjudication of an industrial dispute between the employers in relation to the Cantonment Board, Shillong, hereinafter referred to as the "Board" and their workmen represented by the General Secretary, Shillong Cantonment Employees Union, Shillong, Meghalaya, hereinafter referred to as the "Union", The dispute has been mentioned in the schedule to the order of reference in the following terms:

> "Whether the action of the Executive Officer, Cantonment Board, Shillong, in dismissing Shri Inder Singh, Sanitary Jamadar, from service with effect from 22nd November, 1979 is justified and legal? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the Union, to be short, is that the concerned workman Inder Singh was appointed originally as a Sweeper under the Board in 1957 and ultimately he was promoted to the post of Sanitary Jamadar in October, 1970. The workman concerned is a "workman" according to the definition under Section 2(s) of the Indusrtial Disputes Act. The Union is registered under Trade Unions Act, 1926 and works for the benefit of the workmen of the Board. Inder Singh was the General Secretary of the Union and the Executive Officer of the Board is vindictive against the Union and he had particular grudge against Inder Singh as he had activities for the Union. Without any just reason Inder Singh was placed under suspension and chargesheet was served upon him. The recognition of the Union was withdrawn by the Board authority vindictively. The charges are false, vague and without any basis. Inder Singh submitted his reply to the chargesheet and demanded enquiry if the proceeding was not withdrawn. The Board without giving him opportunity for self-defence and without holding any enquiry dismissed him from service without assigning any ground for his dismissal. There was no enquiry before the order of dismissal. Inder Singh was not given any opportunity to place his case and the order of dismissal was against Cantonment Fund Servants Rules and the principles of natural justice. It has been alleged by the Union that the order of dismissal was mala fide and unjust. The prayer of the Union is that the concerned workman may be reinstated in service with all benefits and arrears of pay and allowance.

3. The Board in its written statement has stated that the allegation about the vindictiveness made by the Union is false. This is not a case of victimisation. Petitioner's explanation to the charge was considered by the Board and thereafter it resolved to dismiss Inder Singh in view of the reasons given in the chargesheet. It has been stated by the Board that as the concerned workman belonged to the lower grade employee of the Board an elaborate enquiry was not required. It has been further stated that no enquiry under rule 12 of the Cantonment Fund Servants Rules is required in case of lower grade servants of the Board. Inder Singh was dismissed after giving him due opportunity to defend himself. The Board decided to dismiss the workman after due consideration of the charges and the reply thereto submitted by the delinquent.

4. On the date of peremptory hearing Mr. S. K. Sanyal, Assistant Secretary of the Union represented the workmen while Mr. A. K. Baratlam, the Cantonment Executive Officer appeared on behalf of the Board. On the side of the workmen the concerned workman was examined and Mr. Baratlam submitted that the Board would not adduce any oral evidence. In this case several documents were exhibited on both the sides, the formal proof whereof was dispensed with by the parties.

5. The contention of Mr. Sanyal is that in this case there was no enquiry regarding the charges framed against the workman and that the delinquent did not get any opportunity whatsoever to defend himself. It has been argued that this is a case of malice and victimisation particularly against Inder Singh who was the General Secretary of the Union for his union activities. Mr. Sanyal has particularly stressed upon the fact that although the delinquent in reply to the charge-sheet demanded an enquiry and wanted all opportunities to defend himself, the Board deliberately and vindictively refused such opportunities to Inder Singh against the rules framed under the Cantonment Act, 1924. He relied upon Cantonment Fund Servants Rules, 1937, briefly referred to hereafter as "CFSR". It has been urged by Mr. Sanyal for the Union that in the present case there is no evidence whatsoever or material to prove any of the charges levelled against the workman.

6. Mr. Baratlam, the Executive Officer of the Board has argued that in the present case the workman being a lower grade servant the Board was not required to hold any enquiry and even if an enquiry was needed it need not be elaborate and the Board in the present case held some enquiry, of course, behind the back of the delinquent and without his knowledge. On the basis of the enquiry the Board found the charges proved and dismissed Inder Singh from service. According to Mr. Baratlam there was no occasion for interference with the order of dismissal in this case.

7. The chargesheet, Ext. W-1 dated 7-9-79 is a letter written to Inder Singh by the Executive Officer of the Board informing him that the Board proposed to take action against him under Rule 12 of the CFSR. Along with the letter a chargesheet was enclosed and the statement of allegations in respect of the charges was also attached. By the letter Inder Singh was required to put in a written statement and to state whether he desired to be heard in person, to furnish the names and addressses of his witnesses and to furnish a list of such documents as he liked. The charges have been enumerated as follows:

"CHARGES

The following are the charges against Shri Inder Singh, Sanitary Jamadar of the Cantonment Board, Shillong based on the statement of allegations attached herewith:

1. That Shri Inder Singh, Sanitary Jamadar while serving in the aforesaid office is guilty of gross misconduct and wilful insubordination.

2. That Shri Inder Singh while working in the aforesaid office was guilty of disobedience and deliberate insubordination.

3. That Shri Inder Singh while serving in aforesaid office was guilty of gross violation of discipline.

4. That Shri Inder Singh while working in the aforesaid office was guilty of gross misuse of his official position.

5. That Shri Inder Singh, Sanitary Jamadar while functioning in the aforesaid office was guilty of instigation of the faithful and loyal staff to go on illegal strike.

6. That Shri Inder Singh, Sanitary Jamadar while working in the aforesaid office is guilty of wilful insubordination and conduct subversive of discipline.

7. That the past record of Shri Inder Singh is far from satisfactory.

Sd/- Illegible,
CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER,
SHILLONG.

8. Along with the above letter a list of witnesses connected with the charges and the documents was also supplied to the delinquent but without the copies of the documents. A large number of documents have been mentioned. There is no dispute that a reply to the chargesheet was given by the delinquent and that has been marked as Ext. W-2.. For all practical purposes the delinquent in his explanation wanted to say that the charges brought against him were denied and not maintainable and not lawful, I have gone through the explanation and I find no statement which will amount to admission of guilt in respect of any of the charges. At page 5 of the explanation in paragraph 5 it has been stated that if the Board decided to proceed with the disciplinary proceedings the delinquent may kindly be informed by official letter about the appointment of an Enquiry Officer and Enquiry Committee and the same was necessary under the Rules of natural justice and on the principles of reasonable opportunity. It has been further alleged in the explanation that if the Board decides to proceed with the disciplinary proceedings the deliquent should be allowed to take the help of a person other than a lawyer who will represent his case before the Enquiry Officer/Enquiry Committee. The delinquent has categorically stated in his explanation that he desires for his self-defence according to the rules. Lastly it is stated that on being informed about the enquiry he would furnish the list of witnesses and document for defence. It has been admitted, as I have already indicated, that there was no enquiry in which the deliquent was given any opportunity for self-defence. There is no evidence that the dequiquent was informed about any sort of enquiry- In the written statement filed by the Board there is no indication whatsoever that there was any sort of enquiry either within the knowledge of the deliquent or behind his black. Mr. Baratlam has referred me to Ext. W-3, the letter of dismissal which reads as follows :

> "You are hereby dismissed from service w.e.f. 22nd November 1979 as decided by the Board vide C.B.R. No. 13 dated 13th November, 1979."

At the bottom of the letter the copy of Cantonment Board Resolution No. 13 dated 13-11-79 has been quoted. The agenda of the Board's resolution No. 13 says that with reference to CBR No. 5 dated 5-11-79 it was to consider the written statement of defence dated 6-10-79 submitted by Inder Singh, Sanitary Jamadar against the chargesheet and in this connection all relevant papers were put up on the table. Regarding Resolution No. 13 it is stated that the Board considered the statement of defence dated 6-10 at length and resolved that Shri Inder Singh be dismissed from service forthwith. In this exhibit W-3 there is reference to the explanation to the chargesheet and in the resolution it is stated that the statement of defence, namely the explanation was considered and the decision for dismissal was taken. There is no indication whatsoever in this letter of dismissal or in the resolution or even in the agenda mentioned there that any enquiry or its result was considered. Mr. Baratlam has drawn my attention to Ext. M-3, a resolution dated 19-3-79, long before the date of dismissal. In this exhibit there is reference to the agenda of the meeting of the Board which says that with reference to C.B.R. No. 13 dated 14-12-78 it was to consider the report of the Enquiry Committee held on 29th February, 1979 and in that connection the relevant papers along with the files were put up on the table. In the resolution dated 19-3-79 it was stated that Inder Singh, Sanitary Jamadar be chargesheet and the Contonment Execute Officer is authorised to issue chargesheet.

9. Now, the report of the Enquiry Committee referred to in the agenda as mentioned in Ext.M-3, if there be any, must be a preliminary report prepared behind the back of the delinquent for the purpose of issuing chargesheet and this enquiry was not held for the purpose of decision as to the allegations made in the chargeshcet. Clearly, therefore, there was no enquiry made by the Enquiry Committee or otherwise in respect of the charges framed and that is why in the written statement there is no indication that any enquiry was held in respect of the charges levelled against the delinquent. In view of the papers brought as exhibit before this Tribunal, it must be held that there was no enquiry whatsoever regarding the charges framed against the delinquent and that the Board did not give any opportunity to the delinquent to be heard in his self-defence regarding the charges. On the other hand, the Board without assigning any reason and without considering any evidence of examining any witness relating to the charges decided to dismiss the workma. In the resolution there is no ground indicated for dismissal. There is no indication that the Board was satisfied on any material coming from the side of the Board that the charges were proved. It appears that the Board considering the explanation of the delinquent alone and came to its finding. In the circumstances it most be held that the finding was without any basis. The delinquent himself gave evidence before this Tribunal regarding the charges. He has asserted that he is not guilty of any of the charges. He has stated that he did not get any opportunity of self-defence. In spite of the evidence the Board did not adduce any evidence to substantive any of the charges. On the other hand, Mr. Baratlam submitted before the Tribunal that the Board would not adduce any oral evidence regarding the merit of the case. Clearly, therefore, before this Tribunal also there is no evidence in support of any of the charges. None of the charges have been proved and there is no material for finding of guilt of the delinquent regarding the charges. In view of this finding of the Tirbunal and in the facts and circumstances it must be held that there was no ground for dismissal of Inder Singh or for any punishment whatsoever. The way in which the order of dismissal was passed by the Board does not appear to be reasonable or just. It may be stated that the charge No. 7 can not be a subject matter of any charge of misconduct.

10. In this connection, I should refer to the submissions made by the parties with regard to the position of law appearing in CFS Rules. According to the Board no enquiry was necessary because the delinquent was a lower grade servant. Rule 12 says that no order of dismissal, removal or reduction shall be passed on a servant unless he has been informed in writing of grounds on which it is proposed to take action and has been afforded an adequate opportunity of defending himself. As I have already stated, in the present case Inder Singh was not given any opportunity whatsoever for his defence although he demanded the same in reply to the chargesheet. In Rule 12 it is also stated that the delinquent is to state whether he desires to be heard in person and if he so desires an oral enquiry shall be held. In the present case there was the demand for enquiry but the Board refrained from holding an enquiry without any reason. My attention has been drawn by Mr. Baratlam to Rule 12A which, according to him, says that in case of lower grade servants elaborate enquiry need not be made. I have read it and read it more than once. It says that in case of a lower grade servant an equally celebrate inquiry need not be made but there shall be delivered to him personally or by registered post a copy of the document showing the ground or grounds on which his reduction, removal or dismissal was ordered. In this connection the first question that arises is whether Inder Singh is a lower grade servant. Now, the words "lower grade servant" has been defined in Rule 2(d) according to which the said words mean daftri, peon, bheasti, mali, lamplighter, chowkidar, coolie or sweeper or any other class of servant declared by the Central Government to be a lower grade servant for the purpose of these rules. The 'sweeper' has been defined in Rule 2(g) to mean any person who is actually employed in collecting or removing or disposing of fifth or rubbish, in cleansing roads, drains or, slaughter houses or in driving carts used for the removal of filth or rubbish. It is admitted from the side of the Board that Inder Singh is not a sweeper as defined. In fact he is Sanitary Jamadar and Mr. Baratlam has admitted that he is not actually employed in collecting and/or depositing of filth, etc. as defined but his duty is to supervise the works of sweepers. Mr. Baratlam however submitted that although Inder Singh was not a sweeper but as he was a class IV employee the Board did not think it necessary to hold an enquiry. There is nothing before me which may suggest that Central Government declared a Sanitary Jamadar as a lower grade servant. Simply because he was a class IV employee it cannot be inferred that he was a lower grade

servant. Of course Mr. Sanyal disputes the contention that Inder Singh was a class IV employee because according to him Inder Singh being a supervisor of sweepers had to record attendance and to do several clerical jobs and in this way he was a class III employee. However, we are not concerned with that contention at present. This much is clear that there is no evidence that Inder Singh was a lower grade servant and, therefore, an enquiry was essential before he is found guilty of the charges. Even in case of a lower grade servant some sort of enquiry should be held giving opportunity to the delinquent for his self-defence. This principle is based upon natural justice. That principle has not been adopted in the present case. The Board has not even produced any evidence of misconduct in support of the chargesheet before this Tribunal. In the order of dismissal no ground for dismissal was given.

11. In view of my findings and discussions above, I must, therefore, hold that the order of dismissal and the order of suspension passed against te workman Inder Singh are illegal and grossly unjustified and the said orders are declared ineffective and inoperative. In consequence Inder Singh should be deemed to be in service and shall be entitled to get all consequential reliefs including arrears of pay and allowances, etc.

This is my award.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer

Dated,
Camp : GAUHATI,
The 24th August, 1981.

[No. 13012(3)/80-D.II(B)]
S. S. BHALLA, Desk Officer

S.O. 2492.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Jharia Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st August, 1981.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 16/79

PARTIES :

Employers in relation to the management of South Jharia Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jharia, Dist. Dhanbad

Vs.

Their workman.

APPEARANCES :

For Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For Workmen—Shri B. Bose, Secretary, R.C.M.S.

INDUSTRY :Coal. STATE : Bihar
Dated, the 24th August, 1981

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) have forwarded the above-mentioned dispute to this Tribunal by Order No. L-20012/53/79-D.III(A) dated the 27th October, 1979, for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of South, Jharia Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P. O. Jharia, Dist. Dhanbad that the date of appointment of Shri Harbans Tewary, Mining Sirdar should be taken as 9th May, 1963 instead of 9th April, 1972, is justified? If so, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The case of the workman is that he was serving in Ganhoodih Colliery as Mining Sordar with effect from 9-5-63 and was subsequently transferred by the present management to South Jharia Colliery in the month of May '72. It is stated that he is holding Sirdarship Certificate issued by the Department of Mines on 21-4-61 and since then he has been working as Mining Sirdar and his employment in Ganhoodih Colliery was made with effect from 9-5-63 and continued to work there as such till he was transferred to the present place of posting. It is further submitted that he is a member of Coal Mines Provident Fund since 1964, but it is not known whether his service record was sent to his new place of posting at the time of his transfer. It is alleged that the colliery management recorded a wrong date of appointment which came to the knowledge of thte workman as late as in 1978 when he took up the matter through the union which resulted in the present reference.

3. It is submitted that the date of his appointment should be taken as 9-5-63 instead of 9-4-72 and he may be given consequential relief.

The case of the management is that the present reference is not maintainable. It is however submitted that the management of Ganhoodih Colliery was taken over with effect from 17-10-71 by the Custodian and it was nationalised subsequently with effect from 1-5-72. The case of the management however is that the present workman was not in employment when the management of this colliery was taken over and he was taken in employment as 'Badli' Mining Sirdar in persuance of a bilateral discussion held between the union and the management on 7-4-72 and the workman was posted in South Jharia Colliery in May 72 and since he joined as a 'badli' Mining Sirdar on 9-4-72 his date of appointment was recorded as such i.e. 9-4-72. It is submitted that as the workman concerned was not in employment on the date of take over of the colliery, hence his date of appointment will be the date on which he joined the Ganhoodih Colliery as a badli Mining Sirdar. They also submitted that before the Conciliation Officer the present workman gave different dates regarding his appointment. It is also submitted that as there is no evidence to show that the concerned workman was in continuous employment in Ganhoodih Colliery and as he was not on the rolls of the said colliery on the date of take over, question of changing the date of his appointment does not arise. It is submitted that the present reference be decided in favour of the management.

5. The point for consideration is as to whether the date of appointment of the concerned workman should be taken as 9-5-63 instead of 9-4-72. If so, to what relief he is entitled to.

6. In support of his case the concerned workman has examined himself as the sole witness while he has filed two documents Exts. W-1 and W-2. Ext. W. 1 is a letter of appointment dated 9-5-63 appointing the concerned workman as Mining Sirdar in Ganhoodih Colliery. Ext. W-2 is an office Order of the present management dated 22-5-72 transferring the concerned workman to Rajpur Colliery. These two documents however do not indicate that the concerned workman was in continuous service of the Ganhoodih Colliery till the colliery was taken over by the Government. No document has been filed to show that the concerned workman was on the rolls of the Ganhoodih Colliery on the date of take over. The workman himself has also not stated in his evidence that he was in continuous service from 1963 and that he was on the rolls of the said colliery on the date of take over. The concerned workman caugth to have filed relevant documents to show that he was on the rolls of the Ganhoodih colliery when it was taken over by the Government.

7. As against this the management has filed the abstract of the Identity Card Register of South Jharia Colliery regarding the concerned workman. It shows his date of birth as 5-4-72 that is the date of his transfer. Ext. M-2 is a letter dated 16-11-78 issued by the Personnel Manager, Area No. 9 which also shows that the date of appointment is 5-4-72 that is the date on which he was taken in the said colliery. The concerned workman put his signature on the register of Identity Card which shows that he accepted the date of appointment as 5-4-72. If there was any mistake in mentioning the date of his appointment he should have raised ob-

jection then and there, but no objection was raised by him till the year 1978 and he kept quiet for all these years. The record of the Provident Fund or any other document has not been filed on behalf of the workman to prove his case. Onus lay on the concerned workman to prove that he was in continuous service in the previous colliery till it was taken over by the present management. But this onus has not been discharged. The appointment letter Ext. W-1 simply shows that he was appointed on 9-5-63. But it does ont show that he continued in service till the date of take over. It may just be possible that he might have left his service and came as as Badli Mining Sirdar when required by the management.

8. Considering the evidenre and circumstances of the case, I hold that the question of changing the date of appointment of the concerned workman does not arise and his demand is not justified. Consequently he is also not entitled to any relief.

9. The award is passed accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012(53)/79-D.III(A)]
A. V. S. SARMA Desk Officer.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1981

का० आ० 2493.— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 935, दिनांक 25 मार्च, 1980 के अनुक्रम में, भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1980 से 30 जून, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिये छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणीय, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिये रखे गये थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गये उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा:—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अभियोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रधारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दें या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाये, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

[संख्या एस-38014/10/80-एच० आई०]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने के किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

New Delhi, the 8th September, 1981

S.O. 2493.—In exercise of the powers conferred by section 87, read with section 91A, of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 935 dated the 25th March, 1980, the Central Government hereby exempts the Bharat Heavy Plate and Vessels Limited, Visakhapatnam from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st July, 1980 upto and inclusive of the 30th June, 1981.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of,—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said Act for the period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period

when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider neccssary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in-charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such acounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/10/80-HI]
N. B. CHAWLA, Deputy Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 2494.— नागालैण्ड राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में एन० जखालु के स्थान पर श्री आर० इज़ुंग, श्रम सचिव, नागालैण्ड सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद्द 20 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"श्री आर० इज़ुंग,
श्रम सचिव,
नागालैण्ड सरकार,
कोहिमा ।"

[संख्या यू-16012/14/81 एच० आई०]

S.O. 2494.—Whereas the State Government of Nagaland has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri R. Ezung, Labour Secretary, Government of Nagaland to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri N. Jakhalu ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 850 (E), dated the 21st October, 1980, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 20, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri R. Ezung,
Labour Secretary,
Government of Nagaland,
KOHIMA.

[No. U-16012/14/81-H. I.]

का० आ० 2495.— आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ), के अनुसरण में श्री जी० आर० नायर के स्थान पर श्री एम० चन्द्र मौलि रेड्डी सचिव श्रम रोजगार पोषण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद्द 8 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"श्री एम० चन्द्र मौली रेड्डी, सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार पोषण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हैदराबाद ।

[संख्या यू-16012/19/81-एच० आई०]
एन० बी० चावला, उप सचिव

S.O. 2495.—Whereas the State Government of Andhra Pradesh has, in pursuance of clause (d) of sectioin 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri M. Chandra Mouli Reddy, Secretary, Labour Employment, Nutrition and Technical Education Department to represent that state on the Employees'State Iinsurance Corporation in place of Shri G. R. Nair;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employes' State Insurance Act, 1948(34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)', for the entry against item 8, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri M. Chandra Mouli, Reddy, Secretary to the Govt. of Andhra Pradesh, Labour Employment, Nutrition and Technical Education Department, HYDERABAD."

[No. U-16012/19/81-HI]
N. B. CHAWLA, Deputy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981